राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 218

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 15 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

पैड को खाद में बदल देगा ईकोफ्रेंडली 'मेन्सयू बर्नर'

पठानकोट : पंजाब के पठानकोट जिले की दसवीं कक्षा की दो छात्राओं कृतिका और हर्षिता ने अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में 'मेन्सयू बर्नर' नामक उपकरण बनाया है, जो इस्तेमाल हो चुके सेनेटरी पैड का समुचित निस्तारण करता है। (पेज-11)

जागरण विशेष

'दुर्गा' के अवतार में एसडीएम शिवानी, माफिया बेहाल

गुना : मध्य प्रदेश के गुना जिले में युवा एसडीएम शिवानी गर्ग के नाम से माफिया को ठंड में पसीने छूट रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ शिवानी ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' व अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 'एंटी माफिया' नाम से बड़ा अभियान छेड़ रखा है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

महासमर ▶ पृष्ठ 2

दिल्ली में आप ने घोषित किए अपने सभी 70 प्रत्याशी

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 46 वर्तमान विधायकों को मैदान में उतारा है। उन 15 विधायकों का टिकट काट दिया है, जिन्हें पार्टी कमजोर कड़ी मान रही थी। पार्टी की ओर से इस बार नौ नए चेहरे मैदान में होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सरकारी और निजी संस्थानों में लागू होगा योग-ब्रेक

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आयुष मंत्रालय ने नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। इसी के चलते सरकारी संस्थानों व कारपोरेट जगत में जल्द ही पांच मिनट का योगा-ब्रेक अनिवार्य हो जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

गूगल और वाट्सएप पुलिस को सुबूत मुहैया कराएं : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर जेएनयू प्रशासन, गूगल और वाट्सएप को निर्देश दिया कि 5 जनवरी को हुई हिंसा मामले से जुड़े सभी सुबूत, सीसीटीवी फुटेज और डाटा पुलिस को उपलब्ध कराएं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

थोक बाजार में भी सिर उठाने लगीं कीमतें, बढ़ी महंगाई

नई दिल्ली : खाने पीने के सामान की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते महंगाई फिर से सिर उठाने लगी है। दिसंबर, 2019 में थोक महंगाई की दर 2.59 फीसद हो गई। यह पिछले आठ महीने में सर्वाधिक है। नवंबर में थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर 0.58 फीसद रही थी।

फंदे के और करीब निर्भया के गुनहगार

फैसला ▶ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विनय व मुकेश की क्यूरेटिव व फांसी पर रोक की याचिका

सुप्रीम फरमान के बाद मुकेश ने दाखिल की राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पवन गुप्ता व अक्षय ने नहीं दाखिल की थी शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव याचिका
- निचली अदालत ने सात जनवरी को जारी किया था चारों दोषियों का डेथ वारंट
- तिहाड़ जेल में 22 जनवरी को दी जानी है चारों गुनहगारों को फांसी

विनय शर्मा

मुकेश कुमार फाइल फोटो

दिल्ली दुष्कर्म कांड की पीड़िता निर्भया के गुनहगार फांसी के फंदे के और करीब पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोषी विनय शर्मा (26) और मुकेश कुमार (32) की क्यूरेटिव याचिका और मृत्युदंड पर रोक की अर्जी खारिज कर दी। इस तरह कोर्ट ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने के फैसले पर फिर मुहर लगा दी। क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद इन दोनों दोषियों के पास सिर्फ राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का रास्ता ही बचा था। लिहाजा मुकेश की ओर से दया याचिका दाखिल कर दी गई। दो दोषियों पवन गुप्ता (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अभी क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। चारों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का आदेश दिया गया है।

मंगलवार को जस्टिस एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन, आर. भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने दोपहर 1.45 पर सर्कुलेशन के जरिये चैंबर में विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिकाओं पर विचार किया और याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, उन्होंने क्यूरेटिव याचिका और उसके साथ के जरूरी दस्तावेजों को देखा और पाया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2002 के अशोका रूपा हुर्रा केस में क्यूरेटिव याचिका पर विचार करने के तय मानकों में नहीं आता।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अशोका रूपा हुर्रा मामले में दिए फैसले में गंभीर अन्याय से बचाने के लिए मुकदमेदारों को क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प दिया था, लेकिन इसके कुछ तय नियम हैं। किसी भी क्यूरेटिव याचिका पर उन्हीं नियमों के मुताबिक विचार होता है। इन नियमों के मुताबिक क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के लिए वरिष्ठ वकील का प्रमाणपत्र याचिका के साथ लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश करते हैं। क्यूरेटिव याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई नहीं होती और न ही वहां वकीलों की अपील दलील होती है। याचिका पर न्यायाधीश चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये विचार करते हैं। विरले मामलों में ही कोर्ट क्यूरेटिव याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश देता है।

बता दें कि दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था जिसमें छात्रा से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारों अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है। उसके बाद ही निचली अदालत ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था।

विनय और मुकेश की याचिका में खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति और उम्र का हवाला देते हुए फांसी की सजा माफी की गुहार लगाई गई थी। पारिवारिक स्थिति का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया था कि कोर्ट ने दोषी में सुधार की संभावनाओं के पहलू पर विचार नहीं किया। इसमें कई पूर्व फैसलों का हवाला दिया गया था जिनमें कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया था। याचिका में कोर्ट से फांसी देने के पांच मई, 2017 के आदेश और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करने के आदेश भी रद करने की मांग थी। याचिकाएं खारिज होने के बाद मुकेश ने दया याचिका के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ वारंट रद करने के लिए भी याचिका दाखिल की है। इस पर बुधवार को सुनवाई की संभावना है।

डेथ वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा दोषी मुकेश पेज>>15

'शाहीन बाग मामले में जनहित के अनुरूप पुलिस ले निर्णय'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट में कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग खोलने की दायर की गई थी याचिका
- यातायात नियंत्रित करने पर पुलिस को नहीं दिया जा सकता निर्देश : कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

दिल्ली में तकरीबन एक महीने से बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जनहित, हालात और कानून व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बारे में फैसला करे।

हाई कोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, पुलिस के पास प्रदर्शन स्थल पर यातायात नियंत्रित करने का अधिकार है। वह एक माह से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के कारण बंद मार्ग के मामले पर विचार करे। पीठ ने कहा, पुलिस को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वह शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे प्रदर्शन और वहां की यातायात स्थिति को कैसे नियंत्रित करे। वे जमीनी हकीकत को देखते हुए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर से लोग उक्त मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि मार्ग बंद होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल बसों को दूसरे रास्ते से जाने को मजबूर होना पड़ रहा है और इसके कारण बच्चों को स्कूल के लिए समय से दो घंटे पहले निकलना पड़ता है। तमाम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 10 जनवरी को शाहीन बाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया था। याचिका के अनुसार विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-नोएडा डाइरेक्ट फ्लाई-वे (डीएनडी) मार्ग पर यातायात की समस्या हो रही है, ऐसे में वहां से प्रदर्शनकारियों को कहीं और स्थानांतरित किया जाए।

फरवरी में भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हो रही है बातचीत
- ट्रंप से पहले के तीनों राष्ट्रपति कर चुके हैं भारत की यात्रा

डोनाल्ड ट्रंप फाइल फोटो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के अंत तक भारत के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2017 में अमेरिका यात्रा के दौरान ही ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया था। फिर जब वह पिछले साल ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के दौरान ट्रंप से मिले, तब फिर उन्हें भारत आने का न्योता दिया। अब लगता है कि ट्रंप भारत आने को तैयार हैं। उनके आने की तिथि तय करने के लिए दोनों देशों के उच्चस्तरीय अधिकारियों के बीच संपर्क बना हुआ है। संभावना इस बात की है कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में चल रहे महाभियोग पर फैसला आने के बाद ही उनकी भारत यात्रा को लेकर भी अंतिम निर्णय होगा।

सूत्रों के मुताबिक, 'राष्ट्रपति ट्रंप के भारत आने को लेकर लगातार अमेरिकी सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात हो रही है, लेकिन, अभी तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ट्रंप वैश्विक कूटनीति के साथ ही घरेलू राजनीति में भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर फरवरी-मार्च, 2020 तक उनकी यात्रा नहीं हो पाती है, तो शायद उनके लिए इस कार्यकाल में भारत आना संभव नहीं हो सकेगा।' दरअसल इसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्षों के अंतराल पर होता है और नवंबर, 2020 में नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी।

ट्रंप ने सितंबर, 2019 में मोदी के साथ न्यूयार्क में हुई मुलाकात में भी कहा था कि वह जल्द-से-जल्द भारत जाने की मंशा रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन स्वयं ही ट्रंप की यात्रा जल्द करवाने को लेकर उत्साहित है।

ट्रंप की संभावित यात्रा भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता कही जाएगी। अभी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन व कई यूरोपीय देशों में सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की यात्रा से यह संदेश दिया जा सकेगा कि भारत की उक्त नीतियों को लेकर अमेरिकी प्रशासन उसके साथ है। कश्मीर पर भी अमेरिकी प्रशासन मिला-जुला संदेश दे रहा है। ट्रंप स्वयं कई बार कश्मीर में मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह कश्मीर की स्थिति को लेकर चिंतित है। वैसे जानकार यह भी मान रहे हैं कि ट्रंप की भावी यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को लेकर है। इस पर भारत की आंतरिक नीतियों का सीमित असर ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय से ही हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो अपने दोनों कार्यकाल में भारत की यात्रा की। अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2016 में वह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उनसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी भारत की यात्रा कर चुके थे। भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भी आमंत्रित किया था।

ईडी ने आम्रपाली मामले में फेमा नियमों का उल्लंघन पाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली समूह द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) से जुड़े कम से कम सात प्रावधानों के कथित उल्लंघन का पता लगाया है। यह भी पाया गया कि समूह ने गृह खरीदारों के 55 करोड़ रुपये से अधिक के कोष की हेराफेरी की और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से उसे विदेश भेजा।

जांच एजेंसी यह भी चाहती है कि इस मामले में कथित रूप से लिप्त अमेरिकी निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन को अवैध तरीके से विदेश भेजी गई तकरीबन 140 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए ताकि उसे जब्त किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह की दो कंपनियों... आम्रपाली जोडिएक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच में विदेशी विनियम प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत सात नियमों एवं प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाया है।

केरल ने सीएए को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नागरिकता संशोधन कानून को कोर्ट में चुनौती देने वाला बना पहला राज्य

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती दी है। केरल ने सीएए को संविधान के मूल सिद्धांत पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन बताते हुए रद करने की मांग की है। केरल पहला राज्य है जिसने संसद से पारित कानून सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह कानून समानता के अधिकार, जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इससे पहले केरल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।

सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ पहले से ही 60 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं जिन पर कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है और याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। हालांकि वे सभी याचिकाएं जनहित याचिकाएं हैं। केरल की याचिका केंद्र सरकार के खिलाफ मूलवाद है जो कि अनुच्छेद 131 के तहत दाखिल किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य व केंद्र के बीच होने वाले किसी भी विवाद चाहे वह कानून से संबंधित हो या तथ्यों पर आधारित हो, की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। केरल ने सीएए कानून पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ मूलवाद इसी अनुच्छेद में दाखिल किया है। इससे इसकी प्रकृति अन्य याचिकाओं से भिन्न हो जाती है।

केरल ने याचिका में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) कानून और उसके साथ पासपोर्ट एक्ट व फारेनर्स एमेन्डमेंट आर्डर में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है। केरल सरकार का कहना है कि सीएए व्यक्ति की धार्मिक पहचान पर आधारित है इसलिए यह पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसे कोर्ट भी अपने कई पूर्ववर्ती फैसलों में संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुका है।

उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून को इसी साल 10 जनवरी को अधिसूचित किया जा चुका है। इससे पड़ोसी इस्लामिक देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के बाद 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने पर अमल शुरू हो गया है। इन तीनों इस्लामिक देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक भारत आने के बाद भी बरसों से बदतर हालात में जी रहे थे।

याचिका में कहा, केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पेज>>5

सत्य नडेला ने विरोध के बाद सीएए के बयान पर दी सफाई

नई दिल्ली : माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्य नडेला ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जो कुछ हो रहा है वह खराब है और दुखद है। उनके इस बयान का भारत में तीखा विरोध हुआ। इसके बाद नडेला ने एक बयान जारी कर सफाई भी दी। (पेज-5)

डीएसपी की गिरफ्तारी को सांप्रदायिक रंग देने पर भड़की भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अधीर रंजन ने देविंदर सिंह के 'देविंदर खान' होने की स्थिति पर किया था ट्वीट
- भाजपा ने कहा, आतंक को धार्मिक रंग देना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति
- पुलवामा हमले पर स्थिति साफ करने की राहुल-सोनिया को दी चुनौती

जम्मू-कश्मीर के विवादित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देविंदर सिंह की गिरफ्तारी को सांप्रदायिक रंग देने को लेकर कांग्रेस और भाजपा में नई जंग शुरू हो गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'देविंदर सिंह' के 'देविंदर खान' होने की स्थिति में संघ की ट्रोल रेजिमेंट की ओर से और भी तीखी प्रतिक्रिया की आशंका जताई तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि आतंकवाद पर धर्म की राजनीतिक करना हमेशा से कांग्रेस की संस्कृति रही है।

वहीं पुलवामा आतंकी हमले की जांच नए सिरे से करने की कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की मांग पर हैरानी जताते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर भारत की पीठ में खंजर घोंपने और पाकिस्तान की तरफदारी करने का आरोप लगाया।

दरअसल आतंकियों के साथ गिरफ्तारी के बाद देविंदर सिंह की संसद से लेकर पुलवामा हमले तक में भूमिका को लेकर आशंका जताई जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस समेत केंद्रीय एजेंसियां तक इसकी जांच में जुटी हैं, लेकिन कांग्रेस ने मंगलवार को इसे धर्म से जोड़ते हुए नया मोड़ दे दिया। यही नहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की दोबारा जांच कराए जाने की मांग कर इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ होने की आशंका को हवा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि देविंदर सिंह केवल मोहरा है। इस तरह कांग्रेस ने खुद ही भाजपा को हमला करने का मौका दे दिया।

अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के बयान की निंदा करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आतंकी हमले का इस तरह राजनीतिकरण अशोभनीय है। पिछले कई मामले इस बात को साबित करते हैं कि कांग्रेस लगातार पाकिस्तान को बचाने और भारत पर हमला करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने हैरानी जताई कि किस तरह कांग्रेस पुलवामा हमले को फिर से जीवित कर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पुलवामा हमले पर स्थिति साफ करने की चुनौती दी। पात्रा ने कहा, कांग्रेस को सीधे तौर पर एलान करना चाहिए कि उन्हें देश की सेना और सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान नहीं है तो कौन है?

अधीर रंजन के ट्वीट पर भड़की भाजपा ने कहा कि हिंदू आतंकवाद से लेकर भारत के हिंदू पाकिस्तान बन जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू जिन्ना बताने जैसे बयानों से साबित होता है कि कांग्रेस हमेशा से आतंक को धार्मिक रंग देने का प्रयास करती रही है। उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस के रवैये और मुंबई हमले के बाद दिग्विजय सिंह के इसे आरएसएस की साजिश बताने के बयान का भी हवाला दिया। पात्रा ने राहुल गांधी के उस बयान का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सिमी या इस्लामिक आतंकवाद से डर नहीं है, बल्कि हिंदुओं से डर है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का पूरा प्रपंच जनता के सामने खुलकर सामने आ गया है।

डीएसपी देविंदर सिंह मामले की जांच एनआइए को सौंपी पेज>>6

वैश्विक कूटनीति

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कूटनीति के महाकुंभ की शुरुआत, नेताओं ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और सक्रिय होने की दी सलाह, पहले दिन अमेरिका-ईरान तनाव और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुई चर्चा

दुनिया में भारत का बढ़ता कद दिखाता है 'रायसीना डायलॉग'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वैश्विक कूटनीति पर आयोजित होने वाले एशिया के बेहद अनूठे कार्यक्रम 'रायसीना डायलॉग-2020' में हिस्सा लेने वाले कई राजनेताओं ने भारत को विश्व मंच पर और सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डॉयलाग के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए कहा भी कि भारत अब सिर्फ दुनिया में होने वाले इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह इसके केंद्र के तौर पर स्थापित होना चाहता है। यही नहीं जिस तरह से बहुध्रुवीय विश्व बन रहा है, उसमें अपने हितों की रक्षा करने के लिए भी इस तरह का आयोजन जरूरी है, ताकि एक मंच पर सभी पक्षों की राय जानी जा सके।

जयशंकर जब भाषण दे रहे थे, तब उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) हमदुल्लाह मोहिब, दुनिया के आठ देशों के पूर्व प्रमुख और तकरीबन एक दर्जन देशों के वर्तमान विदेश मंत्री उपस्थित थे। अगले दो दिनों के दौरान रायसीना डायलॉग-2020 के तहत 80 सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें दुनियाभर से आए तकरीबन 700 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

पहले दिन के उद्घाटन सत्र में अमेरिका-ईरान तनाव, वैश्विक कारोबार की दिक्कतें और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली समस्याओं पर खास तौर पर चर्चा हुई। डेनमार्क के पूर्व पीएम व नाटो के पूर्व महासचिव एंड्रेस रासमुसेन ने कहा कि अभी जिस तरह से कई देशों में तानाशाहों का कब्जा है उसे देखते हुए दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों को एक होना चाहिए। भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने पीएम मोदी की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत एक अहम शक्ति है और आगे भी बना रहेगा। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि भारत अब इस क्षेत्र में ज्यादा क्रियाशील हो गया है। बताते चलें कि मौरिसन को ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने से उन्होंने अपना दौरा रद कर दिया।

रायसीना डायलॉग उस समय हो रहा है जब कूटनीतिक तौर पर दुनिया में काफी अस्थिरता है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भारत के बेहद महत्वपूर्ण संबंध हैं। जैसे ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ इस कार्यक्रम में होंगे। अभी अमेरिका के साथ बेहद तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद उनका इस कार्यक्रम में शिरकत करना इसकी अहमियत को बताता है। यहां यह भी बता दें कि मोदी की ईरान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 12 विदेश मंत्रियों में से मोदी सिर्फ जरीफ और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अलग से बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुका भारत अब उसके साथ रिश्तों को लेकर ज्यादा मुखर होने का मन बना चुका है। यही वजह है कि ईरान व अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने पर जयशंकर ने पहले ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की।

नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2020 के उद्घाटन सत्र के दौरान लोगों का अभिवादन करते पीएम नरेंद्र मोदी। साथ में हैं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई। प्रेट्र

कश्मीर घाटी में हिमस्खलन से छह सुरक्षाकर्मियों समेत 12 की मौत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- 36 को बचाया गया, तीन की हालत गंभीर तीन सैन्य चौकियां और पांच मकान तबाह

कश्मीर घाटी में बीते 24 घंटों के दौरान हिमस्खलन व बर्फीले तूफान की चपेट में आकर छह सुरक्षाकर्मियों समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। बचाव दल के समय रहते पहुंच जाने से 11 सुरक्षाकर्मियों समेत 36 लोगों को बचा लिया गया। इनमें तीन की हालत नाजुक है। हिमस्खलन में तीन सैन्य चौकियां व पांच मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर शाम किपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में एलओसी पर तैनात बीएसएफ का गश्तीदल जाबरा पोस्ट के पास हिमस्खलन की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही निकटवर्ती शिविरों से बचावकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल राहत कार्य करते हुए छह जवानों को बर्फ के नीचे से जिंदा निकाल लिया। एक अन्य जवान को अचेत अवस्था में निकाला गया। उसे तुरंत निकटवर्ती सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे शहीद घोषित कर दिया गया। शहीद की पहचान गंगाबारा निवासी जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है।

मच्छल सेक्टर : कुपवाड़ा के ही मच्छल सेक्टर में एलओसी पर स्थित रिंगबाला, मैदान बहक में सोमवार देर रात सेना की 45 आरआर की एक चौकी हिमस्खलन की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे बचावकर्मियों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। एसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबरकर ने बताया कि पांचों जवानों को कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ से निकाल लिया गया, लेकिन उनमें से चार ने दम तोड़ दिया। पांचवें को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

श्रीनगर-लेह हाईवे में गई पांच की जान पेज>>7

20 नए मामले दर्ज किए गए हैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के सोमवार को राजधानी दिल्ली में। ये सभी नए मामले गैर राजनीतिक लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 15 जनवरी 2020

70 सीटों पर आप ने घोषित किए प्रत्याशी

रणनीति ▶ 15 विधायकों को नहीं मिला मौका, 46 को मिला टिकट, नौ सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे

इस बार आठ महिलाओं को पार्टी ने दिया अवसर

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने उन सभी 15 विधायकों का टिकट काट दिया है, जिन्हें पार्टी कमजोर कड़ी मान रही थी। वहीं 46 वर्तमान विधायकों को मैदान में उतारा है, वहीं 9 खाली सीटों पर नए चेहरे मैदान में होंगे।

आप ने इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि पिछली बार छह महिलाओं को टिकट दिया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से यह उनका तीसरा चुनाव होगा। वहीं मनीष सिसोदिया फिर से पटपड़गंज सीट से चुनाव मैदान में होंगे। अन्य सभी मंत्री गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत व इमरान हुसैन अपनी पुरानी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी पुरानी सीट शाहदरा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी दुर्गेश पाठक को करावल नगर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए सभी प्रमुख नेताओं को टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर फैसला लेने के लिए मंगलवार शाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके आवास पर हुई। बैठक के बाद सभी 70 सीटों पर आप ने अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान कर दिया।

पार्टी ने इस बार भी पूर्वांचल को प्राथमिकता देते हुए 13 विधायकों को टिकट दिया गया है। टिकट काटे जाने के बारे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही संकेत दे दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि जिनकी भी छवि ठीक नहीं पाई जाएगी उनकी टिकट कटेगी। यहां खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर आए सभी छह मजबूत नेताओं को आप ने प्रत्याशी बनाया है। कुछ स्थानों पर आप के विधायकों का टिकट काट कर कांग्रेस से आए लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है।

लोकसभा प्रत्याशी रहे तीन नेताओं पर लगाया दांव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आप ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़े तीन प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसमें पूर्वी दिल्ली से लोकसभा की प्रत्याशी रही आतिशी को कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी रहे राघव चड्ढा को राजेंद्र नगर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी रहे दिलीप पांडेय को तिमारपुर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसमें दिलीप पांडेय तिमारपुर में दो महीने पहले से ही सक्रिय थे। वहीं राघव चड्ढा ने भी राजेंद्र नगर में काम शुरू कर दिया था। आतिशी का पहले गांधी नगर, फिर लक्ष्मी नगर, फिर जंगपुरा से चुनाव लड़ने की बात चली। इसके बाद कालकाजी से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात चली थी। उन्हें इसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दो सीटों पर बड़े मिठाई विक्रेता को उतारा गया है। विश्वास नगर सीट पर दीपक सिंगला और रोहिणी से राजेश नामा बंसीवाला को उतारा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अन्य पांच मंत्री भी अपनी पुरानी सीटों से मैदान में उतरे हैं। इसमें गोपाल राय बाबरपुर, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती, कैलाश गहलोत नजफगढ़, इमरान हुसैन बल्लीमारान व राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी से चुनाव लड़ रहे हैं।

इन विधायकों का कटा टिकट

सीट	किसका कटा	किसे मिला
तिमारपुर	पंकज पुष्कर	दिलीप पांडेय
बवाना	रामचंद्र	जयभगवान उपकार
मुंडका	सुखबीर दलाल	धर्मपाल लाकड़ा
पटेल नगर	हजारीलाल	राजकुमार आनंद
हरी नगर	जगदीप सिंह	राजकुमारी ढिल्लों
द्वारका	आदर्श शास्त्री	विनय मिश्रा
दिल्ली कैंट	कमांडो सुरेंद्र सिंह	वीरेंद्र सिंह कादियान
राजेंद्र नगर	विजेंद्र गर्ग	राघव चड्ढा
कालकाजी	अवतार सिंह	आतिशी
बदरपुर	नारायण दत्त शर्मा	राम सिंह नेताजी
त्रिलोकपुरी	राजू धिंगान	रोहित कुमार महरोलिया
कोंडली	मनोज कुमार	कुलदीप कुमार
सीलमपुर	हाजी इशराक	अब्दुल रहमान
गोकुलपुर	फतेह सिंह	सुरेंद्र कुमार
मटिया महल	आसिम अहमद	शोएब इकबाल

विधायक ने लगाया टिकट बेचने का आरोप

जासं, नई दिल्ली : बदरपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी को टिकट दिए जाने से नाराज आप विधायक एनडी शर्मा ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। राम सिंह नेताजी को अपराधी व भू-माफिया बताया और खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री ने बदरपुर विधानसभा का टिकट 21 करोड़ रुपये में राम सिंह नेता जी को बेचा है। विधायक ने पार्टी को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया। उन्होंने आप सरकार द्वारा बिजली, पानी व बसों में किराया फ्री करने को चुनावी ढकोसला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सिर्फ झूठ की राजनीति करती है।

रणनीति के तहत बाहरियों पर आप ने लगाया दांव

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है। इसमें पार्टी में आए बाहरी नेताओं पर दांव लगाने से गुरेज नहीं किया है। बताया जा रहा कि पार्टी नेतृत्व लगातार लगातार सर्वे करा रहा था। इसमें जिन सीटों पर विधायकों की स्थिति कमजोर थी, उन पर नए प्रत्याशी उतारे गए। इसमें कुछ सीटों पर बाहर से आए मजबूत प्रत्याशियों को भी पार्टी ने मौका दिया है।

आप के प्रत्याशियों की सूची से स्पष्ट है कि पार्टी ने सभी सीटों पर जीतने की रणनीति बनाई है। इसमें कांग्रेस से आए छह लोगों को टिकट दिया है, जबकि एक सीट पर बीएसपी से आए नेता पर दांव लगाया है। इस बार दो बड़े मिठाई वाले भी मैदान में हैं। प्रत्याशियों की सूची पर गौर करें तो सोमवार को ही कांग्रेस व बसपा से पांच नेता आप में शामिल हुए थे। आप ने इन सभी को टिकट दिया है। इसमें कांग्रेस से आए बदरपुर के पूर्व विधायक रामसिंह नेताजी भी शामिल हैं। इन्हें विधायक एनडी शर्मा का टिकट काटकर मौका दिया गया है। कांग्रेस से आए विनय मिश्रा को द्वारका से टिकट मिला है। मिश्रा कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे हैं। इनके लिए पार्टी ने अपने विधायक आदर्श शास्त्री की टिकट काटी है। इसी तरह कांग्रेस से आईं।

राजकुमारी ढिल्लो को हरि नगर सीट से टिकट दिया है। ढिल्लो 2012 से 2017 तक निगम पार्षद रही हैं। इस सीट पर आप ने विधायक जगदीप सिंह का टिकट काटा है। कांग्रेस के दीपू चौधरी भी सोमवार को आप में शामिल हुए थे। उन्हें गांधी नगर से टिकट दिया गया है। अनिल वाजपेयी के पार्टी छोड़कर जाने के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस के ये चारों लोग सोमवार को आप में शामिल हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस से आप में आईं धनवती चंदीला को राजौरी गार्डन से टिकट दिया गया है। राजौरी गार्डन सीट अकाली-भाजपा गठबंधन के पास है।

कांग्रेस से आए शोएब इकबाल को मटिया महल से टिकट दिया है। शोएब पांच बार यहां से विधायक रहे हैं। इसी सीट पर आप के आसिम अहमद विधायक थे। इसी तरह कांग्रेस से आए प्रह्लाद सिंह साहनी को चांदनी चौक से टिकट दिया है। यह सीट अलका लांबा के कांग्रेस में जाने से खाली हुई थी। जयभगवान उपकार बसपा के टिकट से निगम पार्षद हैं। इन्हें बवाना से टिकट दिया गया है। उपकार भी सोमवार को ही आप में शामिल हुए थे। इससे पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह भी बसपा से आप में शामिल हुए थे। उन्हें गोकुलपुर सीट से टिकट दिया गया है। इस सीट पर आप के चौ. फतेह सिंह विधायक थे।

चुनावी हलचल

पहले दिन तीन उम्मीदवारों ने भरे पांच नामांकन

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पहले दिन मटियाला, नई दिल्ली व बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से तीन उम्मीदवारों ने पांच नामांकन पत्र दाखिल किए। नई दिल्ली सीट से एक ही उम्मीदवार वेंकटेश्वर महा स्वामी (उर्फ दीपक) ने तीन दलों के नाम पर अलग-अलग तीन नामांकन पत्र दाखिल किए। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने भाजपा, एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) व हिंदुस्तान जनता पार्टी के नाम पर पर्चा भरा गया है। जबकि अभी तक किसी दल ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि, उन्होंने शपथ पत्र के साथ भाजपा व एनसीपी का कोई पत्र नहीं सौंपा है। जबकि, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पार्टी द्वारा जारी पत्र भी सौंपना पड़ता है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आजाद नफे सिंह राजपूत ने निर्दलीय पर्चा भरा है। इसके अलावा मटियाला से मोहिंदर सिंह ने राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से नामांकन भरा है। प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं होने से पहले दिन नामांकन कम हुआ। (जासं)

भाजपा को राह दिखाने को स्वयंसेवक संभालेंगे कमान

नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव की तरह इस विधानसभा चुनाव में भी गोष्ठी के साथ ही स्वयंसेवक घर-घर जाकर राष्ट्रवाद का अलख जगाएंगे। इस काम में किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए समन्वयकों की भी तैनाती की जा रही है। लोकसभा चुनाव में स्वयंसेवकों ने पूरी दिल्ली में करीब 30 हजार बैठकें की थी। इस बार बैठकों की संख्या बढ़ाकर 40 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि समाज के सभी वर्ग तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। दरअसल, इन दिनों सीएए को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से संघ भी चिंतित है। संघ का मानना है कि वोट बैंक की राजनीति में भाजपा विरोधी पार्टियां सीसीए को लेकर लोगों गुमराह कर रही हैं। इसे ध्यान में रखकर लोकसभा की तुलना में ज्यादा बैठक करने के साथ ही जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया गया है। (राब्यू)

दिल्ली में 40 दिनों में ठंड से मर गए 413 बेघर : मनोज तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा ने गैर सरकारी संस्था के आंकड़ों को आधार बनाकर ठंड से बेघरों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में पिछले 40 दिनों में 413 बेघर लोगों की ठंड से मौत हो गई है। बीते एक वर्ष में 3,623 बेघर लोगों की मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री गीत गा रहे हैं 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल'।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले केजरीवाल ने बेघर लोगों की मौत को बड़ा मुद्दा बनाया था। बेघरों के लिए स्थायी एवं अस्थायी आश्रय गृह बनाने की घोषणाएं की थी पर आज पांच साल बाद भी ठंड से बेघर मर रहे हैं। मुख्यमंत्री गरीबों को घर देना तो दूर राजनीतिक विद्वेष के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं कर रहे हैं। इस योजना के तहत गरीबों को मकान उपलब्ध कराया जाना है।

नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं। वह दिल्ली के लोगों को भाजपा के खिलाफ

मनोज तिवारी। फाइल

भड़काने के लिए सांसद प्रवेश वर्मा की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे है। वह भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा की सरकार आने पर मुफ्त योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा की सरकार आने पर गरीबों व अन्य दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करवा दिया है। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अब मुफ्त सेवा का दिखावा कर रही है। उन्होंने दिल्ली की मंडियों में मंदी के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

महाराष्ट्र अपनाएगा दिल्ली का शिक्षा मॉडल, सिसोदिया करेंगे मदद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र सरकार दिल्ली के शिक्षा मॉडल को राज्य में लागू करने जा रही है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली में लागू शिक्षा मॉडल को देश में सबसे अच्छा होने की न सिर्फ मुहर है, बल्कि भाजपा व अन्य विपक्षी दलों को करारा जवाब भी है। सिसोदिया ने कहा है कि महाराष्ट्र समेत जो भी राज्य दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाना चाहते हैं, उन्हें हर संभव मदद देने को वह तैयार हैं।

सिसोदिया ने कहा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेंगे, तब तक देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। देश व शिक्षा के विकास के लिए व महाराष्ट्र सरकार व अन्य प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की थी और झारखंड में लागू करने की बात कही थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में पिछले दिनों नई सरकारें बनी। वहां दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर काफी जिज्ञासा है। वहां के मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री और अन्य पदाधिकारी दिलचस्पी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बोलते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

न्यूज पोर्टल की खबर को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने दिल्ली वालों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली के लोगों को बधाई। आपका शिक्षा मॉडल हर जगह लागू किया जा रहा है।

दरअसल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अजीत पवार ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने नवी मुंबई सहित सभी निगमों के स्कूलों में दिल्ली का शिक्षा मॉडल लागू करने की बात कही है। महाराष्ट्र सरकार ने नगर निगमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है।

कांग्रेस ने बताया आप सरकार के शिक्षा मॉडल को छात्र विरोधी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करके आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के शिक्षा मॉडल को छात्र विरोधी करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि शिक्षा के लिए आवंटित बजट का 46 फीसद राशि खर्च करने में विफल रही आप सरकार अपने शिक्षा मॉडल को सबसे बेहतर बता रही है।

उन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर तंज कसते हुए कहा कि यदि उनके शिक्षा मॉडल को किसी भी राज्य में लागू किया गया तो वहां के सरकारी स्कूल भी बर्बाद हो जाएंगे। दिल्ली की तरह उस राज्य के सरकारी स्कूल से भी बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे।

पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली के बच्चों के साथ बड़ा अपराध करके उन्हें दो श्रेणियों मे बांट दिया है। इससे बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बने कमरों पर सफेदी करके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इसकी जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पांच सालों में शिक्षा के लिए निर्धारित 26,577 करोड़ में से केवल 12,243.06 करोड रुपये ही खर्च किया है। पिछले चार सालों में सरकारी स्कूलों में 1.32 लाख बच्चे कम हो गए हैं, जबकि दिल्ली की आबादी बढ़ी है। स्कूलों में शिक्षकों के 65 फीसद पद खाली हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी गई है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि पांच सौ नए स्कूल बनाने का वादा करने वाली इस सरकार कार्यकाल में पांच सौ स्कूलों में प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस के शासन में 232 नए स्कूल खोले गए थे और 312 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। वहीं केजरीवाल सरकार ने पांच साल में मात्र छह स्कूल बनाए हैं, वह भी अधूरे हैं।

दुष्यंत ने भाजपा से मांगी एक दर्जन सीटें

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा और दिल्ली के कुछ भाजपा नेताओं के विरोध के बावजूद दिल्ली में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन के की उम्मीद बढ़ गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम एवं जजपा संयोजक दुष्यंत चौटाला ने एक दर्जन विधानसभा सीटों पर दावेदारी जताई है। हालांकि, आधा दर्जन सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है।

दुष्यंत चौटाला की भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक मुलाकात हो चुकी है। दूसरी बुधवार शाम अथवा बृहस्पतिवार को संभव है। इस मुलाकात में गठबंधन के प्रारूप और विधानसभा सीटों पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में भाजपा व जजपा के बीच राजनीतिक गठजोड़ के हक में हैं, लेकिन दिल्ली व हरियाणा के कुछ भाजपा नेता चाहते हैं कि दुष्यंत को ज्यादा भाव न दिया जाए।

सर्वे में जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की कम सीटें दिखाई जा रही हैं, उसके मद्देनजर हाईकमान किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में जजपा को

दुष्यंत चौटाला। फाइल

उसकी पसंद की कई सीटें देने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। दरअसल जजपा के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पार्टी अगर विरोध में प्रत्याशी उतारती है, तो इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। पिछले सवा साल में दुष्यंत चौटाला का यह चौथा चुनाव होगा। इनेलो से अलग होने के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने सबसे पहला जींद उपचुनाव लड़ा। उसके बाद लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन किया। अब दिल्ली चुनाव में जजपा हर हाल में उतरने को तैयार है। यदि भाजपा के साथ जजपा का गठबंधन नहीं होता है तो उस स्थिति में भी दुष्यंत करीब एक दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार को फिर बुलाई बैठक : जजपा के दिल्ली प्रभारी के नाते दुष्यंत चौटाला ने बृहस्पतिवार को फिर पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दुष्यंत ने अपनी पार्टी के पांच प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रखी है। हर्ष कुमार के पास दिल्ली की संगम विहार, देवली और बदरपुर विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। दिग्विजय सिंह चौटाला नजफगढ़, पालमपुर, मटियाला और द्वारका विधानसभा सीटों पर काम संभाले हुए हैं, जबकि डा. केसी बांगड़ के पास नरेला विधानसभा सीट है। राजेंद्र लितानी को मुंडका व नांगलोई तथा अनंत राम तंवर को बिजवासन, महरौली और छतरपुर विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। यह 13 विधानसभा सीटें वे हैं, जिन पर जजपा चुनाव लड़ने का मन बना रही है।

उत्तर प्रदेश से सटे जिलों पर भी निगाह : उत्तर प्रदेश के जिलों से सटे विधानसभा क्षेत्रों पर भी दुष्यंत चौटाला की निगाह है। गाजियाबाद और नोएडा से लगी करीब आधा दर्जन सीटों पर जजपा कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला से टिकट मांगे हैं।

नेशनल कैपिटल

कांग्रेस नेता थरूर ने केजरीवाल पर टिप्पणी के लिए मांगी माफी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आलोचना के बाद मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा था, 'दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिना जिम्मेदारी के सत्ता चाहते हैं, जो किन्नरों का विशेषाधिकार है।' थरूर ने सोमवार की रात आरोप लगाया था कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर केजरीवाल दोतरफा रवैया अपना रहे हैं। थरूर ने एक टीवी चैनल से कहा था, 'उन्होंने मानवीय सहानुभूति भी नहीं दिखाई। एक राज्य के मुख्यमंत्री से पीड़ितों के लिए इसकी उम्मीद की जाती है। अगर छात्रों की इस तरह पिटाई दूसरे राज्य में होती तो वहां के मुख्यमंत्री उनसे मिलते।' केरल के तिरुअनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा, 'केजरीवाल वास्तव में बिना जिम्मेदारी के सत्ता चाहते हैं, जिसे हम सदियों से किन्नरों का विशेषाधिकार समझते रहे हैं।' उनकी इस टिप्पणी की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई। लोगों ने उन्हें ट्रांसजेंडरों के प्रति पूर्वाग्रही बताया और समुदाय से माफी मांगने के लिए कहा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार रनवे के लिए होगी स्टडी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार रनवे की स्टडी कराने के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। एक सप्ताह में एजेंसी का चयन कर स्टडी का कार्य उसे सौंप दिया जाएगा। अप्रैल तक स्टडी पूरी होगी। इसके बाद प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगले एक साल में जेवर एयरपोर्ट के लिए तीन हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए जमीन अधिग्रहण चल रहा है। एयरपोर्ट के लिए विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी का चयन हो चुका है। 2022-23 से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआती चरण में जेवर एयरपोर्ट से सालाना एक करोड़ बीस लाख यात्रियों के हवाई सेवाओं का उपयोग करने का अनुमान है।

> जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार रनवे के लिए स्टडी कराने पर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्टडी कराने के लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा। अप्रैल तक स्टडी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।
>
> **-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण एवं नियाल**

वहीं प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट पर चार रनवे की स्टडी कराने की अनुमति दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) स्टडी के लिए जल्द ही एजेंसी का चयन करेगी। करीब एक सप्ताह में एजेंसी का चयन कर उसे स्टडी की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। मौसम का पूर्वानुमान, एयरपोर्ट पर यात्रियों की सालाना संख्या, हवाई सेवाओं की संख्या समेत विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार होगी। अप्रैल तक स्टडी रिपोर्ट मिलेगी।

प्रचार प्रपंच

फिल्मी दृश्यों के जरिये एक-दूसरे को घेर रहे राजनीतिक दल, फिल्म बाजीगर के एक दृश्य पर आप, भाजपा और कांग्रेस भिड़ीं

सियासी दलों की ट्विटर पर 'बाजीगरी'

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

दिल्ली की सियासी लड़ाई फिल्म स्टार शाह रुख खान, काजोल और अजय देवगन पर लड़ी जा रही है? ये पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि आखिर सियासत में इन सितारों का क्या काम, तो आपको बता दें कि ट्विटर पर इन्हीं फिल्मी सितारों की तस्वीरों, फिल्मी दृश्यों पर तीनों प्रमुख दलों के बीच ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। बाजीगर फिल्म का एक दृश्य ट्वीट कर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना जरूर साधा, लेकिन यह ट्वीट उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। दोनों दलों को आपस में उलझता देख कांग्रेस भी ट्वीट वार में कूद पड़ी और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' सरीखी लाइनें लिख दिल्ली की गद्दी कांग्रेसी झोली में गिरने की वकालत कर डाली।

यह ट्विटर वार तब शुरू हुआ जब आप ने बाजीगर फिल्म के सुप्रसिद्ध गाने- 'छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता' से संबंधित एक दृश्य पोस्ट किया। इसमें अभिनेता शाह

कांग्रेस द्वारा ट्विट किया गया फिल्मी दृश्य। सौ. ट्विटर

रुख खान और सिद्धार्थ रे काजोल की तरफ देख रहे हैं। इस फिल्मी दृश्य को आप ने सियासी ट्विस्ट दिया और शाह रुख खान को अरविंद केजरीवाल, काजोल को दिल्ली और सिद्धार्थ रे को मनोज तिवारी बताते हुए ट्वीट किया। यह फिल्मी पोस्ट आप के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ऑल द बेस्ट मनोज तिवारी लिखकर किया गया। अतिउत्साहित समर्थकों ने इस ट्वीट को हाथोंहाथ लिया और एक के बाद समर्थक री-ट्वीट करने लगे। इसमें रोचक मोड़ तब आया, जब भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसका जवाब दिया गया। इसमें लिखा गया कि बाजीगर में शाह रुख छेड़छाड़ करने वाला खलनायक था, जिसने काजोल और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची। उसने काजोल की बहन को भी मार डाला, और अंत में वह अपने पापों के चलते मारा गया। कुछ ऐसा ही दिल्ली में केजरीवाल के साथ होगा? आप और भाजपा के बीच इस ट्वीट वार में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने भी बाजीगर फिल्म के ही दृश्य को ट्वीट किया, लेकिन उसने एक ट्विस्ट कर दिया। दृश्य में अजय देवगन की तस्वीर लगाकर उन्हें कांग्रेस संबोधित किया। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया कि कांग्रेस वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप और भाजपा देखते रह जाएंगे।

23 साल बाद गौतमबुद्ध नगर में बढ़ा पुलिस बल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ गई है। पिछले 23 सालों से जिले में तैनात रहे अलग-अलग एसएसपी द्वारा पुलिस बल की मांग की गई। अब एक साथ 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती गौतमबुद्ध नगर जिले में की गई है। उम्मीद है कि पुलिसकर्मियों की बढ़ती संख्या से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और अपराध पर अंकुश लग सकेगा। पुलिस बल की कमी के चलते ही अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे और बदमाश ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देते थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर विशेष फोकस किया गया है। बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

दरअसल, गौतमबुद्ध नगर जिले की स्थापना वर्ष 1997 में की गई। जिला बनने के बाद से पुलिस बल की कमी हमेशा से यहां रही। लेकिन वर्ष 2020 के शुरुआती 14 दिनों ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती जिले में की गई है। जिसमें सबसे अधिक संख्या सिपाहियों की है। पुलिस बल बढ़ने के साथ ही सड़कों पर लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। जिले में सबसे बड़ी समस्या स्नैचिंग है। अक्सर बदमाश मोबाइल, नकदी या चेन लूट कर भाग जाते है। इसका मुख्य कारण सुनसान सड़कें और वहां पुलिस की मौजूदगी नहीं होना है।

पुलिसकर्मियों की कमी से पनपा अपराध : वर्ष 1997 में गौतमबुद्ध नगर जिला बनने के बाद कुख्यात नरेश भाटी व सुंदर भाटी गिरोह जिले में सक्रिय हुए। जिले में उद्योगों को बढ़ावा मिला, लेकिन पुलिस बल नहीं बढ़ा। इसका फायदा बदमाशों ने उठाया और ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दिया। यदि जिला बनने के बाद ही पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाती तो अपराध पर पहले ही कुछ हद तक अंकुश लग सकता था।

थानों से मांगे गए नाम : जिले में सात आइपीएस अधिकारियों की तैनाती के साथ ही उनके ऑफिस, घर व कार्यालय का मंथन शुरू हो गया है। अधिकारियों के

10 पायदान फिसल गया है भारत शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। 84वें स्थान पर भारत अब मॉरिटेनिया और ताजिकिस्तान के समकक्ष हो चुका है।

न्यूज गैलरी

'गुलाम कश्मीर पर सेना प्रमुख की टिप्पणी पर होगा विचार'

मुंबई : गुलाम कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने के बयान पर रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि सरकार इसके बारे में विचार करेगी। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनका तो जज्बा यही है। इनका यह बोलना गलत नहीं है। सरकार इस बात पर निश्चित तौर से गौर करेगी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सैनिकों की देश सेवा की सराहना भी की। इसके अलावा उन्होंने दिवंगत सैनिकों की याद में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी को सेना प्रमुख नरवाने ने कहा था कि यदि सेना को आदेश मिलता है, तो वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को फिर से हासिल करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने संसद द्वारा पारित उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया था, जिसमें संपूर्ण जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग बताया गया था। उन्होंने कहा कि यदि संसद चाहती है और इस सिलसिले में कोई आदेश मिलता है, तो सेना उचित कार्रवाई करेगी। बताते चलें कि फरवरी, 1994 में पीवी नरसिंह राव सरकार के दौरान संसद ने संकल्प प्रस्ताव पारित कर गुलाम कश्मीर को जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र बताते हुए भारत का हिस्सा करार दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद दो बार साफ कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत केवल गुलाम कश्मीर के मसले पर ही होगी। (एएनआइ)

भारत ने पाक से समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे मांगे

नई दिल्ली : भारत ने पाकिस्तान से वाघा में पिछले पांच महीने से खड़ी समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे लौटाने को कहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रेल सेवा निलंबित कर दी गई। रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से इस संबंध में अनुरोध किया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारे (रेलवे) अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वह ट्रेन के हमारे डिब्बे लौटाए।' ट्रेन के डिब्बों को अंतिम बार आठ अगस्त 2019 को इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वाघा सीमा पर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी थी और 117 यात्री फंस गए थे। ट्रेन को अपराह्न 12:30 पर अटारी पहुंचना था, लेकिन वह शाम 5:15 बजे पहुंची जब भारतीय रेल ने ट्रेन और अपने यात्रियों को वाघा सीमा से अटारी लाने के लिए अपना इंजन, चालक दल के सदस्यों और सुरक्षाकर्मियों को भेजा। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए दोनों देश छह महीने के अंतराल पर एक दूसरे के रेल के डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं। (प्रेट्र)

फिटनेस मंत्र ▸ केंद्र लाया कार्यस्थल पर कर्मचारियों को तनावमुक्त करने का नुस्खा

हर संस्थान में लागू होगा योग-ब्रेक

आयुष मंत्रालय ने पांच मिनट की हल्की कसरत का प्रोग्राम तैयार किया, ट्रायल शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र : काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो। इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आयुष मंत्रालय ने एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। इसी के चलते सरकारी संस्थानों और कारपोरेट जगत में जल्द ही पांच मिनट का वाई ब्रेक या योगा-ब्रेक अनिवार्य हो जाएगा। इन योगासनों से कर्मचारियों का ध्यान दुरुस्त होगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी। इस दौरान काम के घंटों में से सिर्फ पांच मिनट की छुट्टी लेकर कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी।

कार्यस्थल पर व्यवसायियों को तनावमुक्त और तरोताजा करने में मदद के लिए हल्के-फुल्के योगासन कारगर होने वाले हैं। ताकि विशेष रूप से डेस्क वर्क करने वाले कर्मचारी और अधिकारी घंटों एक ही अवस्था में बैठे रहकर रोगग्रस्त न हो जाएं। विगत सोमवार को आयुष मंत्रालय ने पांच मिनट के वाई ब्रेक का ट्रायल कराया। यह वाई ब्रेक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के जरिए मंत्रालय ने विकसित कराया है। यहां के प्रख्यात योग विशेषज्ञों की देखरेख में कुछ आसान योगासनों को इसमें समाहित किया गया है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ कारपोरेट हाउस जैसे टाटा कैमिकल्स, एक्सिस बैंक और अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल कंसल्टिंग सर्विसेज समेत करीब 15 संस्थानों ने इस ट्रायल में स्वैच्छिक रूप से हिस्सा लिया है। आयुष मंत्रालय ने इससे पहले सरकारी संस्थानों और अन्य कारपोरेट कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से 30 मिनट का ब्रेक करने की अपील की थी।

फिक्की ने कंपनियों को अपने कारपोरेट ऑफिसों में अपने कर्मचारियों को योग-ब्रेक देने का सर्कुलर भी जारी किया है। वाई-ब्रेक योगासनों का कोई कोर्स नहीं है। बल्कि यह एक संक्षिप्त मॉड्यूल है। इस योग प्रोटोकाल की प्रक्रिया पर करीब तीन महीने पहले दस प्रख्यात योग विशेषज्ञों ने काम शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि इन हल्की-फुल्की कसरतों पर एक बुकलेट और वीडियो फिल्म भी तैयार की गई है। ताकि इन्हें कारपोरेट हाउस में दिखाया जा सके। इसके प्रभाव और दक्षता को परखने के लिए ट्रायल जारी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को काम के भारी दबाव से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए पांच मिनट का यह ब्रेक स्ट्रेस दूर करने में सहायक होगा और उनकी कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ेगी। साथ ही कर्मचारियों को कई तरह के रोगों से भी निजात मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने खेल को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल किया जा सकता है या नहीं इसका जवाब देने का निर्देश दिया। एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस संबंध में प्रश्नावली तैयार की है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्हें अभी तक सिर्फ आठ राज्यों से ही जवाब मिले हैं, लेकिन यह आधे अधूरे और अस्पष्ट हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने दो पेज की प्रश्नावली तैयार की है ताकि इस मामले से संबंधित मुद्दों पर राज्य जवाब दे सकें। पीठ ने शंकरनारायणन को सभी राज्यों को यह प्रश्नावली भेजने की अनुमति देते हुए उन्हें तीन सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का निर्देश दिया। शीर्ष

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

अदालत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्याय मित्र ने कहा कि उनकी प्रश्नावली में राज्य सरकारों और राज्य के शिक्षा बोर्ड से सबंधित सवाल भी हैं। इनमें खेल शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया है। इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धन या मदद प्रदान करते हैं।

ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर पर ब्रॉडकास्टरों को फौरी राहत नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बांबे हाई कोर्ट ने ट्राई से जवाब दाखिल करने को कहा, अगली सुनवाई 22 को
- ऑर्डर में 153 रुपये में 200 फ्री चैनल व 12 रुपये में पेड चैनल दिखाने का आदेश

ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ब्रॉडकास्टरों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को ट्राई से ब्रॉडकास्टरों की आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके आधार पर वह 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। इस बीच भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए टैरिफ ऑर्डर को उचित ठहराते हुए इसे सभी के लिए न्यायसंगत बताया है। नया टैरिफ ऑर्डर एक मार्च से लागू होना है।

याचिकाकर्ता एवं ब्रॉडकास्टरों की प्रतिनिधि संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने यह कहते हुए नए टैरिफ ऑर्डर का विरोध किया है कि इससे उनका रेवेन्यू कम होगा और ब्रॉडकास्टिंग उद्योग के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। फाउंडेशन में टीवी ब्रॉडकास्टरों के अलावा फिल्म एवं टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड तथा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया शामिल हैं।

नए टैरिफ ऑर्डर में ब्रॉडकास्टरों को 130 रुपये (कर समेत 153 रुपये) में 100 के बजाय 200 फ्री टू एयर चैनल दिखाने को कहा गया है। इसमें पेड चैनलों की नई दरें भी निर्धारित की गई हैं और ब्रॉडकास्टरों से 15 जनवरी तक इन सभी दरों को टीवी पर सार्वजनिक करने को कहा गया है। याचिका में इस अंतिम तिथि को स्थगित करने की भी मांग की गई है।

नया टैरिफ ऑर्डर ट्राई द्वारा दिसंबर 2018 में जारी और फरवरी 2019 से लागू पहले टैरिफ ऑर्डर का संशोधित रूप है। पहले टैरिफ ऑर्डर में ब्रॉडकास्टरों को 100 फ्री टू एयर चैनल दिखाने के लिए ग्राहकों से नेटवर्क कैपेसिटी फीस के रूप में 130 रुपये वसूलने (कर समेत 153 रुपये) की छूट दी गई थी। उसने छह महीने की परामर्श प्रक्रिया के बाद अब अपने पहले टैरिफ ऑर्डर में संशोधन कर नया ऑर्डर निकाला है। नए टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक 200 फ्री टू एयर चैनलों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य चैनलों को नहीं गिना जाएगा। जिन घरों में एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा टीवी हैं, वहां अन्य टीवी सेट्स के लिए 40 फीसद से अधिक नेटवर्क कनेक्शन फीस नहीं वसूली जा सकती है।

इसी प्रकार पेड चैनलों की बकेट में किसी भी चैनल का मूल्य बकेट के मूल्य के डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। बकेट में शामिल किसी भी पेड चैनल की दर उसमें शामिल दूसरे चैनलों की औसत दर के तीन गुना से ज्यादा नहीं हो सकती।

बांग्लादेश की नाराजगी हुई दूर, सूचना-प्रसारण मंत्री भारत आए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दोनों देशों के बीच कारोबार सहयोग पर गठित समूह की बैठक आज
- बंग बंधु पर एक फिल्म बनाने के समझौते पर भी किए हस्ताक्षर

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनसीआर) में बार-बार अपना नाम लिए जाने से नाराज बांग्लादेश को मनाने में अंततः भारत सफल रहा है। बांग्लादेश के सूचना-प्रसारण मंत्री हसन महमूद न सिर्फ मंगलवार को भारत पहुंचे, बल्कि उन्होंने यहां एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। बुधवार को दोनों देशों के बीच कारोबार सहयोग पर गठित समूह की बैठक होगी।

हसन महमूद ने सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर के साथ बंग बंधु पर एक फिल्म बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। भारत व बांग्लादेश के साझा सहयोग से बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल करेंगे। महमूद ने इस समझौते के बाद रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लिया। सनद रहे कि पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम के रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में इसे टाल दिया था। दरअसल, जब से भारतीय संसद में सीएए पारित हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश के नेताओं

बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद (दाएं) ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात की। एएनआइ

के तीन भारतीय दौरों को रद किया गया। माना जाता है कि बांग्लादेश ने नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) से नाराज होकर ही यह फैसला किया था। वैसे भारत ने उसे आश्वस्त किया था कि सीएए मौजूदा शेख हसीना सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाती है।

मोदी ने किए घरेलू बजट के 'टुकड़े-टुकड़े' : राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जीडीपी गिरावट, बेरोजगारी व महंगाई की हालत को आर्थिक आपातकाल जैसा बताया
- कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से की मंहगाई पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग
- प्रियंका बोलीं, सरकार ने जेब काट कर पेट पर लात मार दी है

राहुल गांधी। फाइल

लगाया आरोप

3.15 फीसद से बढ़कर खुदरा महंगाई 7.35 फीसद हो गई

60 फीसद बढ़ गए सब्जियों और 15 फीसद दाल के दाम

2019 में 16 लाख नौकरियों के कम होने का भी आरोप लगाया

कांग्रेस ने आर्थिक सुस्ती के बीच महंगाई में भारी इजाफे को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने देशवासियों के घरेलू बजट के 'टुकड़े-टुकड़े' कर दिए हैं। वहीं पार्टी ने महंगाई पर प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई ही मोदी सरकार का देश को दिया अब तक का दो तोहफा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने तो आम लोगों की जेब काट कर उनके पेट पर लात मार दी है।

महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने उसी टुकड़े-टुकड़े नारे का सहारा लिया जिसे भाजपा अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। राहुल ने ट्वीट कर कहा 'कमरतोड़ महंगाई, जानलेवा बेरोजगारी और गिरती जीडीपी ने आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है। सब्जी, दाल, खाने का तेल, रसोई गैस व खाद्य पदार्थों की महंगाई ने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया है। मोदी जी ने देशवासियों के घरेलू बजट के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं।'

प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा 'सब्जियों, खाने-पीने की चीजों के दाम आमलोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या? ऊपर से मंदी की वजह से गरीब को काम भी नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने तो जेब काट कर पेट पर लात मार दी है।'

वहीं, कांग्रेस की ओर से हमला बोलते हुए मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस कहा कि 2012-13 के बाद महंगाई पहली बार इतनी चरम सीमा पर पहुंची है। तब पीएम मोदी ने कहा था कि महंगाई वह डायन है जो हर रोज बढ़ती जाती है और इसीलिए अबकी बार महंगाई पर वार। मगर अब पीएम महंगाई पर चुप हैं। खुदरा महंगाई जुलाई 2019 में 3.15 फीसद से बढ़कर दिसंबर में दोगुनी से ज्यादा 7.35 फीसद हो गई है और जनवरी में यह आठ फीसद का आंकड़ा छू रही है।

सब्जियों के दाम 60 फीसद और दालों के 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ गए हैं। दूध, मीट और मछली के साथ मसालों के दाम में भी भारी में इजाफा हुआ है। प्याज 2014 में आठ रुपये किलो था जो आज 85 रुपये किलो से ज्यादा है। इसीलिए कांग्रेस की मांग है कि पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी दलों को 30 दिन के भीतर महंगाई कम करने का रोडमैप बताएं।

सुरजेवाला ने कहा कि एक ओर जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ भाजपा की आय में भी 1400 फीसद का इजाफा हुआ है।

महंगाई के साथ बेरोजगारी पर आरबीआइ के आंकड़ों के सहारे सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2019-20 में 16 लाख नौकरियां कम हो गई हैं। ताजा आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि इस साल करीब 50,000 सरकारी नौकरियां भी कम हो जाएंगी। सुरजेवाला ने कहा कि लोगों से जुड़े इन मुद्दों का हल निकालने का काम करने की बजाय सरकार का काम शासन करना नहीं विभाजन करना बन गया है।

दुर्लभ बीमारी के मरीजों को 15 लाख तक की मदद देगी सरकार

- दुर्लभ रोग नीति के मसौदे में एकमुश्त इलाज के लिए प्रावधान
- बीपीएल परिवारों और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्रों को होगा फायदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार दुर्लभ बीमारियों के एकमुश्त इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देगी। बहुप्रतीक्षित दुर्लभ रोग नीति मसौदे में राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत इसका प्रावधान किया गया है।

दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा सोमवार को जारी किया गया। इसके तहत लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत आबादी भी इसके लिए पात्र होगी। दुर्लभ बीमारियों में किडनी और लीवर प्रत्यारोपण भी शामिल है। केंद्र सरकार की इस योजना से कई जरूरतमंदों को लाभ पहुंचेगा। फिलहाल कई दुर्लभ बीमारियों में अधिक खर्च होने के कारण लोगों को इलाज में आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का इरादा कुछ चिकित्सा संस्थानों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में अधिसूचित करने का इरादा है। इनमें एम्स, नई दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ शामिल हैं।

मसौदा नीति के अनुसार इन केंद्रों में मरीजों के उपचार का खर्च ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त दान से पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने मसौदा नीति अपनी वेबसाइट पर डाल दी है और 10 फरवरी तक इस पर टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं। मसौदे में कहा गया है कि सरकार दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के इलाज पर आने वाले खर्च के लिए दान करने वाले स्वैच्छिक लोगों और कॉर्पोरेट घरानों की खातिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित कर वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र बनाने का प्रयास करेगी।

ट्रेनों में 2022 से मांग पर सिनेमा, वीडियो

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2022 से यात्रा के दौरान रेल यात्री सिनेमा, शो, शैक्षणिक कार्यक्रम, वीडियो जैसी मनोरंजन सेवाओं का निर्बाध आनंद उठा सकेंगे। रेलवे सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल की ओर से मंगलवार को बताया गया कि यह पेड और अनपेड दोनों रूपों में उपलब्ध रहेगा।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने जी एंटरटेनमेंट की सहयोगी मार्गो नेटवर्क को डिजीटल एंटरटेनमेंट सेवा प्रदाता (डीईएसपी) के रूप में चुना है। मार्गो नेटवर्क ट्रेनों और स्टेशनों में मांग पर कंटेंट (सीओडी) मुहैया कराएगा।

रेलटेल ने कहा है, 'अगले दो वर्षों में भारतीय रेलवे की सभी प्रीमियम, एक्सप्रेस, मेल ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों में सीओडी उपलब्ध होगा। सिनेमा, शो, शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे कंटेंट 10 वर्षों के लिए ठेके पर पेड और अनपेड दोनों रूपों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें शुरू के दो वर्ष लागू करने के होंगे।' इस परियोजना में रेलटेल चलती ट्रेनों में स्थापित मीडिया सर्विस के माध्यम से विभिन्न प्री-लोडेड बहु-भाषी कंटेंट (सिनेमा, संगीत, वीडियो, सामान्य मनोरंजन, जीवनशैली) मुहैया कराएगा।, जिसके बाद लोग मनोरंजन भी कर पाएंगे।

जब अमित शाह ने उड़ाई पतंग...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं से दूसरे) ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तरायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पतंगबाजी में भी हाथ आजमाया। पतंगबाजी करते शाह को देखने के लिए लोग आसपास के घरों की छतों पर उमड़े नजर आए। गुजरात में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार वाले दिन लोग पतंगें उड़ाने के साथ खुशी मनाते हैं। प्रेट्र

लड़कियों का सरकारी लड़कों का निजी स्कूल में प्रवेश कराते हैं लोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : चार से आठ वर्ष आयु वर्ग के 90 फीसद से अधिक बच्चे किसी ने किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक है। मंगलवार को जारी शिक्षा के स्तर पर 14वीं वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) में यह जानकारी दी गई है। वर्ष 2019 के लिए एएसईआर की यह रिपोर्ट 24 राज्यों के 26 जिलों में कराए गए सर्वे पर आधारित है। सर्वे में चार से आठ वर्ष आयु वर्ग के 36 हजार बच्चों को शामिल किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'चार से आठ वर्ष आयु वर्ग के 90 फीसद से ज्यादा बच्चे किसी ने किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेते हैं। सर्वेक्षण के लिए चुने गए जिलों में यह प्रतिशत उम्र के साथ बढ़ता है। चार वर्ष की आयु में 91.3 फीसद बच्चों ने प्रवेश लिया, लेकिन आठ वर्ष की आयु के बच्चों में यह प्रतिशत 99.5 फीसद रहा।' हालांकि समान उम्र के बच्चों में इस बात का काफी अंतर देखा गया कि उनका प्रवेश कहां हुआ। उदाहरण के तौर पर पांच वर्ष के 70 फीसद बच्चे आंगनबाड़ी या प्री-प्राइमरी कक्षा में है, लेकिन 21.6 फीसद पहले से कक्षा एक में दाखिला ले चुके हैं।

छह वर्ष के 32.8 फीसद बच्चे आंगनबाड़ी या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में हैं जबकि 46.4 फीसद कक्षा एक में और 18.7 फीसद कक्षा या ऊंची कक्षाओं में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 'छोटे बच्चों में भी लैंगिक असमानता साफ तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि सरकारी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के प्रवेश की संख्या अधिक है और निजी संस्थानों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों के प्रवेश की संख्या अधिक है।'

कह के रहेंगे

माधव जोशी

पीएम से सवाल पूछने के लिए छात्रों में जबरदस्त उत्साह

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

'परीक्षा पे चर्चा'

- अब तक करीब तीन लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, दो लाख से ज्यादा ने किए सवाल भी
- 20 जनवरी को होगी चर्चा, पिछले साल सिर्फ सवा लाख बच्चों ने ही कराया था रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल

दसवीं और बारहवीं के बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू हो रही हैं। ऐसे में बच्चों में परीक्षा को लेकर किसी तरह का तनाव हावी हो, इससे पहले ही प्रधानमंत्री उन्हें इस तनाव को भगाने की टिप्स देते नजर आएंगे। 'परीक्षा पे चर्चा' पर पीएम का यह कार्यक्रम 20 जनवरी को होगा। छात्रों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब तक देश भर के करीब तीन लाख छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से करीब दो लाख बच्चों ने पीएम से सवाल भी किया है। हालांकि कार्यक्रम में करीब दो हजार बच्चों को ही शामिल होने का मौका मिलेगा। इनमें से करीब 18 से 20 बच्चे सवाल भी पूछ सकेंगे।

प्रधानमंत्री के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' में शामिल होने को लेकर छात्रों का यह रुझान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के दौरान सामने आया है। इस दौरान छात्रों के चयन का जो आधार तय किया गया, वह निबंध प्रतियोगिता के जरिए होना है। इसमें छात्रों को पांच अलग-अलग विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना था। इस दौरान जिस बच्चे का निबंध सबसे अच्छा होगा, उन्हें ही इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। हालांकि छात्रों के चयन की यह जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। इसके तहत प्रत्येक राज्य का एक कोटा तय किया गया है, जो उस राज्य में कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों की संख्या के आधार पर तय की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए करीब छह करोड़ रुपये का बजट भी तय किया है, जो बाहर से आने वाले बच्चों के रुकने और आने-जाने पर खर्च होगा।

गौरतलब है कि छात्रों के साथ परीक्षा से पहले पीएम का इस तरह से रूबरू होने का यह तीसरा साल है। इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। पिछले साल में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी करीब सवा लाख छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे।

पढ़ाई-लिखाई और सेहत से जुड़े सबसे ज्यादा सवाल : इस बीच पीएम के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान छात्रों ने जो सवाल भेजे है, उनमें बड़ी संख्या में सवाल पढ़ाई- लिखाई और सेहत से जुड़े है। सूत्रों की मानें तो इनमें से कुछ सवाल मौजूदा राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़े हैं, लेकिन जैसा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होता है, ऐसे में इस तहत के सवालों को शामिल करना मुश्किल है।

इन विषयों पर लिखने थे निबंध : 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों से जिन पांच विषयों पर निबंध मांगे गए थे, उनमें कृतज्ञता एक महान गुण है, आपकी आकाक्षांओं से संवरता है आपका भविष्य, परीक्षा का मूल्यांकन, हमारे कर्तव्यों पर आपके विचार, संतुलन है फायदेमंद जैसे विषय शामिल थे।

पहली बार कार्यक्रम की एंकरिंग करेंगे स्कूली बच्चे : पीएम की छात्रों के साथ होने वाली 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम की इस बार जो खासियत होंगी, उनमें इस बार दो स्कूली बच्चे एंकरिंग करते दिखेंगे। यह बच्चे केंद्रीय विद्यालय के होंगे। इनके चयन की फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले एंकरिंग करने के लिए किसी बड़े चेहरे को बुलाया जाता था। लेकिन इस बार बच्चों के कार्यक्रम में बच्चे ही एंकरिंग करते दिखेंगे।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (MAINS)
से कक्षा प्रारम्भ... 20 JAN 2020 | 11:30 AM 2:00 PM
GS (प्रारम्भिक परीक्षा)
राजव्यवस्था
POLITY (PT) 20 JAN 2020 | 6:15 PM 8:15 PM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58

16 द्वीपों की पहचान की गई है विकास के लिए अंडमान एवं निकोबार में केंद्र सरकार की ओर से। लक्षद्वीप में भी ऐसे 10 द्वीपों की पहचान की गई है। यहां पर्यटन को बढ़ावा और सीफूड और नारियल आधारित उत्पादों के निर्यात की सुविधा की पेशकश के जरिये सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 15 जनवरी 2020

मंत्रिमंडल के बहाने जातिगत समीकरण साध रही कांग्रेस

सियासत ▶ छग में आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने का भी प्रयास

तीन संभावित मंत्रियों में एक अगड़ी, दो पिछड़ी जाति के विधायक को शामिल करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खरमास का इंतजार खत्म होने को आया, लेकिन मंत्रियों के नाम पर लगा ग्रहण अभी दूर नहीं हुआ है। अगले एक-दो दिनों में इन नामों पर सहमति होने की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल, कांग्रेस इसी बहाने जातिगत समीकरण साधने में जुटी है। यह भी दुरुस्त करना चाहती है कि जहां से उसे सर्वाधिक वोट मिले, उन जातियों को निराश न होना पड़े। वर्तमान में अगड़ी जाति से एक और पिछड़ी जाति से दो विधायकों को मंत्री बनाने की संभावनाएं पार्टी स्तर पर दिख रही हैं। दूसरी ओर, पांच आदिवासी विधायक भी चुनाव जीतकर पहुंचे हैं और इस आधार पर एक और आदिवासी के लिए मंत्रिमंडल में व्यवस्था करने की मांग की जा रही है।

मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने कांग्रेस का लक्ष्य एक बार फिर जातिगत समीकरण को साधना और अगले चुनाव की तैयारियों को पुख्ता करना है। कांग्रेस के 16 विधायकों में आठ पिछड़ा वर्ग के हैं, पांच आदिवासी और तीन अगड़ी जातियों के। ऐसे में कांग्रेस अगड़ी जाति से एक विधायक को मंत्री बनाने की कवायद में है। सामान्य वर्ग से एक ब्राह्मण और दो राजपूत जीतकर पहुंचे हैं। ऐसे में राजपूतों का पलड़ा भारी दिख रहा है। दोनों उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के हैं। जातियों के बहाने कांग्रेस पांचों प्रमंडल को भी साधने के तरीके खोजेगी। फिलहाल संताल परगना और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रतिनिधित्व मंत्रालय में हो रहा है। कोल्हान और पलामू प्रमंडल के लिए भी पार्टी प्रयास करेगी। इसके बावजूद मुख्य लक्ष्य तो जातिगत समीकरण ही है। कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को भी मजबूत करना चाहती है। इस लिहाज से एक मंत्री तो बनाया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग एक और पद के लिए कैंप कर रहे हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस महिला विधायकों को भी मंत्रालय में जगह देना चाहती है।

अगड़ी जाति से दावेदार
1. बादल पत्रलेख
2. राजेंद्र सिंह

पिछड़ी जाति से दावेदार
1. दीपिका पांडे सिंह
2. बन्ना गुप्ता
3. इरफान अंसारी
4. अंबा साहू

अनुसूचित जनजाति से
1. राजेश कच्छप
2. नमन विक्सल कोंगाड़ी

17 को विधायकों से मिलेंगी सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड के सभी 16 विधायकों को 17 जनवरी को मिलने का समय दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव 16 को ही नई दिल्ली जा रहे हैं, जबकि कुछ विधायक अभी दिल्ली में ही हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद ही एक साथ मिलने के लिए सोनिया गांधी से समय की मांग की गई थी। एक बार फिर यही मांग की गई, जिस पर उन्होंने 17 जनवरी का समय दिया है।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का ईवीएम विरोध शुरू

नईदुनिया, भोपाल : कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग का विरोध कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह को मंगलवार को सौंपे ज्ञापन में कहा कि ईवीएम को लेकर कई भ्रांतियां हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम से हुए मतदान को लेकर अनुभव संतोषजनक नहीं रहे हैं। ज्ञापन में निकाय चुनाव मत पत्र से कराने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह मत पत्र का उपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैं। उधर, भाजपा ने कांग्रेस की मांग का विरोध किया है।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा देश हित में लिए जा रहे फैसलों से कांग्रेस बुरी तरह भयभीत है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसे वे पूरा नहीं कर पा रही है। जनता में सरकार को लेकर आक्रोश है, जिसे कांग्रेस जान गई है।

नगरीय निकाय चुनाव के आने वाले परिणामों से भयभीत होकर कांग्रेस ईवीएम की जगह मत पत्र से चुनाव चाहती है, ताकि वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव में धांधली कर सके।

महागठबंधन में अधिक सीटें लेने की रणनीति अपना रही कांग्रेस

एसए शाद, पटना

▶ बिहार में 243 सीटों पर तैयारी की पहल के पीछे राजद पर दबाव बनाना मकसद

प्रतीकात्मक

बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने लिए अधिक सीटें जुटाने की रणनीति पर अमल कर रही है। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर संगठन सुदृढ़ करने की पहल की है। मगर, इस पहल को महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद पर दबाव बनाने का प्रयास माना जा रहा है। मजबूत संगठन के नाम पर अधिक सीटों के लिए बेहतर सौदेबाजी हो सकती है। अधिक सीटों की चाहत इस कारण भी परवान चढ़ी है, क्योंकि जदयू के बाहर हो जाने के बाद महागठबंधन में कांग्रेस अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सभी सीटों पर संगठन मजबूत होने से अंततः महागठबंधन को ही होगा। हमारा प्रयास है कि मजबूत संगठन के बल पर हम अपने हिस्से की सीट तो जीते ही, साथ ही अन्य सीटों पर अपने सहयोगी दलों की जीत सुनिश्चित कराएं। अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना किसी दूसरी पार्टी को आंख दिखाना नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद और जदयू ने 101-101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 41 सीटें आई थी।

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जदयू से थोड़ा ही कम पार्टी का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में रहा था। जदयू की सीट जीतने की दर जहां 70.29 फीसद थी, वहीं कांग्रेस की दर 65.85 प्रतिशत आंकी गई थी। पार्टी अब जदयू के हिस्से की सीटों पर नजर गड़ाए है, हालांकि जदयू के बाहर होने के बाद महागठबंधन में तीन अन्य दल शामिल हो चुके हैं। इनमें रालोसपा, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। अधिक सीटों पर दावेदारी की रणनीति के तहत कांग्रेस ने आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी तेज कर दिए हैं। देखा जाए तो केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ पिछले एक डेढ़ माह में कांग्रेस से अधिक आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाए हैं। राजद ने पिछले माह केवल बिहार बंद का एक कार्यक्रम चलाया था। राजद वाम दलों के बंद में भी शरीक नहीं हुआ था, जबकि कांग्रेस ने राजद और वाम दलों द्वारा आहूत बंद में सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि पिछले चुनाव में खुद लालू प्रसाद ने राजद की कमान संभाल रखी थी। उनके फिलहाल जेल में रहने के कारण राजद पहले जैसी स्थिति में नहीं है।

बंगाल में पहली बार विवि के कुलपतियों ने बनाया संगठन

जागरण संवाददाता, कोलकाता: सियासी गतिविधियों व हस्तक्षेप के लिए मशहूर बंगाल के शिक्षा कैंपसों में मंगलवार को एक और संगठन का नाम जुड़ गया। अब तक स्कूलों, व कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में छात्र, शिक्षक और प्रोफेसरों के संगठन थे। परंतु, पहली बार बंगाल में राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अपना संगठन बना लिया है। संगठन का नाम पश्चिम बंगाल कुलपति परिषद रखा गया है। संगठन का अध्यक्ष जादवपुर विवि के कुलपति सुरंजन दास और सचिव उत्तर बंगाल विवि के कुलपति सुविरेश भट्टाचार्य को बनाया गया है।

मंगलवार को कुलपतियों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संगठन ने कहा कि काफी सोच विचार करने के बाद हमने पश्चिम बंगाल कुलपति परिषद का गठन किया है। यह परिषद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का काम करेगा। इसके साथ ही यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा। राज्य सरकार के इशारे पर विवि कार्य कर रहा है संबंधित राज्यपाल की टिप्पणी पर वीसी सुविरेश भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल के बयान पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उन्होंने किस आधार पर यह बयान दिया ये वहीं जानते हैं। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं और हम पर राज्य सरकार का कोई दबाव नहीं है।

न्यूज गैलरी

हाई कोर्ट में मीसाबंदियों ने दायर कीं 40 याचिकाएं

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में पेंशन रोकने के फैसले के खिलाफ मीसाबंदियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग 40 याचिका दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं ने पेंशन रोके जाने के कारण भरण पोषण की समस्या का हवाला देते हुए पेंशन व्यवस्था को नियमित रखने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा के बाद जेल में बंद किए गए राजनीतिक बंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देते हुए पेंशन व्यवस्था लागू की थी। मीसाबंदियों को पेंशन के लिए दो श्रेणी बनाई गई थी। छह महीने से कम जेल में रहने वाले बंदियों को प्रति महीने 15 हजार रुपये व छह महीने से ज्यादा जेल में बंद रहने वाले बंदियों को प्रति महीने 25 हजार रुपये पेंशन की व्यवस्था शुरू की थी। ऐसे मीसाबंदी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी पत्नी को आधी राशि का भुगतान किया जा रहा था। (नईदुनिया)

चारा घोटाला मामले में लालू का कल दर्ज होगा बयान

रांची : रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 16 जनवरी (गुरुवार) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद का बयान रांची स्थित सीबीआइ अदालत में दर्ज होगा। मंगलवार को सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद को अदालत में पेश करने का आदेश निर्गत किया है। डोरंडा कोषागार से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद सहित 111 आरोपित ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इसमें 109 आरोपितों का बयान दर्ज किया जा चुका है। लालू व एक पशु चिकित्सक डॉ. शिवनंदन प्रसाद का बयान लेना बाकी है। शिवनंदन को भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन बीमार होने के कारण बयान दर्ज कराने वह नहीं आ सके हैं। (जासं)

गुमशुदा के पोस्टर बोले सनी देयोल, बेतुकी बातें न करें

पठानकोट: पठानकोट में गुमशुदगी के पंफ्लेट लगने के बाद सांसद सनी देयोल ने सोमवार को फेसबुक अकाउंट पर वीडियो जारी किया। लोहड़ी पर्व की बधाई के बहाने सांसद ने विरोधियों को बेतुकी बातें न करने की नसीहत दे दी। सांसद सनी ने सलाह दी कि विरोधी उनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वह पठानकोट का विकास करने के लिए आए हैं। सभी के साथ मिलकर इलाके को आगे बढ़ाएंगे। (जासं)

पंजाब में बाजवा की कैप्टन के खिलाफ खुली बगावत

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

प्रताप सिंह बाजवा। फाइल

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल

पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यसभा सदस्य व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। सभी विधायकों और पार्टी हाईकमान से कैप्टन से पिंड छुड़ाने संबंधी बाजवा के बयान को लेकर पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के पक्ष में उतर आई है। कैबिनेट में मंत्रियों के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत में सभी ने एक आवाज में बाजवा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग की है। दूसरी तरफ बाजवा ने कहा है कि वह ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं।

मंत्रियों व पार्टी के सीनियर नेताओं ने कहा कि बाजवा ने सार्वजनिक प्लेटफार्म प्रयोग करते हुए कैप्टन के खिलाफ बयान दिया है। अगर बाजवा को किसी बात से परेशानी है तो वह पार्टी प्लेटफार्म पर अपनी बात रखें। वह अब अपनी आलोचना में इस हद तक जा चुके हैं कि उन्होंने पंजाब सरकार के नेतृत्व को चुनौती देनी शुरू कर दी है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी बनती है।

मंत्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि बाजवा शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। वह भी उस समय जब राज्य में विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन है और कांग्रेस को उससे कोई चुनौती नहीं है। इस तरह बगावत के पर अगर शुरू में ही न कुतरे गए तो इसका पार्टी में बहुत गलत संदेश जाएगा। इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि बाजवा जैसे नेताओं का इस तरह का व्यवहार पार्टी को कमजोर बना देगा। चरनजीत चन्नी ने कहा कि कोई कुछ भी बोल दे, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रह्म मोहिंदरा ने कैप्टन से कहा कि वह इस मामले में पार्टी हाई कमान से बात करें।

मनप्रीत बादल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि असंतोष ने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। जब हम इकट्ठे थे तो हमने पंजाब में कई सीटें जीतीं। एकता किसी भी कीमत पर खंडित नहीं होनी चाहिए। ओम प्रकाश सोनी, साधू सिंह धर्मसोत और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने भी बाजवा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

मैं पंजाब की जनता के प्रति जवाबदेह : बाजवा

कैबिनेट मंत्रियों द्वारा पार्टी से निकालने की मांग पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मेरी जवाबदेही पंजाब के लोगों के प्रति है। मुझे इस तरह की धमकियों से दबाया नहीं जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे आरोपों का जवाब देने की हिम्मत तो जुटा नहीं सके, अलबत्ता उन्हें अपने मंत्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं कैप्टन को बहस की खुली चुनौती देता हूं।

बाजवा ने कहा था, कैप्टन को हटाएं

प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन से वादे पूरे करने को कहा था। साथ ही विधायकों और पार्टी हाईकमान से कहा था कि वह ऐसे मुख्यमंत्री को हटाएं जो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने जितने वादे किए थे उन्हें पूरा करने में तो कैप्टन को एक हजार साल लगेंगे।

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी साधा था कैप्टन पर निशाना

पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बीते लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा था। बठिंडा में रैली को संबोधित करते हुए बिना कैप्टन का नाम लिए कहा था कि बादलों से मिलीभगत करने वालों को भी ठोक दें। इसके बाद कैप्टन ने सिद्धू का विभाग बदल दिया था जिसका नतीजा यह हुआ कि सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

लखनऊ और नोएडा को अतिरिक्त पुलिस बल भी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पुलिस कमिश्नर प्रणाली
- यातायात पुलिस में भी की जाएगी अतिरिक्त तैनाती
- लखनऊ को मिले 150 से अधिक निरीक्षक व उपनिरीक्षक

लखनऊ शहर व नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यातायात पुलिस की भी अतिरिक्त तैनाती की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली में दोनों शहरों में अतिरिक्त आइपीएस व पीपीएस अधिकारियों की तैनाती के साथ ही निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी पदों पर भी अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। दरअसल, थानों व अधिकारियों की संख्या बढ़ने से यहां कार्यालय स्टाफ से लेकर वाहन चालकों तक की अतिरिक्त जरूरत होगी। नई प्रणाली पर खरा उतरने के लिए पुलिस व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी अतिरिक्त बल तैनात किया जा रहा है। यह पुलिस बल जोन स्तर से आवंटित है। लखनऊ में 150 से अधिक अतिरिक्त निरीक्षक व उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है। अभी और तैनाती की जाएगी। लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडेय का कहना है कि अतिरिक्त आवंटित बल की जानकारी अभी उन्हें नहीं है। जरूरत के अनुरूप बल मांगा गया है। दूसरी ओर नोएडा में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

कमिश्नर प्रणाली के लागू होने के साथ ही पुलिस को मिले अधिकारों में अब वह कई मामलों में सीधे अपील भी कर सकेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब तक किसी मामले में आरोपित के कोर्ट से दोषमुक्त होने की स्थिति में पुलिस को उसके खिलाफ कोर्ट में अपील करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब पुलिस को यदि लगता है कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो वह ऐसे मामलों में पुलिस कमिश्नर की अनुमति लेकर सीधे अपील कर सकेगी।

राजद में मिलिट्री अनुशासन नहीं चलेगा खुद को अनुशासित रखिए : रघुवंश

राज्य ब्यूरो, पटना

▶ बगैर नाम लिए राजद बिहार प्रदेश अध्यक्ष पर खूब भड़के रघुवंश सिंह

रघुवंश प्रसाद सिंह। फाइल

राजद के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह मंगलवार को राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर खूब भड़के। अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राजद में मिलिट्री अनुशासन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम तो आरंभ से ही नीतीश कुमार को अपने साथ बुला रहे हैं। अगर वह भाजपा छोड़कर आ जाएं तो उनके लिए हम अपनी पार्टी में झगड़ लें। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के काम के अंदाज पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को पत्र लिखा था।

रघुवंश ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजद के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यह सिस्टम ही रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहता है पर इसके लिए सहयोगी दल का समर्थन जरूरी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष की यह बात गलत है कि जिन्हें गठबंधन में रहना है रहें और जिन्हें जाना है जाएं। यह भाषा ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। केवल राजद के चाहने से ही कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या?

उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में उस पत्र को भी जारी किया जिसे उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को लिखा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बेकार कर दिया गया है। ऐसे में काफी मुश्किल आएगी। जरूरत इस बात की है कि अभी से उन्हें सक्रिय किया जाए। हम लड़ने के लिए हैं किसी की बात मानने के लिए नहीं। इनफैंट्री के सिपाही हैं। मंगलवार को रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने आवास पर चूड़ा-दही का भोज भी दिया। भोज में राजद के पूर्व अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे सहित राजद के कई अन्य नेता भी शामिल हुए।

जब इतने वरिष्ठ नेता बोल रहे तो कोई न कोई अंतर्विरोध जरूर है : वशिष्ठ

जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से राजद में चल रहे इस घमासान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी दल के आंतरिक मामले में वह कुछ अधिक नहीं बोलेंगे। वहीं अगर कोई वरिष्ठ नेता इतना बोल रहा तो यह सही है कि कहीं न कहीं अंतर्विरोध जरूर है।

एक दिन के लिए कुर्सी....

उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) में मंगलवार को एक नया इतिहास बना। विश्वविद्यालय को पहली बार एक दिन के लिए कार्यवाहक कुलपति मिला। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इविवि प्रशासन के बीच दिनभर चले मंथन के बाद वरिष्ठता के आधार पर कला संकाय के डीन प्रोफेसर पीके साहू (बाएं) को देर शाम कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया। रात 8:50 बजे रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल (दाएं) ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। उल्लेखनीय है कि प्रो. साहू बुधवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद इविवि को स्थायी कुलपति मिलने तक एक बार फिर से नया कार्यवाहक कुलपति मिलेगा। गत 31 दिसंबर को विवादों में घिरे तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में प्रो. केएस मिश्र को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया। प्रो. मिश्र मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर रहे कला संकाय के अध्यक्ष प्रो. पीके साहू को दायित्व सौंपा गया। शरद मालवीय

विवाद जारी

दुष्यंत को टक्कर देने के लिए विज को बनाया गया था गृहमंत्री, खुद अनिल विज ने जाहिर की सब कुछ ठीक नहीं होने की आशंका

सीआइडी छिनी तो गृह मंत्रालय छोड़ सकते हैं अनिल विज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

> मेरे सामने ऐसी सूचनाएं आई कि हरियाणा में सीआइडी को गृह विभाग से वापस लेने की तैयारी अधिकारी कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा होते हैं। उन्हें किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं होती और न ही है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सिर्फ आदेश देकर कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी विभाग का विभाजन कर सकते हैं। मुझे इस पूरे मामले में हो रही भागमभाग पर संदेह है कि इसके पीछे जरूर कोई और मंशा है।
> – अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा

अनिल विज। फाइल

हरियाणा सरकार में सीआइडी (क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट) को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीआइडी मुख्यमंत्री के पास रहेगी अथवा गृहमंत्री अनिल विज को ही रिपोर्ट करती रहेगी, इसे लेकर सरकार में घमासान के आसार हैं। सीआइडी को गृह विभाग से अलग कर नया डिपार्टमेंट बनाने की दिशा में जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में काम चल रहा है, वहीं ऐसे भी संकेत मिल रहे कि यदि सीआइडी को गृह विभाग से अलग कर दिया गया तो अनिल विज गृह मंत्रालय छोड़ सकते हैं। खुद विज ने आशंका जाहिर की है कि सीआइडी को गृह विभाग से अलग करने की मंशा के पीछे सब ठीक नहीं माना जा सकता।

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सीआइडी को गृह विभाग से अलग करने की अंदरूनी तैयारी चल रही है। ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पास कर विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस ड्राफ्ट के तहत सीआइडी को गृह विभाग से कानूनी तौर पर अलग कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सीआइडी मुख्यमंत्री के पास रहेगी और गृह विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। अभी तक गृह मंत्री अनिल विज प्रबल दावा कर रहे हैं कि सीआइडी गृह विभाग का हिस्सा है और उसके मंत्री वे ही हैं। विज को यह कहने की नौबत इसलिए आन पड़ी, क्योंकि पिछले दिनों सीआइडी को अलग विभाग मानते हुए इसे हरियाणा सरकार की साइट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विभागों में दर्शा दिया गया था। जब ऐसा हुआ तो विज ने कहा था कि यदि सीआइडी को अलग करना है तो इसके लिए विधानसभा में बिल पेश करना होगा।

अब सवाल उठता है कि सीआइडी को लेकर सरकार में तनातनी की नौबत क्यों आई? दरअसल, गृह मंत्री के नाते अनिल विज ने सीआइडी प्रमुख से वह रिपोर्ट तलब कर ली थी, जो विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की स्थिति के आधार पर तैयार की गई थी। कई दिनों तक जब यह रिपोर्ट नहीं आई तो विज ने स्पष्टीकरण मांग लिया। रिपोर्ट मिलने के बाद अगले दिन ही विज ने उन लोगों की सूची भी तलब कर ली, जिनके फोन टेप किए जाते हैं। इस रिपोर्ट के मांगने पर सरकार में हड़कंप मच गया। इसके बाद गृह मंत्री से सीआइडी को वापस लेने का खाका बुना जाने लगा। अब जबकि सीआइडी को गृह विभाग से अलग करने का ड्राफ्ट तैयार करने की खबरें आ रही हैं तो गृह मंत्री विज के नजदीकी लोगों ने संकेत दिए हैं कि यदि ऐसा हुआ तो विज गृह मंत्रालय भी छोड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह स्थिति पूरी सरकार को असहज करने वाली हो सकती है। विज की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें पार्टी हाईकमान के निर्देश पर गृह मंत्री बनाया गया था। अनिल विज को गृह मंत्री बनाए जाने के पीछे पार्टी नेतृत्व की यह मंशा थी कि दुष्यंत चौटाला के मुकाबले उन्हें खड़ा किया जा सके।

शिवाजी के वंशज ने शिवसेना और राकांपा पर तंज किया

पुस्तक विवाद
- भाजपा विधायक भोसले बोले-ऐसी तुलना तो पीएम मोदी को भी पसंद नहीं
- शिवसेना से पूछा-महाशिव अघाड़ी से शिव शब्द क्यों हटा दिया

पुणे, प्रेट्र : छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और भाजपा नेता उदयनराजे भोसले ने कहा कि विश्व में किसी की भी तुलना 17वीं शताब्दी के मराठा राजा से नहीं की जा सकती है। उन्होंने शिवसेना और राकांपा की खिंचाई करते हुए कहा कि शिवसेना को अपने नाम से शिव हटा लेना चाहिए और उसका नाम ठाकरे सेना कर देना चाहिए। जब आप अपना नाम बदलेंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आपके पीछे खड़े रहते हैं। उन्होंने राकांपा प्रमुख शरद पवार का नाम लिए बगैर उन पर तंज करते हुए कहा कि केवल शिवाजी महाराज को ही 'जनता राजा' बुलाया जा सकता है।

विवादास्पद पुस्तक 'आज के शिवाजी : नरेंद्र मोदी' को वापस लिए जाने की घोषणा का समर्थन करते हुए पिछले साल ही राकांपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भोसले ने पूछा कि हर बार वंशजों से हस्तियों के बारे में पूछने को कहा जाता है। लेकिन क्या शिवसेना ने यह नाम इस्तेमाल करते हुए वंशजों से तब पूछा था। उल्लेखनीय है कि उदयन राजे भोसले शिवसेना की सोमवार की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे। राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले उद्धव ठाकरे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महाशिव अघाड़ी से शिव शब्द क्यों हटा दिया गया। उन्होंने अपनी सुविधानुसार शिवाजी महाराज का नाम इस्तेमाल करने पर राजनीतिक दलों की आलोचना की।

19 जिलों में रहने वाले 40 हजार अवैध प्रवासियों की जानकारी जुटाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश में अब तक। इसकी सूची यूपी सरकार ने केंद्र को भी भेज दी है। इसी के साथ उप्र देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक प्रवासियों की जानकारी गृह मंत्रालय को भेजी है।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने यहां तक कह दिया कि साक्षर लोगों को कैसे शिक्षित होने की जरूरत है, यह उसका सबसे सटीक उदाहरण है

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने विरोध के बाद सीएए के बयान पर दी सफाई

नई दिल्ली, एजेंसियां

माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्य नडेला ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वह खराब है और दुखद है। उनके इस बयान का भारत में तीखा विरोध हुआ। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने यहां तक कह दिया कि साक्षर लोगों को कैसे शिक्षित होने की जरूरत है, यह उसका सबसे सटीक उदाहरण है। विरोध बढ़ने पर नडेला ने एक बयान जारी कर सफाई भी दी।

सत्य नडेला। फाइल

माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में शनिवार को सत्य नडेला (52) संपादकों से मुखातिब थे। इस दौरान न्यूयॉर्क स्थित 'बजफीड' ने उनसे सीएए के बारे में उनके विचार पूछे साथ ही सवाल किया कि क्या डाटा के इस्तेमाल के मामले में वह भारत सरकार के साथ काम करने को लेकर चिंतित हैं? जवाब में नडेला ने कहा, 'मैं भारत में पला-बढ़ा हूं और मुझे अपनी विरासत और उस शहर की संस्कृति पर गर्व है जहां मैं पला-बढ़ा हूं। मुझे हमेशा लगता है कि वह पलने-बढ़ने की शानदार जगह है, हम क्रिसमस और दिवाली मनाते थे। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है गलत है। खासतौर पर उसके लिए जो वहां पला-बढ़ा है। मुझे लगता है और अब जानकार होने के नाते साफ कहूं तो मुझे दो शानदार अमेरिकी चीजों ने बनाया है, पहली जहां मेरी परवरिश हो रही थी वहां तक उसकी तकनीक की पहुंच और इसकी आव्रजन नीति। मेरे जैसे व्यक्ति की कहानी इस जैसे देश में ही संभव हो पा रही है।' हैदराबाद में जन्मे नडेला ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह सिर्फ बुरा है... अगर मैं कुछ देखना चाहता हूं तो यह कि भारत आया एक बांग्लादेशी प्रवासी भारत में अगले यूनीकॉर्न की स्थापना करे या इंफोसिस का सीईओ बने, यह आकांक्षा होनी चाहिए। अमेरिका में मेरे साथ जैसा हुआ, मुझे उम्मीद है कि भारत में भी वैसा ही होगा।'

'बजफीड' को दिए इस जवाब पर भारत में तीखा विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने माइक्रोसाफ्ट के सीईओ नडेला पर जमकर तंज कसे। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, 'सीएए के लिए सटीक वजह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना का शिकार होकर आए अल्पसंख्यकों को अवसर मुहैया कराना है। अमेरिका में यजीदी की बजाय सीरियाई मुसलमानों को अवसर देने के बारे में वह क्या सोचते हैं?'

बाद में सत्य नडेला ने अलग से एक बयान जारी कर स्पष्ट किया, 'प्रत्येक देश अपनी सीमाओं को परिभाषित, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण और आव्रजन नीति का निर्धारण करेगा और करना भी चाहिए। और लोकतंत्र में लोग और उनकी सरकारें इन्हीं दायरे में इस पर चर्चा और बहस करेंगे। मुझे बनाने में मेरी भारतीय विरासत, बहुसांस्कृतिक भारत में परवरिश और प्रवासी के रूप में अमेरिका के मेरे अनुभव का योगदान है। भारत के बारे में मेरी उम्मीद यही है कि वहां प्रवासी एक समृद्ध स्टार्टअप की आकांक्षा रख सकें या बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन का नेतृत्व कर सकें ताकि भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो सके।' उनके इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि नडेला ने स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने जो कहा है सरकार वही कर रही है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

न्यूज गैलरी

दिलीप घोष ने कहा-बंगाल देशद्रोहियों का सबसे बड़ा गढ़

दिलीप घोष। फाइल

कोलकाता : बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर एक विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने बंगाल को देशद्रोहियों का सबसे बड़ा गढ़ बताया है। घोष ने मंगलवार खड़गपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित सभा में यह बयानबाजी की। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को गोली मारने के बयान के एक दिन बाद ही उन्होंने फिर एक विवादित बयान दिया था। इसके पहले उन्होंने नदिया जिले के रानाघाट में सभा के दौरान सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के बारे में कहा था कि 'यूपी, असम, कर्नाटक में हमारी सरकार ने इन लोगों को सबक सिखाया है।' उन्होंने कहा था 'दीदी (ममता बनर्जी) की पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नष्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे उनके वोटर हैं।' प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर राज्य की राजनीति में बहस छिड़ी हुई है। भाजपा के कुछ नेता भी इस तरह के बयान को उचित नहीं ठहराते। केंद्रीय राज्यमंत्री और आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के इस बयान को अनुचित बताया है। दलीप घोष के गोली मारने वाले बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए नदिया जिला तृणमूल महासचिव कृष्णेंदु बनर्जी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की ओर से भी उनके बयान को लेकर एफआइआर दर्ज कराई गई है। (जासं)

सीएए, एनआरसी व एनपीआर पर प्रस्ताव लाएगी पंजाब सरकार

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल

चंडीगढ़ : नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए), नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) पर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। सदन में जो सहमति होगी, उसके आधार पर ही इसे लागू या रद किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने इन सभी को गैर संवैधानिक व समाज को बांटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह देश के सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुंचाने और संविधान की नींव को आघात पहुंचाने वाला है। कैबिनेट ने इस पर सदन में बहस करवाने की बात की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विचार पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई कि सरकार सदन की सिफारिश के अनुसार ही कदम उठाएगी। कानूनी जानकारी देने के लिए पंजाब के महाधिवक्ता अतुल नंदा भी बैठक में उपस्थित थे। (राब्यू)

प्रधानमंत्री ने कहा ▸ भारत तेज गति से विकास कर रहा, खत्म हो रही हैं वर्षों से लंबित समस्याएं

'देश अस्थिर करने की हो रही कोशिश'

सरकार ने दशकों पुरानी समस्याएं खत्म करने का मिशन बनाया

चेन्नई, प्रेट्र : देश में कई स्थानों पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है। प्रायः असंभव समझी जाने वाली बातें अब हकीकत बन चुकी हैं। लेकिन अपने निहित स्वार्थों के लिए कुछ लोग देश को गुमराह और अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।

चेन्नई की एक तमिल पत्रिका के मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों से देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ने में मदद मिली है। कांग्रेस पर अपरोक्ष प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि पेंडुलम क्या होता है। यहां से वहां घूमता रहता है और हर चीज अस्थिर रखता है। इससे कई परेशानियां बढ़ती हैं और फिर वह इसे सुलझाने का ढोंग करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चीजें बदल रही हैं। हमारी सरकार ने दशकों से चली आ रही समस्याओं को खत्म करने का मिशन बनाया है। ऐसी लंबित समस्याएं जिनका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल

हल निकाला जा चुका है, उनमें अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना आदि शामिल हैं। भारत जैसे आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो बातें असंभव मानी जाती थीं। उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी समूह इन बदलावों को पचा नहीं पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'तुगलक' जैसी पत्रिकाओं की ऐसे हालात में भूमिका और बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पत्रिका के संस्थापक दिवंगत संपादक चो एस. रामास्वामी ने जिम्मा लिया होता। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और नौकरी में दस फीसद कोटा देने का भी रास्ता साफ किया है। आयुष्मान भारत योजना के जरिये सस्ता स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से हमने कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है।

पाकिस्तान को अब सता रहा गुलाम कश्मीर हाथ से जाने का डर : योगी

रमण शुक्ला, गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वालों के तार 'दूर' से जुड़े हैं। कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान को अब गुलाम कश्मीर हाथ से जाने का डर लग रहा है। उन्होंने मंगलवार को गया के गांधी मैदान में सीएए के समर्थन में बिहार भाजपा की ओर आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, न कि छीनने के लिए। इसलिए इससे किसी भी जाति, धर्म और समाज के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता विरोध करने वाली ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। नए कानून को लेकर विपक्षी दल जनता को साजिशन गुमराह कर रहे।

नए भारत के निर्माण को अपरिहार्य है सीएए : अपार जनसमूह में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण की कड़ी में यह कानून अपरिहार्य है। इसका विरोध करने वाले देश के साथ पाप कर रहे हैं। मैं नागरिकों से एकजुट होकर नए कानून के समर्थन की अपील करता हूं। बकौल योगी, देश को नागरिकता संशोधन कानून देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जगह-जगह अभिनंदन होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश विरोध किया जा रहा है। मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल भी मौजूद रहे।

घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे : योगी ने कहा कि सीएए के जरिए देश से रोहिंग्या व घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। शरणार्थियों को यहां की नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के पहले कानून मंत्री योगेंद्रनाथ मंडल इस्तीफा देकर कोलकाता में निर्वासित जीवन के लिए विवश हुए। 1964 तक गुमनामी की जिंदगी जीने के बाद वहीं उनकी मौत हो गई। योगी ने कहा, पाकिस्तान से हिंदुओं को मार भगाया गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी महज एक फीसद रह गई है, जबकि 1947 में 23 फीसद थी।

हिंदुस्तान में मुस्लिमों को हर तरह की आजादी : सुशील मोदी

जागरण संवाददाता, गया

योगी आदित्यनाथ की जनसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम को हर तरह की आजादी है। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बिहार या देशभर में कभी नहीं रोका गया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के ईसाई रहते हुए भी हिंदुस्तान ने उन्हें स्वीकार किया। यह भारत की धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि सीएए दूसरे देशों में वैसे प्रताड़ित और शोषित अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बना है, जिन्हें पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान) से निकाला गया है। उन देशों से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई समुदाय वाले) को उदार हृदय से स्वीकार करने की व्यवस्था है। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्हें विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से निष्कासित होकर जो हिंदू भारत की शरण में आए हैं, उनमें अधिसंख्य अनुसूचित जाति-जनजाति परिवार के हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से पूछा कि जो भारत की नागरिकता से 70 साल तक वंचित रहे थे, उन्हें नागरिकता देकर मोदी सरकार ने कौन सा पाप किया है। गरीबों और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोगों का लाभ चाहते हैं, तो सीएए का विरोध करना बंद करें।

सुशील मोदी। फाइल

जायसवाल ने कहा-यह रोहिंग्या या घुसपैठियों का हिंदुस्तान नहीं : भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती का खामियाजा पूरा देश 70 साल से भुगत रहा है। उस वक्त पाकिस्तान से आए हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे दी जाती तो आज परेशानी उठानी नहीं पड़ती। यह हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का देश है। रोहिंग्या या पड़ोसी देशों से आने वाले घुसपैठियों का हिंदुस्तान नहीं है। यह देश भारत माता को मानने वालों का है।

योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करते हुए डॉ. जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान से पांच लाख शरणार्थी भारत आए थे। वे पिछले कई दशकों से अपने ही देश में तंबू में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सीएए पर पूरी तरह साफ है जदयू का रुख : संजय

राज्य ब्यूरो, पटना

जदयू ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन पर अपने स्टैंड को फिर से दोहराया है। जदयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने यह स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएए पर चर्चा की बात कही थी। चर्चा का आशय यह नहीं था कि वह इस पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। उनके वक्तव्य को गलत तरीके से समझा जा रहा। जदयू ने संसद में इस कानून के समर्थन में वोट किया था। जदयू के उक्त स्टैंड में किसी भी तरह के बदलाव की कोई बात ही नहीं है। एनआरसी के मसले पर तो नीतीश कुमार ने पहले ही यह कह रखा है कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजय झा ने कहा कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में सीएए पर दिए गए वक्तव्य का यह आशय निकाल लिया कि वह इस पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। यह बात निराधार है। नीतीश कुमार ने केवल यह कहा था कि वह सीएए पर चर्चा को तैयार हैं।

संजय ने कहा कि जिस वक्त मुख्यमंत्री का यह संबोधन विधानसभा में हो रहा था वह स्वयं सदन के भीतर थे। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी सहमति से ही पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया है। जदयू को इस बात का पूरा इल्म है कि सीएए से किसी तरह की कोई समस्या

स्पष्ट राय

- जदयू नेता ने कहा, एनआरसी के बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
- मुख्यमंत्री ने केवल यह कहा था कि वह सीएए पर चर्चा को तैयार हैं

संजय झा। फाइल

नहीं होने वाली है। इसका उद्देश्य वैसे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है जो किसी वजहों से इससे वंचित हैं। मुख्यमंत्री तो विपक्ष की उस मांग पर जवाब भर दे रहे थे, जिसके तहत यह कहा गया था कि वह इस पर चर्चा करें। स्पष्ट तौर पर यह समझा जाना चाहिए कि चर्चा के लिए तैयार रहने का वक्तव्य का यह मतलब नहीं होता कि पार्टी अपने पुराने स्टैंड से हट सकती है। उन्होंने साफ कहा कि सीसीए पर पार्टी राजग के साथ है और उसका रुख स्पष्ट है। वह किसी भी तरह से इस मुद्दे को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अलग जाने को तैयार नहीं हैं।

याचिका में कहा, केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

केरल सरकार ने अपने सूट में कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 256 राज्य को बाध्य करता है कि वह सीएए को लागू करे और पासपोर्ट व फारेन आर्डर एमेंडमेंट को लागू करे, जो कि मूलतः मनमाना गलत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। केरल ने कहा है कि उसका केंद्र के साथ कानून को लागू करने के कानूनी अधिकार और राज्य के निवासियों के कानूनी व मौलिक अधिकारों को लेकर विवाद है। इसीलिए यह केस दाखिल किया है। मूल कानून में अवैध घुसपैठियों को नागरिकता से बाहर रखा गया था लेकिन सीएए में प्रावधान जोड़ा गया है जिससे भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को छूट दी गई है।

केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि नए कानून में धर्म और मूल देश को आधार माना गया है जबकि तय कानूनी सिद्धांत में धर्म को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसमें म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के लोगों को शामिल नहीं किया गया। इस कानून में श्रीलंका के तमिल, नेपाल के हिंदू मधेसी को भी शामिल नहीं किया गया। न ही इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अहमदिया, शिया और हजारा को शामिल नहीं किया गया है। अगर कानून का उद्देश्य धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को मदद देना है तो इन देशों में ये वर्ग भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं।

राहुल को इटालियन और वामपंथियों को चीनी में समझाना पड़ेगा सीएए : बाबुल सुप्रियो

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में देश के ज्यादातर राज्यों में लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस दौरान पदयात्रा, तिरंगा यात्रा और रैलियों के साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता और कार्यकर्ता न केवल समर्थन में आयोजन कर रहे हैं बल्कि विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों को आइना भी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भिलाई में केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इटालियन और वामपंथियों को चीनी भाषा में सीएए के बारे में समझाना चाहिए। उधर, मध्य प्रदेश में भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा, पंजाब में जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएए को लेकर विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला

भिलाई में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ बाबुल: सीएए को लेकर चल रहे आंदोलन पर अपनी बात रखने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो मंगलवार को भिलाई पहुंचे। यहां वे नंदिनी रोड से हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी तक आयोजित तिरंगा रैली में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस, वामपंथी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर सीएए को लेकर झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएए का कानून इतना सरल है फिर भी ये विपक्षियों को समझ नहीं आ रहा है।

छत्तीसगढ़ के भिलाई में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करते केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। नईदुनिया

लग रहा है कि राहुल गांधी को इटालियन और वामपंथियों को चीनी भाषा में सीएए समझाना पड़ेगा।

राजनीति के लिए खूनखराबा करने वाली पार्टी है कांग्रेस: झा: मध्य प्रदेश के खंडवा में भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि सीएए का कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार कि या जा रहा है। विरोध तो वे लोग करते हैं, जिनकी जमीन खिसक गई हो। देश को लहूलुहान करने वाली घटनाओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए देश में खून खराबा कि या है। झा मंगलवार को मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

भ्रमित कर रही कांग्रेस: निर्मल सिंह: पंजाब में मंगलवार को सीएए के समर्थन में भाजपा और अन्य संगठनों ने जागरूकता रैलियां निकालीं। लुधियाना में जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाकर देश में अशांति फैलाना चाहती है, लेकिन उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा।

विपक्षी दलों ने साजिश के तहत मुस्लिमों को भड़काया : स्वामी: अयोध्या में उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएए को लेकर विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने साजिश के तहत मुस्लिम समाज को सीएए के खिलाफ भड़काया और किराये के गुंडों के जरिये हिंसा कराई।

नेपाल सीमा पर राष्ट्रवाद की अलख जगाएगा संघ

विजय द्विवेदी, बहराइच

नेपाल सीमा पर बढ़ती राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर है। सीमा के प्रत्येक गांव में संघ शाखा लगाकर राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मंसूबों को विफल करने की रणनीति बनाई है।

भारत-नेपाल सीमा से कई राष्ट्रविरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान के कराची के रहने वाले आइएसआइ के एजेंट मसरूर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सीमा पर बढ़ती राष्ट्र विरोधी हरकतों से चिंतित संघ ने सांगठनिक ढांचे को और मजबूत बनाने के साथ गांव-गांव में राष्ट्रवाद की अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। आरएसएस ने इस मुहिम को न्याय पंचायत स्तर तक शाखाएं लगाकर इनकी उप शाखाओं को गांव तक विस्तारित करने की कार्ययोजना तैयार की है। संघ सीमावर्ती जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत समेत अन्य जिलों के सीमावर्ती गांवों में शाखाओं का विस्तार करेगा।

तैयार किए जाएंगे स्वयंसेवक: आरएसएस के जिला प्रचारक राहुल कहते हैं कि संपूर्ण जिले में इस कार्ययोजना को गति देने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। वह कहते हैं कि नवाबगंज, मिहीपुरवा के हर न्याय पंचायत में दो-दो युवकों को एकत्र कर पाक्षिक दक्षता वर्ग लगाकर स्वयंसेवकों को तैयार किया जाएगा।

चार घंटे की होगी दक्षता वर्ग: संघ के सह जिला कार्यवाह पंकज गिरि बताते हैं कि चार घंटे के दक्षता वर्ग में स्वयंसेवकों को संस्कार व राष्ट्रहित सर्वोपरि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संघ की प्रक्रिया सीखकर स्वयंसेवक अपने गांव में शाखा लगाएंगे। समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने व शाखा में लाने का यह अभिनव प्रयोग चलता रहेगा।

राजनीतिक कार्यक्रमों से छात्रों को दूर रखने को महाराष्ट्र में बन सकता है नियम

मुंबई, प्रेट्र

महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू काडू ने मंगलवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र सरकार स्कूलों में आयोजित होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों से छात्रों को दूर रखने के लिए नियम बना सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा महिला व बाल विकास राज्यमंत्री काडू ने मीडिया से कहा, 'स्कूली छात्रों को राजनीतिक मुद्दों में नहीं लपेटा जाना चाहिए। कोई ऐसा करता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए नियम बनाएंगे।' इससे पहले दिन में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कहा था कि राज्य के सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रखने को कहा गया है। भाजपा इस नोटिस की आलोचना कर रही है।

- महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू काडू का सख्त रुख
- कहा, स्कूली छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल कराने वालों पर होगी कार्रवाई
- स्कूलों को नोटिस भेजकर छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा गया

स्कूली छात्रों के सीएए जागरूकता कार्यक्रम पर सोमैया ने साधी चुप्पी

सीएए पर जागरूकता कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को शामिल किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल को पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने टाल दिया। एक टीवी चैनल के सवालों पर उन्होंने 27 बार एक ही बात कही, 'मैंने आपको जवाब दे दिया है।' सोमैया ने श्री दयानंद बालक, बालिका विद्यालय व जूनियर कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने संस्थान की प्रबंध समिति से मुलाकात कर राज्य की शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार की तरफ से दिए गए नोटिस की आलोचना की।

उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी को श्री दयानंद बालक, बालिका विद्यालय व जूनियर कॉलेज के बगल में स्थित सार्वजनिक मैदान में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्कूल का संचालन आर्य समाज करता है। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेताओं ने कक्षा 8-10 तथा इंटरमीडिएट के छात्रों को सीएए के बारे में जानकारी दी थी। इसका उद्देश्य सीएए को लेकर फैले भ्रम को दूर करना था और लोगों को इसकी सही जानकारी देनी थी।

जम्मू-कश्मीर से हट सकता एम फार्म : राम माधव

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

भाजपा के केंद्रीय महासचिव व जम्मू-कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने कहा कि केंद्र सरकार नए साल में कश्मीरी पंडितों को एक और सौगात दे सकती है। एम फार्म को कश्मीर से हटाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों को हर चुनाव में यह फार्म भरना अनिवार्य है। इसे भरने के बाद ही मतदान किया जा सकता है। वह मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा 'नए भारत के निर्माण में अनुच्छेद-370, सीएए और एनआरसी की भूमिका' विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कश्मीरी पंडितों के कश्मीर में बसाने के संबंध में उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को उनके जीने के मौलिक अधिकारों और सम्मान के साथ वहां बसाया जाएगा। इसके लिए प्रयास जारी हैं और बहुत जल्द ही उनको यह सम्मान उपलब्ध होगा। कहा कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार है, यही हम पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चाहते हैं। सीएए को लेकर कांग्रेस देश के लोगों को भ्रमित कर रही है। हम लोगों की भ्रांतियों को दूर करेंगे और उन्हें यह समझाएंगे की सीएए से भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। राम माधव ने कहा कि सीएए को लेकर भ्रम व झूठ फैला कर विपक्षी पार्टियां देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर हिंसा फैलाने की साजिश में लगी हैं।

क्या है एम फार्म : अभी घाटी से विस्थापित पंडितों को मतदान करने के लिए एम (माइग्रेटेड) फार्म भरना होता है। कश्मीरी पंडित इसके विरोध में हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सरकार के पास कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़ा सारा डाटा मौजूद है जिससे सरकार हर तरह की जानकारी जुटा सकती है।

60 हजार के आसपास अवैध ड्रोन भारत में हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की आकलन रिपोर्ट में यह आंकड़ा जारी किया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 15 जनवरी 2020

डीएसपी मामले की जांच एनआइए को सौंपी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- एक-दो दिन में देविंदर सिंह और तीनों आतंकियों को हिरासत में ले लेगी एनआइए,
- एनआइए ही कर रही है पिछले चार साल के दौरान पुलवामा में हुए मामलों की जांच

देविंदर सिंह। फाइल

आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह के मामले की जांच मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दी गई। एक-दो दिन में एनआइए निलंबित डीएसपी और उसके साथ पकड़े गए हिजबुल व लश्कर के तीनों आतंकियों को अपनी हिरासत में ले लेगी।

इस बीच, दूसरे दिन भी एनआइए और इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) के अधिकारियों ने देविंदर सिंह और हिजबुल कमांडर नवीद मुश्ताक उर्फ नवीद बाबू से पूछताछ जारी रखी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। हालांकि कश्मीर में पहले से ही मौजूद एनआइए के अधिकारी आरोपित देविंदर और आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं।

इन लोगों ने आरोपित डीएसपी को पकड़ने के अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की है। इंटेलीजेंस ब्यूरो के तीन सदस्यीय दल ने भी इनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि एनआइए को इस मामले की जांच से जुड़ी कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना है, उसके बाद ही देविंदर सिंह व उसके साथ पकड़े गए आतंकियों को उसके हवाले किया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एनआइए ही पुलवामा में बीते चार वर्षों के दौरान हुए विभिन्न आतंकी हमलों की जांच कर रही है। इनमें जनवरी 2017 में जिला पुलवामा पुलिस लाइन पर हुआ आतंकी हमला भी शामिल है। डीएसपी देविंदर सिंह इस हमले के समय पुलवामा में ही तैनात था। इसलिए यह मामला भी एनआइए को सौंपा गया है।

यह था मामला

जम्मू कश्मीर पुलिस ने गत शनिवार को दक्षिण कश्मीर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम में मीर बाजार में डीएसपी देविंदर सिंह को एक कार में दो आतंकियों और एक ओवरग्राउंड वर्कर संग पकड़ा था। आरोप है कि डीएसपी इन सभी को सुरक्षाबलों से बचाकर चंड़ीगढ़ पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह पहले भी इस तरह आतंकियों की मदद कर चुका है और बदले में मोटी रकम लेता था।

केंद्र ने नहीं राज्य सरकार ने किया था देविंदर को सम्मानित

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि आतंकियों संग पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिला है। उसे सिर्फ जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा वर्ष 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी आरोपित डीएसपी देविंदर सिंह और उसके साथ पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के लिए मंगलवार को एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया। यह दल ऐसे पुराने मामलों की छानबीन करेगा, जिसमें देविंदर ने कथित तौर पर कभी आतंकियों का साथ दिया हो।

क्यों दिया था पुरस्कार : देविंदर सिंह को यह वीरता पुरस्कार 25/26 जनवरी को जिला पुलिस लाइन पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले से निपटने के लिए चलाए गए अभियान में उनकी भूमिका के आधार पर प्रदान किया गया था। उस समय वह जिला पुलवामा में डीएसपी जिला पुलिस लाइन पुलवामा के पद पर तैनात थे। गौरतलब है कि आरोपित डीएसपी के बारे में कुछ मीडिया संस्थानों ने दावा किया था कि उसे राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है।

राष्ट्रविरोधी का लिहाज नहीं करती जम्मू कश्मीर पुलिस : पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक समर्थ, अनुशासनबद्ध, राष्ट्रभक्त और पेशेवर संगठन है, जो किसी भी राष्ट्रविरोधी या असामाजिक तत्व, चाहे वह किसी से भी जुड़ा हो, उसका लिहाज नहीं करती। डीएसपी देविंदर सिंह को भी पुलिस ने ही पकड़ा और उसके खिलाफ भी संबंधित कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कानून सभी के लिए एक समान है।

'पुलिस ने डीएसपी को छिपाया नहीं बल्कि पकड़ा है'

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- उपराज्यपाल के सलाहकार ने कहा- ब्लैक शीप है डीएसपी देविंदर

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार एवं जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक फारूक खान ने मंगलवार को दो आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह को ब्लैक शीप बताया।

उन्होंने कहा कि उसे पकड़ने का श्रेय जम्मू-कश्मीर पुलिस को ही जाता है। राज्य पुलिस का राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में कुर्बानियां देने का एक गौरवशाली इतिहास है। पुलिस के शहीदों ने अपने खून से जम्मू-कश्मीर में हमेशा राष्ट्रविरोधी तत्वों को नाकाम बनाया है। देविंदर सिंह जैसी ब्लैक शीप से पुलिस के मनोबल या निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। पुलिस आतंक को खत्म करने के अभियान को जारी रखेगी। फारूक खान ने ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस अभियान दल जिसे एसटीएफ और एसओजी के नाम से जाना जाता है, की नींव रखी थी। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्लैक शीप किसी भी जगह, किसी भी संस्था में हो सकते हैं। पुलिस कोई अपवाद नहीं है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ही उसे आतंकियों संग पकड़ा है, उसे छिपाया नहीं है। उसके साथ आतंकियों जैसा ही सुलूक किया जा रहा हे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

उन्होंने जांच के बारे में किसी तरह का ब्यौरा देने से इन्कार करते हुए कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है।

पुलिस की छवि को कोई नुकसान नहीं : फारूक खान ने कहा कि यह देश की एकता और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। देविंदर सिंह ने जो किया उससे राज्य पुलिस के जवानों और अधिकारियों का मनोबल कहीं नहीं गिरेगा।

पुलिस की छवि को कोई नुकसान नहीं है। कोई सड़ी हुई मछली जम्मू-कश्मीर पुलिस की छवि को खराब नहीं कर सकती।

रिश्वत मामले में मुकुल को राहत, गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : रेलवे पैनल की सदस्यता दिलाने के नाम पर कथित रिश्वत लेने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता मुकुल राय को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मिला गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया। मुकुल राय की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

इसके साथ ही खंडपीठ ने भाजपा नेता को जांच में सहयोग कर का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता और लोक अभियोजक शाश्वत मुखर्जी ने कहा था कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइआई) का गठन किया गया है और वह आरोपों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है। दस्तावेजों के सत्यापन में और अधिक समय की मांग करते हुए वकीलों ने 4 दिसंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। इस मामले में भाजपा नेता को हाई कोर्ट से पहले भी गिरफ्तारी से संरक्षण मिल चुका है। राय को सबसे पहले 29 अगस्त को हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से एक हफ्ते का संरक्षण मिला था और बाद में इसे बढ़ा दिया गया।

संटू गांगुली ने शिकायत में आरोप लगाया था कि भाजपा के स्थानीय मजदूर मोर्चा के नेता बबन घोष ने उन्हें जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी की सदस्यता दिलाने का वादा करते हुए राय का नाम लिया था और लाखों की रिश्वत ली थी।

'जेएनयू, गूगल-वाट्सएप मुहैया कराएं जानकारी'

हाई कोर्ट का निर्देश ▶ पुलिस गवाहों को जल्द समन भेजे, वाट्सएप ग्रुप के सदस्यों का फोन करें जब्त

जेएनयू के तीन प्रोफेसरों ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुलिस ने कहा कि ग्रुप के 37 सदस्यों की पहचान की जा चुकी है
- 5 जनवरी को हुई हिंसा मामले से जुड़े सभी सुबूत और डाटा पुलिस को उपलब्ध कराने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर जेएनयू प्रशासन, गूगल और वाट्सएप को निर्देश दिया कि 5 जनवरी को हुई हिंसा मामले से जुड़े सभी सुबूत, सीसीटीवी फुटेज और डाटा पुलिस को उपलब्ध कराएं।

पीठ ने पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द गवाहों को समन जारी करें और हिंसा से जुड़े वाट्सएप ग्रुप के सदस्यों के फोन जब्त करें। पीठ ने इसके साथ ही जेएनयू प्रशासन व कैंपस स्थित एसबीआइ बैंक की शाखा को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराएं। पीठ ने उक्त निर्देशों के साथ तीन प्रोफेसर अमीत परामेस्वरन, प्रोफेसर अतुल सेन और प्रोफेसर शुक्ला विनायक सावंत की याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ के फैसले से पहले सुनवाई के दौरान गूगल की तरफ से पीठ को बताया गया कि अगर पुलिस घटना से जुड़े लोगों और दोनों वाट्सएप ग्रुप (यूनिटी अगेस्ट लेफ्ट व फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस) के सदस्यों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराती है, तब वह गूगल ड्राइव की जांच करेगी। अगर बैकअप में इससे जुड़े डाटा मिले तो इन्हें संरक्षित करके पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं, वाट्सएप ने पीठ को बताया कि अगर एक बार मैसेज किसी व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो फिर एप में उपलब्ध कराए गए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के कारण यह सर्वर पर नहीं रहता है। वाट्सएप ने दावा किया कि इससे जुड़े संदेश सिर्फ इसे रिसीव करने या फिर भेजने वाले के मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगे। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि वाट्सएप ने एक अन्य मामले में मद्रास हाई कोर्ट में कहा था कि यूजर का आइपी एड्रेस उपलब्ध कराया जा सकता है। इस दलील के साथ याचिकाकर्ता ने वाट्सएप को दोनों ग्रुप के सदस्यों का आइपी एड्रेस उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की। इस पर वाट्सएप ने कहा कि वह अंतिम यूजर का आइपी एड्रेस उपलब्ध करा सकता है।

37 लोगों की हुई पहचान : दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि उनकी तरफ से 10 जनवरी एवं 11 जनवरी को वाट्सएप को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की थी, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं जेएनयू प्रशासन और सीबीआइ ब्रांच को भी पत्र लिखकर घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करके पुलिस को देने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पुलिस ने कहा कि ग्रुप के 37 सदस्यों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें पेश होने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। हालांकि, अब तक कोई फोन जब्त नहीं किया गया है।

जेएनयू हिंसा मामले में दो और छात्रों से की गई पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जेएनयू। फाइल

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने मंगलवार को जेएनयू पहुंचकर सुचेता तालुकदार और प्रिया रंजन कुमार से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले एसआइटी ने सोमवार को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष, वास्कर विजय व पंकज मिश्रा से भी पूछताछ की थी। ये सभी वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े हैं।

बीते शुक्रवार (10 जनवरी) को एसआइटी ने जेएनयू हिंसा मामले में वामपंथी छात्र संगठनों के सात व दक्षिणपंथी छात्र संगठनों के दो छात्रों की तस्वीरें जारी कर दावा किया था कि ये लोग कैंपस में 5 जनवरी को हुई हिंसा में शामिल थे। हिंसा में घायल चार छात्रों से भी एसआइटी ने मंगलवार को पूछताछ की और उनसे जानकारी ली। 5 जनवरी की घटना से एक दिन पहले 4 जनवरी को वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रशासनिक भवन स्थित सर्वर रूम में घुसकर तोड़फोड़ की थी।

उधर, एसआइटी की एक अन्य टीम के साथ फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने सर्वर रूम में पूरे दिन रहकर जांच की और फुटेज प्राप्त करने की कोशिश की। बता दें कि जांच टीम बुधवार को भी सर्वर रूम की जांच करेगी।

बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 1426 शिक्षकों पर मुकदमा

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों में संविदा पर काम करने वाले 1426 शिक्षकों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमा दायर किया है। निगरानी के राडार पर अभी सैकड़ों और शिक्षक भी हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। निगरानी ब्यूरो के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाली मामले की जांच शुरू की गई थी।

ब्यूरो ने अब तक 2.43 लाख शिक्षकों से मिले करीब सात लाख प्रमाण पत्रों में से 3.16 लाख प्रमाण पत्रों की जांच की है। बताया जाता है कि कई शिक्षकों ने जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने के प्रमाण पत्र भी जमा किए। जिनकी गहनता से जांच के क्रम में अब तक 1131 प्रमाण पत्र फर्जी मिले। जिसके बाद निगरानी ने अलग-अलग समूह में अलग-अलग जिलों में करीब 419 प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। इन प्राथमिकी में 1426 शिक्षकों को आरोपी बनाते हुए इन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है।

निगरानी ब्यूरो के सूत्रों की माने तो जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। जिलों से लगातार शिक्षकों के प्रमाण पत्र के फोल्डर मांगे गए हैं। जैसे-जैसे प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे जांच आगे बढ़ेगी। इस दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर संबंधित दोषी शिक्षक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।

जीने का तरीका बताता है धर्म इसलिए सर्वोच्च : भागवत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली में किया मेडी-डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म इंसान को जीने का तरीका बताता है, इसलिए इसे सर्वोच्च माना जाता है। समाजसेवा और अच्छे कार्यों में सभी को सहभागिता करनी चाहिए। इसमें जाति और संप्रदाय नहीं देखना चाहिए। सेवा मानवता की सहज अनुभूति है और यह निस्वार्थ भाव से होती है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली स्थित जसोला संस्थानिक क्षेत्र में मेडी-डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें किडनी के मरीजों को सस्ती दर पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। ओम बिरला ने सस्ती दर पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि और लोगों को भी सेवा कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। भागवत ने कहा, आज भी बहुत से लोग और संस्थाएं हैं जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान सुरक्षित रखकर उसे नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इस सेंटर में योग और ध्यान साधना का भी इंतजाम किया गया है ताकि व्यक्ति की बीमारी दूर करने के साथ ही उसका मन भी स्वच्छ हो जाए। विज्ञान और अध्यात्म को साथ-साथ चलना चाहिए।

गौरतलब है कि इस सेंटर की देखरेख भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन और डॉ. हेडगेवार स्मारक न्यास द्वारा की जाएगी। इस सेंटर में निजी अस्पतालों में करीब साढ़े पांच हजार रुपये में होने वाली डायलिसिस प्रक्रिया को सिर्फ 500 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। गरीब रोगियों को इससे भी कम दर पर डायलिसिस मिलेगी। यहां मेडिटेशन सेंटर भी होगा ताकि ध्यान, योग साधना के जरिये भी मरीजों का स्वास्थ्य सुधारा जा सके। यह सेंटर सभी आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। इसमें डायलिसिस सेंटर में विशेषज्ञों, आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन योग और ध्यान का भी परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा ताकि रोगियों को बाद में डायलिसिस की जरूरत ही न पड़े।

अब मप्र के जिला अस्पताल में आठ घंटे में छह बच्चों की मौत से हड़कंप

नईदुनिया, भोपाल

- अस्पताल प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला, कहा- गंभीर स्थिति में थे बच्चे
- नेता प्रतिपक्ष भार्गव बोले- वेंटिलेटर पर हैं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं

> जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उनको बचाने की कोशिश डॉक्टर व स्टाफ ने की, लेकिन नहीं बचाया जा सका।
>
> **डॉ. राजेश पांडेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल।**

राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में कुछ ही दिनों में एक सौ से ज्यादा बच्चों की मौतों के बाद अब मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में मात्र आठ घंटों में छह बच्चों की मौत हो गई है। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, जिला अस्पताल प्रबंधन ने इन मौतों पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि जितने भी बच्चे यहां भर्ती थे वे सब गंभीर स्थिति में थे। उनको बचाना बेहद मुश्किल था। मृत बच्चों में से अधिकांश को निमोनिया की शिकायत थी। उधर, इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। अस्पताल में जिन बच्चों की मौत हुई उनमें दो माह के सूरज बैगा, श्यामनारायण कोल सहित 13 दिन, 6 दिन के बच्चे शामिल हैं। वहीं बच्चा वार्ड में ढाई महीने का सुभाष बैगा, दो माह की अंजलि बैगा का नाम शामिल हैं।

बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही शहडोल के प्रभारी कलेक्टर पार्थ जायसवाल एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट) पहुंचे और इंचार्ज डॉ. सुनील हथगेल से जानकारी ली। प्रदेश के मंत्री कमलेश्वर पटेल शहडोल प्रवास पर थे, सूचना मिलते ही वह भी अस्पताल पहुंचे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्थिति का जायजा लिया।

स्वास्थ्य मंत्री सिलावट के निर्देश पर शहडोल के कमिश्नर आरबी प्रजापति ने जांच कमेटी गठित की है। यह 15 जनवरी को रिपोर्ट सौंपेंगी।

सिविल सर्जन बोले-किसी की कोई लापरवाही नहीं : सिविल सर्जन ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है, जिसमें किसी डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं बताते हुए बच्चों की मौत गंभीर बीमारी की वजह से होना बताया है।

कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला : भार्गव

मप्र विस में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर शहडोल में बच्चों की मौत पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में मासूमों की मौत का सिलसिला कब थमेगा? क्या हर बार जांच के नाम पर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर लेगी? रतलाम अस्पताल में दो माह में 90 नवजात बच्चों की मौत के बाद भी सरकार नहीं जागी।

राजकपूर की बेटी रितु नंदा का लंबी बीमारी के बाद निधन

नई दिल्ली में मंगलवार को अपनी मां रितु नंदा के अंतिम संस्कार के दौरान निखिल नंदा। इस दौरान अभिनेता अभिषेक बच्चन और निखिल की बेटी नव्या भी मौजूद रही। एएनआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बॉलीवुड के शोमैन राजकपूर की बेटी और अमिताभ बच्चन की समधन रितु नंदा का सोमवार रात एक बजे निधन हो गया। मंगलवार को दिल्ली में लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह कैंसर से पीड़ित थीं। कारोबारी और चित्रकारी की शौकीन रितु के अंतिम दर्शन के लिए बच्चन परिवार के साथ ही कपूर खानदान भी श्मशान घाट पर मौजूद था। रितु के बेटे निखिल नंदा ने उनको मुखाग्नि दी। रितु एस्कॉर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन रहे राजन नंदा की पत्नी थीं। राजन का निधन अगस्त 2018 में हुआ था। अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार व पारिवारिक मित्र भी पहुंचे। रितु के बेटे निखिल नंदा और बेटी नताशा नंदा हैं। निखिल की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से हुई है। रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर के अलावा अभिषेक बच्चन, रीमा जैन, अनिल नंदा भी वहां मौजूद थे।

कसा शिकंजा

इंवेस्टीगेशन, खुफिया और बेनामी विंग ने तेज की छानबीन, श्वेता और आरती से पूछताछ में विभाग को मिले कई नाम

हनी ट्रैप मामले में आयकर के निशाने पर कई बड़े अधिकारी

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपित श्वेता विजय जैन और आरती दयाल से आयकर विभाग में हुई लंबी पूछताछ में ऐसे अधिकारियों व अन्य लोगों की जानकारी सामने आई है, जिनके बीच लाखों का लेनदेन हुआ। निशाने पर कई बड़े अधिकारी भी आ गए हैं। जल्द ही इनसे पूछताछ हो सकती है। विभाग की खुफिया, बेनामी और इंवेस्टीगेशन शाखा इनके खिलाफ वित्तीय लेनदेन के सुबूत जुटा रही हैं।

प्रदेश में करीब चार महीने से हनी ट्रैप मामला सियासी और प्रशासनिक हलकों के साथ मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। आयकर विभाग की बेनामी एवं इंवेस्टीगेशन विंग अब अधिकारियों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठे जाने की पुष्टि करने में जुटी है।

मामले की प्रमुख आरोपित श्वेता विजय जैन से सोमवार को हुई पूछताछ के दौरान भी विभाग का फोकस इसी बात पर रहा। मंगलवार को विभाग के समक्ष आरती दयाल को भी पूछताछ के लिए पेश किया गया। मामले की जांच कर रहे एसआइटी (विशेष जांच दल) सभी आरोपितों से पहले ही लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसका ब्योरा भी आयकर विभाग को मिल गया है।

एसआइटी ने सौंपे साक्ष्य: बताया जाता है कि एसआइटी ने मामले में चालान पेश होने के बाद आयकर विभाग को अब तक की जांच के संदर्भ में कई तथ्य उपलब्ध कराए हैं।

आयकर विभाग वित्तीय लेनदेन के संबंध में आरोपितों से पूछताछ, आरोप पत्र और दस्तावेजों की छानबीन से जरूरी तथ्य जुटाने में लगा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय लेनदेन के संदर्भ में उनके सामने कई अफसरों के भी नाम हैं, हालांकि फिलहाल विभाग इन सभी के खिलाफ पुख्ता सुबूत जुटा रहा है।

भगोड़े अखबार संचालक का घर-होटल होगा कुर्क

इंदौर में हनी ट्रैप से जुड़े मामले सहित 55 अपराधों में वांछित एक लाख रुपये के इनामी अखबार संचालक जीतू सोनी (जितेंद्र) की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने सोनी के घर, ऑफिस, होटल सहित इंदौर में कई जगह फरारी संबंधित नोटिस भी चस्पा किए हैं। एमआइजी थाना पुलिस ने होटल माय होम और घर कुर्क करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। आरोपित को 13 जनवरी तक हाजिर होने का समय दिया गया था। मंगलवार को पुलिस ने मामले में कोर्ट में आवेदन पेश कर दिया है। डीआइजी रुचि वर्धन मिश्र ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट तारीख तय कर कुर्की के आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि जीतू के विरुद्ध हरभजन सिंह की शिकायत पर एक दिसंबर को पहला केस दर्ज किया गया था। हरभजन ने आरोप लगाया कि हनी ट्रैप में गिरफ्तार महिला आरोपितों द्वारा बनाए वीडियो यूट्यूब और अखबार के माध्यम से प्रकाशित कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मामले में जीतू सोनी का बेटा अमित सोनी गिरफ्तार हो चुका है।

> मामले में वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। हमारा फोकस केवल वित्तीय लेनदेन और मामले से जुड़े संबंधितों की आय के स्रोत पर है। पैसों के लेनदेन 'मनी ट्रैल' में शामिल सभी लोगों को छानबीन के दायरे में लिया गया है। साक्ष्य मिलने पर अधिकरियों सहित अन्य सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
>
> **-राजेश टुटेजा, महानिदेशक, आयकर इंवेस्टीगेशन विंग, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़**

पंजाब में चार बार घुसे पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग

जासं, फिरोजपुर

भारत-पाक सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन देखे गए। चार बार दिखाई दिए ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने फायरिंग कर लौटने पर मजबूर कर दिया। फिरोजपुर सेक्टर की चौकी बीओपी शामे के गाव टेंडी वाला में दो बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सरहद में दाखिल हुआ। दूसरी बार सोमवार रात 8:48 बजे ड्रोन दाखिल होने पर बीएसएफ 136 बटालियन के जवानों ने फायरिंग की, लेकिन इन्हें गिराने में कामयाबी नहीं मिली। घटना के दौरान ग्रामीण सड़क पर निकल आए।

पंजाब पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इन ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के लिए किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर गुरदीप सिंह ने कहा कि वह मौके पर गए थे, लेकिन तलाश में कुछ नहीं मिला। तरनतारन के खेमकरण सेक्टर में भी रात 10 बजे गांव गजल के पास दो ड्रोन भारतीय क्षेत्र में दिखाई दिए। इन्हें देखकर बीएसएफ की 116वीं बटालियन के जवानों ने 10 राउंड फायर किए। इसके बाद ड्रोन वापस लौट गए। गांव गजल के कुलदीप सिंह, मूला सिंह, मेवा सिंह, फौजा सिंह ने बताया कि उन्होंने रात को रोशनी वाली वस्तु देखी, जो काफी ऊंचाई पर थी। गांव रत्तोके व भंगाला के लोगों ने भी ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की। सुबह बीएसएफ ने 12 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला।

तीन दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने जेल से ड्रोन नेटवर्क चलाने का पर्दाफाश किया। पिछले साल पांच अगस्त को ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने की पहली घटना सामने आई थी।

3696 करोड़ रुपये का चुनावी चंदा विभिन्न स्रोतों से दो राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस सहित पांच क्षेत्रीय दलों (टीएमसी, बीजद, जेडीएस, टीआरएस और वाइएसआरसीपी) को मिला। कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के अनुसार, इनमें 65.51 फीसदी चंदा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिला।

पहाड़ों में जारी है बर्फबारी और परेशानी का दौर

मौसम का मिजाज ▸ बंद पड़े हैं केदारनगरी के सभी निर्माण कार्य

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई भीषण बर्फबारी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं पर्यटक फंस गए हैं। इसके अलावा ठंड बढ़ने से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते केदारनगरी के सभी निर्माण कार्य रुक गए हैं। इसके अलावा तीनों ही पहाड़ी प्रदेशों में हवाई यातायात भी बाधित है।

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। केदारनाथ में छह से सात फीट बर्फ की चादर पसरी हुई है। वहां पुनर्निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक प्रदेश में मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं होगा।

घाटी में रेल और हवाई सेवा बहाल : घाटी में जबरदस्त बर्फबारी के बाद मौसम में तो सुधार हुआ, लेकिन जनजीवन अभी भी अस्तव्यस्त बना हुआ है। वादी के सैकड़ों इलाके जिला मुख्यालयों से कटे हुए हैं। वहीं, अधिकांश क्षेत्रों में बिजली-पानी की आपूर्ति ठप होकर रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम के मिजाज तीखे हो जाएंगे। जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, लेह-श्रीनगर और पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड अभी भी बंद है। बनिहाल से कश्मीर जाने वाली रेल सेवा और हवाई सेवा दोपहर बाद बहाल हो गई।

हिमस्खलन का खतरा : ताजा बर्फबारी के बाद वादी के उच्च पवर्तीय इलाकों कुपवाड़ा, गांदरबल, शोपियां, बारामुला, अनंतनाग व बडगाम में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने इन इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल में बारिश व बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है।

लद्दाख की जंस्कार वेली में 'चादर ट्रैक' पर लापता हुए पर्यटक दल को सेना ने बचा लिया है। माइनस 30 डिग्री तापमान होने के कारण सर्दियों में जंस्कार नदी जम जाती है और एक ट्रैक बन जाता है। ऐसे में देश-विदेश के सैकड़ों पर्यटक जंस्कार नदी पर ट्रैकिंग के लिए यहां आते हैं। ऐसे ही एक दल के कुछ पर्यटकों की तबीयत बिगड़ गई और फिर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें निकाला गया। एएनआइ

श्रीनगर-लेह हाईवे में हिमस्खलन के कारण गई पांच लोगों की जान

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

जिला गांदरबल में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमर्ग पर स्थित कुल्लन इलाके में दो जगह हिमस्खलन हुए। एसएसपी गांदरबल खलील मोहम्मद पोस्वाल ने बताया कि पहला हिमस्खलन कुल्लन के साथ सटे राइसन इलाकों में हुआ। यहां समय रहते बचावकर्मियों ने 12 लोगों को बचा लिया। दूसरा हिमस्खलन कुल्लन के ही खास इलाके में हुआ और पहाड़ से खिसके बर्फ के बड़े-बड़े तोदों की चपेट में एक मकान और उसमें रहने वाले नौ लोग दब गए। सूचना मिलते ही राहत कार्य शुरू किया गया। वहीं, चार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन पांच अन्य ग्रामीणों को जब तक बर्फ के नीचे से निकाला जाता, वह दम तोड़ चुके थे।

गुरेज में गई एक ग्रामीण की जान : कुपवाड़ा के साथ सटे जिला बांडीपोरा में गुरेज सेक्टर और रामपुर सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आकर दो सैन्य चौकियों को क्षति पहुंची। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनक्षति नहीं हुई है। गुरेज सेक्टर में ही पुराना तुलैल गांव में हिमस्खलन के दौरान दो मकान बर्फ के तोदों के नीचे दब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और सेना के जवानों के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। बर्फ के नीचे से तीन ग्रामीणों को जिंदा निकाला गया। उन्हें गंभीर हालत में निकटवर्ती अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक अन्य ग्रामीण को मृत अवस्था में ही बर्फ के नीचे से निकाला जा सका।

करनाह में भी एक शहीद : करनाह में शिवा पोस्ट के पास मंगलवार देर शाम करीब आठ बजे गश्त कर रहे सेना के छह जवान हिमस्खलन की चपेट में आ गए। बचाव दल ने पांच जवानों को बचा लिया, जबकि एक शहीद हो गया। शहीद की पहचान राइफलमैन लक्ष्मण के रूप में हुई है। वहीं, बचाए गए पांच जवान भी बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं।

हिमाचल में भी भूस्खलन, गई तीन की जान : बारिश-बर्फबारी थमने के बाद मंगलवार को चंबा जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। विकास खंड मैहला की गागला पंचायत के तहत चंबा-धुलाड़ा मार्ग पर नरालपट्टा नाले के पास मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे पहाड़ी दरकने से मलबे की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, त्रिवेणी घार में कुटिया पर पहाड़ी का मलबा गिरने से युवक की मौत हो गई।

बीस साल से लटकी सीडीएस की नियुक्ति, मोदी ने दी मंजूरी

जयपुर में मंगलवार को भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह में एक पूर्व सैनिक से मिलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण

- भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह में शिरकत करने जयपुर पहुंचे रक्षामंत्री
- कहा-भारत की एकता और अखंडता का श्रेय सेना के जवानों को

जागरण संवाददाता, जयपुर

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति पर 20-21 साल से मंथन चल रहा, मगर मैंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की तो उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। साथ ही पद गठन के आदेश जारी कर दिए। वह मंगलवार को जयपुर में भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह में बोल रहे थे। समारोह में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने व सीडीएस बिपिन रावत ने भी शिरकत की।

इस दौरान सिंह ने कहा कि भारत अगर आज सुरक्षित है तो इसका पूरा श्रेय सेना के जवानों को जाता है। देश, इसकी सीमाएं, एकता और अखंडता सुरक्षित है तो यह सब सेना के बहादुर जवानों के कारण है। ऐसे में सेना के जवानों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है ।

आपका कद बड़ा है : भूतपूर्व सैनकों से राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा पद बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका कद बड़ा है । व्यक्ति की पहचान पद से नहीं उसके काम से होती है। पूर्व सैनिकों ने जंग लड़ी है, जोखिम उठाया है, इसलिए आपका कद बड़ा है। उन्होंने कहा कि एक बार जो सैनिक बन गया वह जीवनभर सैनिक रहता है। यह बात देश जानता है।

आपका कल्याण हमारी प्राथमिकता : रक्षामंत्री ने पूर्व सैनिकों से कहा कि आपका कल्याण हमारी प्राथमिकता है । हमें अपने पूर्व सैनिकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका कार्य अतुलनीय है । देश में पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान की परंपरा काफी समय से है । सेना को एक संस्थान के तौर पर अपने सैनिकों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए । हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो जड़ों से कट जाता है,वह कटी पतंग हो जाता है । अपने बड़े बुर्जुगों का सम्मान हमेशा होना चाहिए । कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिक एवं अधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षामंत्री उनसे मुखातिब हुए और हालचाल पूछे।

महिलाओं की मिलिट्री पुलिस में नियमित होगी भर्ती : नरवाने

इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने के कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिक अलग-अलग क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं । पूर्व सैनिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमेशा इनका सम्मान कायम रहेगा । उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 240 अधिकारियों और 11 हजार 500 सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद अन्य क्षेत्रों में नौकरी पाने में मदद की थी ।यह काम आगे भी जारी रहेगा । उन्होंने कहा कि हाल ही में 1700 महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में शामिल किया गया है। यह पहली बार हुआ। इन दिनों इनकी ट्रेनिंग चल रही है । अब महिलाओं की मिलिट्री पुलिस में भर्ती नियमित होगी ।

देश के प्रति धर्म पहले : रावत

इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना के जवानों का देश के प्रति धर्म पहले है और खुद एवं परिवार के लिए बाद में। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का सम्मान हमेशा कायम रहा है और आगे भी इसे बरकरार रखा जाएगा । जयपुर के सैन्य क्षेत्र के सप्तशक्ति कमांड एरिया में आयोजित समारोह के बाद नरवाने और रावत ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया ।

न्यूज गैलरी

सजा होने मात्र से नहीं की जा सकती बर्खास्तगी : हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अहम निर्णय में कहा कि केवल आपराधिक मामले में सजा होने मात्र से सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी नही की जा सकती। इन मामलों में उस कर्मचारी के आचरण पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने एसएसपी झांसी के याची सिपाही की बर्खास्तगी आदेश को रद कर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने कांस्टेबल रामकिशन की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एके ओझा ने बहस किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विधि सिद्धांतों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि नैतिक अपराध की स्थिति में सेवा प्रभावित होगी। याची को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। अपील में उसे जमानत मिली है। एसएसपी ने सजा होने के कारण उसे बर्खास्त कर दिया। इस पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा कि आचरण पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि याची बहाल होता है तो बकाया वेतन सहित सेवाजनित परिलाभ पाने का भी हकदार होगा। (जासं)

मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के बीच कटेकल्याण इलाके में सोमवार रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या मुखबिरी के आरोप के कारण की है। हत्या के बाद नक्सलियों ने शव के पास पर्चा भी फेंका है, जिसमें पीड़ित को पुलिस का मुखबिर बताया गया है। जानकारी के अनुसार कटेकल्याण थाना क्षेत्र के दुवालीकरका निवासी लक्ष्मण की नक्सलियों ने सोमवार रात धारदार हथियार से हत्या कर उसका शव गांव के पास ही सड़क किनारे फेंका दिया। सुबह ग्रामीण और राहगीरों ने शव देखकर परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर मिले हस्तलिखित नक्सली पर्चे के मुताबिक लक्ष्मण मंडावी पुलिस के लिए मुखबिरी करता था और उसकी मुखबिरी की वजह से अप्रैल माह में हुए मुठभेड़ में नक्सली नेता वर्गीस और लिंगा मारे गए थे। इसके बाद से ही लक्ष्मण नक्सलियों के निशाने पर था। उधर, गांव में चर्चा है कि सोमवार को लक्ष्मण मवेशी चराने पास के जंगल में गया था तभी नक्सली पकड़कर उसे अपने साथ ले गए थे। उसके बाद उसकी हत्या नक्सलियों ने कर दी। (नईदुनिया)

156 करोड़ की मनी लांड्रिंग में तीन सीमाशुल्क अधिकारियों पर मुकदमा

- हीरा आयात में मनी लांड्रिंग गिरोह में शामिल होने का आरोप
- सीबीआइ ने कुल 17 के खिलाफ दर्ज किया मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने मनी लांड्रिंग के मामले में मुंबई के सीमाशुल्क विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों समेत 17 व्यक्तियों और कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया है। सीमाशुल्क अधिकारियों पर उस मनी लांड्रिंग गिरोह में शामिल होने का आरोप है, जिसने 156 करोड़ के हीरा आयात में हेराफेरी की थी। सीबीआइ के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की जांच में पाया गया कि इस षड्यंत्र में शामिल रहते हुए सीमाशुल्क अधिकारियों ने कथिततौर पर चालान में फर्जीवाड़ा किया। इसके बाद मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंपा गया।

डीआरआइ ने जांच में पाया था कि हांगकांग के कारोबारी गिरीश कडेल ने स्विट्जरलैंड से हांगकांग स्थित अपनी चार कंपनियों के नाम पर कच्चा हीरा खरीदा था। इसके बाद उसने भारत की दो कंपनियों एंटिक एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड और तनमन ज्वेलर्स को 14 खेप में कुछ हीरों का निर्यात किया। इनकी कीमत उसने बढ़ा-चढ़ाकर 156.28 करोड़ रुपये बताई थी।

सीबीआइ। फाइल फोटो

सीबीआइ का आरोप है कि कडेल ने दोनों भारतीय कंपनियों के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड (आइईसी) का अपने सहयोगी अतुल पालडेचा के जरिये इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में कीमत से बहुत ज्यादा मूल्य के हीरे का आयात दिखाकर बड़ी राशि को भारत से बाहर भेजने का अपराध किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कच्चे हीरे की अत्यधिक कीमत में आयात का उद्देश्य दूसरे आयातित वस्तुओं की कीमत को अदा करना और विदेश में राशि जमा करना था, ताकि उसका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि तत्कालीन आयुक्त एपीएससी मुंबई विनय ब्रज सिंह ने इस मामले में अपने अधीनस्थों को पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके बावजूद कि उन्होंने ही इस मामले में जांच के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि इसके कुछ दिनों के बाद ही सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाया और उन्हें जांच रिपोर्ट बदलने के लिए कहा।

इस मामले में सिंह के अलावा सीमाशुल्क उपायुक्त सीवाई मणिकन्हैया और आशिकजमा, कडेल, पालडेचा, एंटिक एग्जिम, तनमन ज्वेलर्स, इंप्रेस क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यात्री को जेल भेजने की धमकी देने वाला पायलट ड्यूटी से हटाया गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक महिला यात्री ने दावा किया कि बेंगलुरु में अपनी मां के लिए व्हीलचेयर मांगने पर इंडिगो के एक पायलट ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। इस मामले में केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयरलाइन ने पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है।

सुप्रिया उन्नी नायर ने सोमवार रात बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमान लैंड करने के बाद अपनी 75 वर्षीय मां के लिए व्हीलचेयर की मांग की। उन्होंने ट्वीट में आरोप लगाया कि पायलट ने उनसे दुर्व्यवहार किया और जेल भेजने की धमकी दी। इस पर पुरी ने ट्वीट किया, 'मैंने जैसे ही सुप्रिया उन्नी नायर का उनके और उनकी मां के साथ पायलट के व्यवहार से जुड़ा ट्वीट देखा, तो अपने कार्यालय से इंडिगो से संपर्क करने को कहा। एयरलाइन ने नागर विमानन मंत्रालय को बताया कि जांच पूरी होने तक पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है।' नायर ने दावा किया कि जब बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उनकी मां को ले जाने के लिए व्हीलचेयर लाई गई, तो पायलट ने उनको विमान से ले जाने से रोका।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फैसला अब 20 को

- मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 20 लोगों पर चला पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में साकेत कोर्ट अब 20 जनवरी को फैसला सुनाएगा। मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत कुल 20 लोगों पर (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) पॉक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल रहा है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अभियुक्तों में बालिका गृह के कर्मचारी और सामाजिक कल्याण विभाग बिहार के अधिकारी भी शामिल हैं। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 20 जनवरी की तारीख दी है। हाल में मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने अदालत को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी।

फरवरी 2019 से चल रही सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी 2019 से इस मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है। मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर पर पॉक्सो व दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था।

यह है मामला

जुलाई 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त बालिका गृह में कई बच्चियों से दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। सभी 20 आरोपितों को 23 फरवरी 2019 को कड़ी सुरक्षा में दिल्ली लाया गया था। मामले में ब्रजेश ठाकुर, इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि कुमार रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल, किशन राम उर्फ कृष्णा, रोजी रानी, डॉ. अश्विनी उर्फ आसमानी, विक्की, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह व साइस्ता परवीन उर्फ मधु आरोपित हैं।

चोरी के शक में पीट-पीटकर हत्या करने वाले नौ को उम्रकैद

नईदुनिया, टीकमगढ़ : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या व शव पेड़ से लटकाने के नौ दोषियों को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को पंचम अपर सत्र न्यायालय ने सभी को दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार 25 मार्च 2017 को किशोरी कुशवाहा के घर में चोरी हुई थी। इसमें सोना-चांदी और नकदी चोरी हो गई थी। इस बात की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। गांव के लोगों ने चोरी का शक भज्जू उर्फ कमलेश पर किया और उसके साथ जमकर लात-घूसों से मारपीट कर दी। नौ लोगों ने पहले भज्जू के साथ मारपीट की और फिर सांसें थम जाने के बाद शव साक्ष्य छिपाने के लिए महुआ के पेड़ से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उजागर होने के बाद नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर किया गया था। मामला पंचम अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक प्रत्यूष पाठक ने बताया कि मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

आर्मी कैंप से राइफलें चोरी करने वाला पूर्व फौजी अस्पताल से हुआ फरार

जागरण संवाददाता, होशियारपुर

सवा माह पहले मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी होशंगाबाद के आर्मी कैंप से दो राइफल चोरी कर अपराधी बना हवालाती पूर्व फौजी हरप्रीत सिंह मंगलवार तड़के चार बजे सरकारी अस्पताल होशियारपुर से एएसआइ को धक्का देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। हवालाती हरप्रीत के फरार होने के बाद एएसआइ और उसके साथी हेड कांस्टेबल ने दो घंटे तक अपने आला अधिकारियों को सूचित ही नहीं किया और खुद ही उसे इधर-उधर ढूंढते रहे।

सूचना मिलने के बाद एसपी (हेड क्वार्टर) परमिंदर सिंह अस्पताल के कैदियों वाले वार्ड में पहुंचे। एसएसपी गौरव गर्ग ने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसआइ बलदेव राज व हेड कांस्टेबल दविंदर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके निलंबित कर दिया गया है। मूलरूप से होशियारपुर के गांव मियाणी निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ राजा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बतौर जवान तैनात था। गत पांच दिसंबर को हरप्रीत सिंह ने अपने दोस्त की मदद से आर्मी कैंप से दो राइफलें चोरी कीं और फिर टांडा आ गया था।

हरप्रीत सिंह की फाइल फोटो।

जेल में ही रचा भागने का षडयंत्र : हरप्रीत ने जेल में ही भागने का साजिश रची था। 29 दिसंबर को हरप्रीत ने जेल प्रशासन से शिकायत की थी कि वह गिर गया है और उसकी बाईं बाजू में चोट लगी है। दो दिन तक जेल में इलाज कराने पर आराम न मिलने पर हरप्रीत को सरकारी अस्पताल भेजा गया। यहां पर एक्स-रे में हरप्रीत की बाजू में फ्रैक्चर निकला। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह ने उसे दाखिल कर लिया। एक जनवरी को हरप्रीत का ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद से ही वह अस्पताल के कैदियों वाले वार्ड में रह रहा था। मंगलवार तड़के चार बजे हरप्रीत सिंह ने एएसआइ बलदेव राज से शौच जाने की बात कही। एएसआइ बलदेव सिंह उसे हथकड़ी पहनाकर शौचालय की तरफ ले जा रहा था। इस दौरान हरप्रीत ने बलदेव राज को धक्का दे दिया और हथकड़ी समेत भाग गया। डॉ. मनमोहन सिंह के मुताबिक मंगलवार दोपहर को हरप्रीत को अस्पताल से छुट्टी करके जेल भेजना था। हरप्रीत के पिता हरबंस राज को भी पुलिस ने उसके घर से उठा लिया है। पुलिस को शक है कि हरप्रीत के भगाने में हरबंस ने भी उसका साथ दिया है।

हरप्रीत के पाक भागने की आशंका : हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हरप्रीत के पाक भागने की आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर होशियारपुर के अलावा पड़ोसी जिलों सहित हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है।

मिसाल

लाल आतंक पर बीते दो सालों में मिली सफलता को जाया नहीं होने देना चाहती पुलिस

नक्सल चुनौती से निपटने डीजीपी खुद घूम रहे बस्तर के जंगलों में

नईदुनिया, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। बीते दो वर्षों में फोर्स ने उन इलाकों तक पहुंच बना ली है, जो पहले नक्सलियों के स्वतंत्र इलाके समझे जाते थे। अब यहां नक्सलवाद से अंतिम चरण की लड़ाई चल रही है। बीते सालों में मिली सफलता जाया न जाए और जवानों का उत्साह बना रहे इसलिए नक्सल ऑपरेशन की कमान अब भी सीधे डीजीपी डीएम अवस्थी थामे हुए हैं। वह नक्सल चुनौती से निपटने को खुद बस्तर के जंगलों में घूम रहे हैं।

अवस्थी पिछली भाजपा सरकार में डीजी नक्सल ऑपरेशन थे, तब वह रायपुर से ज्यादा वक्त बस्तर के जंगलों में गुजारा करते थे। उस वक्त उनकी भेज्जी किस्टाराम जैसे धुर नक्सल इलाकों से तस्वीर आती थीं। वह बाइक पर बैठकर अंदरूनी गांवों में चले जाया करते थे। इससे नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब वह पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं पर नक्सल समस्या से निपटने की मुहिम में उनका सीधा दखल अब भी दिख रहा है। डीजीपी बनने के बाद व्यस्तता बढ़ी है, लिहाजा पहले की तरह वह हर हफ्ते तो बस्तर नहीं आ पा रहे पर लगभग हर महीने संभाग के धुर नक्सल प्रभावित जिलों तक उनका दौरा अब भी हो रहा है। सोमवार को वह दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले पहुंचे थे। अधिकारियों की बैठक लेकर नक्सल अभियान में प्रगति का हाल जाना। आसपास के ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया।

डीजीपी डीएम अवस्थी कभी भी फोर्स के किसी भी कैंप में पहुंच जाते हैं। उनकी इस सक्रियता का सीधा असर नक्सल मोर्चे पर दिखता है। बीते एक साल में नक्सल वारदात में 40 फीसद से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। पिछले साल नक्सली एक भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, जबकि यह साल चुनावों का साल रहा।

सफलता के रास्ते में रुकना नहीं है : दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से अवस्थी ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हम सफलता के रास्ते पर काफी आगे निकल आए हैं। यहां रुकना नहीं है। नक्सल समस्या का पूर्ण समाधान निकालकर बस्तर में शांति और विकास की राह खोलनी है। इसके लिए जरूरी है कि नक्सलियों पर लगातार दबाव बनाए रखा जाए।

खुफिया तंत्र मजबूत हुआ : डीएम अवस्थी राज्य खुफिया ब्यूरो के प्रमुख भी हैं। नक्सल डीजी रहते हुए उन्होंने एसआइबी को काफी मजबूत किया। इसका नतीजा यह हुआ कि नक्सलियों के बारे में सुदूर गांवों से भी पुख्ता सूचनाएं मिलने लगी हैं। पिछले कुछ महीनों में एसआइबी के इनपुट के आधार पर पुलिस ने कई कुख्यात नक्सलियों को पकड़ा है।

जगदलपुर के धुर नक्सल प्रभावित जगरगुंडा कैंप के पास की बस्ती में ग्रामीणों से मिलने जाते डीजीपी डीएम अवस्थी (दाएं) और उनके साथ हैं सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान। नईदुनिया

जंगल में कसता फोर्स का शिकंजा

बस्तर में इस साल के शुरुआती दस दिनों में फोर्स के तीन नए कैंप खोले गए हैं। बड़े केरपे, बोदली और करेमेटा में। इन कैंपों के खुलने से न सिर्फ सुरक्षा चाक-चौबंद हुई है बल्कि ग्रामीणों में विश्वास की बहाली भी हुई है। सुकमा के पालोड़ी और दंतेवाड़ा के पोटाली जैसी रणनीतिक महत्व की जगहों पर कैंप खुलने से नक्सलियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। अवस्थी ने कहा है कि इस साल अभी और कैंप खुलेंगे।

असम राइफल का जवान छुट्टी पर जाते हुए लापता

जागरण संवाददाता, चमोली : चमोली जिले के सुनाऊं तल्ला गांव का रहने वाला असम राइफल का एक जवान लापता हो गया है। वह तीन जनवरी को छुट्टी पर दीमापुर से रवाना हुआ था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। जवान के ससुर ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी है। राजस्व पुलिस को सौंपी तहरीर में सेरा विजेपुर गांव के रहने वाले कैलाश चंद्र ने कहा है कि उनका दामाद अनिल पुरोहित 14-असम राइफल की चार्ली कंपनी में तैनात हैं। वह एक माह की छुट्टी लेकर तीन जनवरी को चला था। रवाना होने से पहले उसने मोबाइल पर पत्नी लक्ष्मी देवी से बात भी की। लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंचा। उन्होंने इस दौरान अपने सभी रिश्तेदारों और अनिल के दोस्तों से भी पता किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थराली क्षेत्र राजस्व उपनिरीक्षक चंद्र सिंह बुटोला ने बताया कि यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करने के लिए नायाब तहसीलदार को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

दैनिक जागरण
शब्दों की शक्ति बहुत प्रभावी होती है

छिछली बयानबाजी

संसद के भीतर और बाहर कई बार अपनी बेतुकी बातों से कांग्रेस को शर्मिंदा कर चुके कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी का यह बयान बेतुका ही है कि अगर कश्मीर में आतंकियों के साथ पकड़ा गया पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह यदि देविंदर खान होता तो आरएसएस के समर्थकों की प्रतिक्रिया कहीं तीखी होती। चूंकि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं इसलिए यही माना जाएगा कि वह पार्टी की रीति-नीति को ही बयान कर रहे हैं। यदि वह कांग्रेस की आधिकारिक राय को प्रकट नहीं कर रहे तो फिर पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है? सवाल यह भी है कि क्या अधीर रंजन चौधरी यही देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी मसले पर किस संगठन के समर्थक और उनकी भाषा में कहें तो ट्रोल्स क्या कह रहे हैं? आखिर वह इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि देविंदर सिंह के मामले में आरएसएस समर्थकों की प्रतिक्रिया उतनी तीखी नहीं है जितनी होनी चाहिए? क्या वह खुद एक ट्रोल की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस इस पर ध्यान दे तो बेहतर कि अधीर रंजन चौधरी किस तरह उसकी जगहंसाई करा रहे हैं। समझना कठिन है कि कांग्रेस के नीति-नियंता इसकी अनदेखी कैसे कर रहे हैं कि हाल के समय में अधीर रंजन चौधरी ने जब भी संसद के भीतर या बाहर कुछ बोला है, पार्टी को असहज ही किया है। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियां भी बेहद हल्की किस्म की होती ही हैं। यह लगता ही नहीं कि वह पांच बार के सांसद और देश की सबसे पुरानी पार्टी के लोकसभा में नेता हैं।

देविंदर सिंह के मामले में अधीर रंजन चौधरी का बेहूदा बयान राजनीति की गरिमा को गिराने वाला ही नहीं, सार्वजनिक विमर्श को छिछले स्तर पर ले जाने वाला भी है। आखिर जब जम्मू-कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देविंदर सिंह के साथ एक आतंकी सरीखा व्यवहार किया जाएगा तब फिर अधीर रंजन या फिर अन्य किसी को हिंदू-मुस्लिम का सवाल खड़ा करने की क्या जरूरत थी? आखिर कांग्रेस हर मामले में हिंदू-मुस्लिम का सवाल खड़ा करने को आतुर क्यों है? नागरिकता संशोधन कानून के मामले में वह कुल मिलाकर यही कर रही है और वह भी बड़े ही भोंडे ढंग से। वह नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए हर तरह के छल-छद्म का सहारा लेने में जुटी हुई है और वह भी तब जब इस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना ही नहीं। यदि कांग्रेस अथवा अन्य किसी दल के नेता राजनीतिक विमर्श के स्तर को गिराएंगे तो वे पार्टी को रसातल में ही ले जाएंगे।

पलायन पर अंकुश

चीन सीमा से सटे उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बन चुका है। प्रदेश में 1700 से ज्यादा गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जबकि ऐसे गांवों की भी बड़ी संख्या है, जहां अब इक्का दुक्का लोग ही रह रहे हैं। पलायन की इस प्रवृत्ति से शहरी क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार इस मसले पर गंभीर हुई है। पलायन आयोग का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट पर अमल करने की कवायद भी जारी है। सरकार रिवर्स पलायन पर फोकस कर रही है। जल्द ही ऐसे लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिन्होंने शहरों से गांव लौटकर कुछ कर दिखाया हो। इसके अलावा अब एक और योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। योजना को नाम दिया गया है 'आइ एम ए विलेज (मैं एक गांव हूं)'। इसके तहत प्रदेश में 95 ब्लाक में एक-एक गांव को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। योजना के तहत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए चुने गए गांवों को एक से डेढ़ करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। दअरसल पलायन के कारण पहाड़ों में खेत बंजर हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो करीब दस साल पहले राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का हिस्सा सात फीसद था, जो अब घटकर 4.67 फीसद पर आ गई है। 72 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर में तब्दील हुई है। वैसे राज्य गठन के वक्त जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 14 फीसद थी। जाहिर है सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन योजना कितनी फलीभूत होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बावजूद इसके कुछ सवाल अपनी जगह मौजूं हैं। सच यह है कि योजनाएं बनती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन्हें जमीन पर उतारना है। मसलन सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इस समिट के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे, लेकिन अब तक यह साफ नहीं है कितने निवेशकों ने प्रदेश में रुचि दिखाई और जिन्होंने रुचि दिखाई, उनके प्रस्ताव कहां तक पहुंचे। इसके साथ ही पहाड़ को लेकर उद्यमियों का रुख क्या रहा है। दूसरा सरकार की होम स्टे जैसी योजनाओं को मिल रहा रिस्पांस कैसा है। इस योजना की धरातलीय स्थिति क्या है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खाली होते गांवों को आबाद करने के लिए सरकार योजनाएं तैयार कर रही है, लेकिन यह तभी संभव है जब योजनाएं जमीन पर उतरें

वैचारिक असहिष्णुता का प्रदर्शन

डॉ. एके वर्मा

आज वामपंथी और मध्यमार्गी-वामपंथी भाजपा से यह उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वह उनके हिसाब से चले?

आज देश में विचारधाराओं के संघर्ष से वैमनस्य और उन्माद उपज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा-राजग सरकार बनने के बाद यह और ज्यादा मुखर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद केरल और त्रिपुरा वामपंथी गढ़ हुआ करते थे, लेकिन देश के अन्य भागों जैसे कानपुर (जहां कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ), बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र आदि में भी उनकी उपस्थिति रहती थी। बंगाल में 1977 से करीब 30 वर्षों तक वामपंथी सरकार रही। आज केरल के अलावा हर जगह से वामपंथी सरकार साफ हो चुकी है। 1990 के दशक में सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत और कम्युनिस्ट चीन में उदारवाद के अभ्युदय से वामपंथ की नींव हिल गई। भारत में वामपंथ की अस्मिता पर ग्रहण लग गया, जिसे बचाने हेतु कई क्षेत्रों में उग्र-वामपंथ और नक्सलवाद का फैलाव हुआ। आज जेएनयू की हिंसा को वामपंथी अस्मिता संकट के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, अन्यथा शीर्ष वामपंथी नेता समस्या के साथ नहीं, वरन केवल वामपंथी छात्रों के साथ ही क्यों खड़े दिखाई देते?

भारतीय लोकतंत्र वैचारिक स्पर्धा का खुला मंच है। संविधान इस स्पर्धा को मान्यता देता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है-इंडिया, दैट इज भारत अर्थात जिसे हम 'इंडिया' कहते हैं वह 'भारत' है। जो लोग देश को 'इंडिया' के रूप में परिभाषित करते हैं वे प्रगतिशील और वामपंथी कहलाते हैं और जो उसे 'भारत' के रूप में देखते हैं उन्हे दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी, संघी और भाजपाई कहा जाता है। इस प्रकार इंडिया और भारत परस्पर विरोधी विचारधाराओं के प्रतीक हैं। इंडिया शब्द का वजूद तो नया है जो 17वीं शताब्दी से प्रयोग हुआ, लेकिन भारत का विचार तो हजारों वर्ष पुराना है जिसमें 'वयं ब्रह्मास्मि' (हम सब ब्रह्म हैं) और 'वसुधैव कुटुंबकम' (संपूर्ण धरती परिवार है) की अवधारणाएं समाहित हैं। वे समस्त मूल्य और सांस्कृतिक तत्व समाहित हैं जो भारतीयता के प्रतीक थे। इंडिया के प्रयोग से हमें यूरोपीय लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाकर शिष्ट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद हम भूल गए कि ये सभी हमारी संस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग रहे हैं। पाश्चात्य जगत हमें समानता का क्या पाठ पढ़ाएगा? विश्व में आज लैंगिक-समानता की बात हो रही है, पर भारत में हजारों वर्ष पूर्व आदि शक्ति की परिकल्पना 'अर्ध-नारीश्वर' के रूप में की गई, जिसमें स्त्री-पुरुष समानता अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में विद्यमान है। बंधुत्व में हमसे आगे कौन हो सकता है जहां वसुधा को परिवार माना गया और बेंथम के 'अधिकतम लोगों' और मार्क्स के 'सर्वहारा' से आगे जाकर 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की परिकल्पना की गई। इसी प्रकार, सेक्युलरिज्म और सहिष्णुता को आधुनिक संकल्प मानकर 'आइडिया ऑफ इंडिया' को परिभाषित किया जाता है, लेकिन प्राचीन भारत में असंख्य पंथों एवं असीमित विभिन्नताओं वाले सामजिक परिवेश का अस्तित्व प्रमाणित करता है कि जब यूरोप सेक्युलरिज्म और सहिष्णुता से अपरिचित था तब भारत में ये संकल्प सामाजिक-संस्कृति की आधारशिला थे। संविधान निर्माताओं ने पश्चिम से कुछ ग्रहण किया जरूर, पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सेक्युलरिज्म और सहिष्णुता जैसे संकल्पों की संपदा तो स्वयं हमारे पास थी। इसीलिए उन्होंने 'इंडिया' को 'भारत' की पहचान दी।

अवधेश राजपूत

संविधान में किसी को भी हीन या अछूत नहीं समझा गया है। जनता भी विचारधारा को लेकर सहिष्णु है अन्यथा बंगाल, त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों में वामपंथ को स्वीकारने के बाद वह उसे अस्वीकृत क्यों करती? एक लंबे समय तक देश में मध्यमार्गी-वामपंथी कांग्रेस को सत्ता देने के बाद वह उसे अपदस्थ कर दक्षिणपंथी भाजपा को सत्ता क्यों देती? मूल प्रश्न है कि जनता किन परिस्थितियों में किस विचारधारा को स्वीकार करती है और क्यों? जिस दल को जनादेश मिलता है उसे अपनी विचारधारा के अनुरूप नीतियां बनाने, निर्णय लेने, नियुक्तियां करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेहरू के समय से यही सिलसिला चला आ रहा है। आज वामपंथी और मध्यमार्गी-वामपंथी क्यों भाजपा से उम्मीद करते हैं कि वह उनके हिसाब से चले?

वास्तविक लोकतांत्रिक सहिष्णुता तो यही है कि आज मोदी को अपना काम करने दो, कल जब तुम फिर आना तो अपने हिसाब से काम करना। आज यदि मोदी के लिए 'ताजमहल' से ज्यादा 'गीता' आइडिया ऑफ इंडिया को व्यक्त करती है तो वामपंथ को आपत्ति क्यों? अगर पिछले 70 वर्षों में भारतीय विश्वविद्यालयों में वामपंथियों की नियुक्ति हुई है तो अब दक्षिणपंथियों की नियुक्ति पर सवाल क्यों? आज कांग्रेस और वामपंथी विपक्ष के सामने अस्मिता का संकट है। वामपंथी तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्वीकृत हो चुके हैं। फिर वे करें क्या? उनके लिए मोदी सरकार की हर बात बुरी है, हर नीति खराब है, हर निर्णय खोटा है, हर कार्यक्रम धोखा है अन्यथा मोदी सरकार की प्रत्येक बात का वे इतना संगठित और सतत विरोध क्यों करते? जिस तरह नागरिकता के मुद्दे पर अनेक दल विरोध को हवा दे रहे हैं और मुद्दों को उलझाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं उसमें शांत और बौद्धिक विमर्श का स्थान बचा ही कहां है?

हाल में केरल में 'इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस' में मुख्य अतिथि राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के साथ वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब ने जैसी बदसुलूकी की वह वामपंथ की वैचारिक असहिष्णुता की एक बानगी भर थी। विपक्ष यह नहीं समझ पा रहा कि लोकतंत्र में तर्कपूर्ण असहमति और विरोध अनिवार्य है, पर उसमें अभद्रता, संघर्ष और विद्रोह को मान्यता नहीं। आज विपक्ष ने संघर्ष और विद्रोह की लीक पकड़ ली है। ऐसे लोकतंत्र में समाधान के दो रास्ते होते हैं। एक सैनिक हस्तक्षेप और दूसरा जन-हस्तक्षेप। कोई भी दल सैन्य-हस्तक्षेप नहीं चाहेगा। तो दूसरा विकल्प जन-हस्तक्षेप का ही बचता है, जिसमें दो मार्ग हैं। एक हमें सिविल-वॉर और दूसरा चुनावों की ओर ले जाता है। अमेरिका में हम दोनों का प्रयोग देख चुके हैं जहां रंगभेद को लेकर दक्षिणी और उत्तरी राज्यों में 1861-65 के बीच सिविल-वॉर हुआ, लेकिन आज वह एक विकसित राष्ट्र है और अपवादों को छोड़ अमेरिकी समाज समावेशी-सभ्य माना जाता है। बेहतर होता कि वामपंथी और मध्यमार्गी-वामपंथी कुछ वैचारिक सहिष्णुता का परिचय देते और भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी विचारधारा को भी स्पेस देते जिससे लोकतंत्र और संविधान की छत्रछाया में जनता को वैचारिक स्पर्धा का आनंद मिलता और समाज एवं राज्य लोक-कल्याण और विकास में आगे बढ़ते रहते।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और पहल

रमेश कुमार दुबे

एक देश-एक राशन कार्ड योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के साथ ही गरीबों का भला भी करेगी

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी और वन रैंक वन पेंशन के बाद एक देश-एक राशन कार्ड की परिकल्पना को साकार कर केंद्र सरकार देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को नया रूप देने के साथ ही एक तरह से देश को आर्थिक रूप से एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से अपने कोटे का अनाज ले सकेंगे। एक जनवरी 2020 से केंद्र सरकार ने देश के 12 प्रांतों में एक देश-एक राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए पहले 1 जून 2020 की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन अब इसे 15 जनवरी 2020 से लागू करने की तैयारी है। 30 जून तक सभी राज्यों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। इससे न सिर्फ कोटेदारों की मनमानी रुकेगी, बल्कि उनके भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इसका सबसे अधिक फायदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों विशेषकर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा।

पीडीएस पर गठित वाधवा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उचित दर की दुकान ही भ्रष्टाचार का केंद्र हैं। यहां जनता को ठगने के लिए दुकान मालिक, ट्रांसपोर्टर, नौकरशाह और नेताओं में साठगांठ है। इसी साठगांठ के चलते खाद्यान्न की कालाबाजारी होती है और योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने 2014 से ही राशन कार्डों का डिजिटलाईजेशन शुरू किया और अब तक यह किया जा चुका है। इतना ही नहीं 90 प्रतिशत राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं। इसमें 2.98 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए, जिन्हें रद कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी था कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी होने वाले राशन कार्ड एक मानक प्रारूप में हों। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक प्रारूप जारी किया गया।

जिन प्रांतों में उचित दर की दुकानें शत प्रतिशत ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से युक्त हो चुकी हैं वहां पीडीएस लाभार्थी अब किसी भी प्रदेश में निवास करते हुए अपने मौजूदा राशन कार्ड से ही अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर रहे हैं। जल्द ही देश की सभी ऐसी दुकानों को प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से जोड़ दिया जाएगा। पीडीएस के लाभार्थी खाद्यान्न से वंचित न रह जाएं, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी जा रही हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन भी काम करेंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 75 फीसद ग्रामीण आबादी और 50 फीसद शहरी आबादी को केंद्र सरकार रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया करा रही है। इसके लिए देश में 23.18 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं। कुल संख्या को देखें तो केंद्र सरकार देश में 81 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न मुहैया कराती है।

2018-19 की आर्थिक समीक्षा में तेजी से बढ़ती खाद्य सब्सिडी का हल ढूंढ़ने की जरूरत पर बल दिया गया था। इतनी भारी-भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद देश में यदा-कदा भुखमरी की खबरें आती रहती हैं तो इसका कारण है कि खाद्यान्न का वितरण जिस पीडीएस के माध्यम से होता है वह भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। पीडीएस में सुधार पर गठित वाधवा समिति ने यह पाया था कि 42 फीसद अनाज राशन की दुकानों से निकल कर कालाबाजारी के लिए पहुंच जाता है। पूर्वोत्तर प्रांतों में तो 97 फीसद अनाज बाजार में पहुंच जाता है। इसके बावजूद तमिलनाडु, केरल, आंध्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पीडीएस अच्छी तरह चल रही है। पीडीएस सुधार के लिए छत्तीसगढ़ में पीडीएस की सफलता रोल मॉडल बन सकती है।

2004 तक छत्तीसगढ़ में पीडीएस की कहानी उत्तर भारत के किसी भी राज्य से अलग नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा तीन स्तरों पर किए गए उपायों ने तस्वीर ही बदल दी। सबसे पहले सरकार ने अति गरीबों और आदिवासियों को घर के नजदीक अनाज मुहैया कराने के लिए उचित दर की दुकानों के लाइसेंस निजी व्यापारियों के बजाय स्थानीय समुदाय को सौंप दिए। इसका लाभ यह हुआ कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से दुकानें पूरे दिन खुलने लगीं और गांव वाले अपनी सुविधानुसार राशन लेने लगे। दूसरा सुधार राशन की दुकानों की संख्या बढ़ाकर किया गया। हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक दुकान खोली गई। इससे राशन लेने की लंबी कतारों में कमी आई और कम समय में ही राशन मिलने लगा। तीसरा सुधार दुकानों तक अनाज पहुंचाने में किया गया। इसके तहत हर महीने की छह तारीख तक पीले रंग के विशेष ट्रकों में पूरी सामग्री सीधे दुकानों तक पहुंचाई जाने लगी। सरकार ने दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ा दिया जिससे उनका घाटा कम हुआ और उन्होंने अनाज को बाजार में बेचना कम किया। फर्जी राशन कार्डों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने पुराने राशन कार्डों को खत्म कर नए प्रकार के कार्ड जारी किए। इन कदमों से पीडीएस की लागत भले बढ़ी, लेकिन अनाज की कालाबाजारी रुकी और गरीबों के मुंह में निवाला पहुंचने लगा।

सरकार भ्रष्टाचार की जड़ पर हमला करने के लिए प्रत्येक स्तर पर तकनीक रूपी चौकीदार बैठा रही है। पिछले पांच वर्षों में सरकार राशन कार्ड, रसोई गैस, छात्रवृत्ति और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं से जुड़े छह करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर कर चुकी है। इससे सरकारी खजाने में 90,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। एक देश-एक राशन कार्ड योजना भी भ्रष्टाचार मिटाने और वास्तविक लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संयम का महत्व

संयम वह गुण है जिससे व्यक्ति सफलता के शीर्ष को स्पर्श कर सकता है। यह गुण हमारी आत्मिक शक्ति को सबलता प्रदान करता है। यह चारित्रिक परिष्कार का कारक है। संयमी व्यक्ति के भीतर अथाह सामर्थ्य का भंडार संग्रहित होता है। संयम का पोषण सद्विचारों एवं सत्संगति से ही संभव है। अच्छे विचार संयमी प्रभाव में वृद्धि करते हैं। सत्संगति भी संयम के जन्म का कारक है। अच्छे परिवेश, भद्रजनों के सामीप्य से संयम प्राणवान होता है। संयम का गुण ही इस नश्वर शरीर को अमरता प्रदान करता है, क्योंकि संयम व्यक्ति को सद्कार्यों के लिए उद्वेलित करता है। यह नकारात्मकता को पास नहीं फटकने देता। संयम एवं नकारात्मक विचारों का आपस में बैर है।

महात्मा गांधी ने कहा था, 'जब साहस के साथ संयम और शिष्टाचार जुड़ जाता है, तो वह व्यक्ति अनूठा हो जाता है।' अर्थात् व्यक्तित्व में अनूठेपन के लिए संयम का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति में मौलिक विशिष्टता उसके संयम से पोषित होती रहती है। पश्चिमी विचारक रूसो से जब संयम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि, 'संयम मनुष्य के जीवन में नई रोशनी उत्पन्न कर देता है।' स्पष्ट है कि संयम में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को प्रकाशवान बना सके।

वाणी का संयम व्यक्ति को प्रखर बना देता है। वाणी संयम एक तरह से वाक् सिद्धि है। जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया वह व्यक्ति अद्वितीय हो जाता है। लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगते हैं। वहीं इंद्रिय संयम व्यक्ति की प्रकृति को अजेय बना देता है। जितेंद्रिय व्यक्ति स्वतः संस्कारों की खान में प्रवर्तित हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व सदैव अनुकरणीय होते हैं। संयमी जीवनचर्या एक आदर्श जीवनचर्या है। नवयुग का निर्माण संयमी युवा शक्ति के सहयोग से संभव है। किसी भी राष्ट्र की युवा पीढ़ी यदि संयमी है तो निश्चित ही उसका सामाजिक परिवेश पावन होगा और वह राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा।

ललित शौर्य

विविधता में एकता की मिसाल है सेना

पीएन खेड़ा

पिछले सात दशकों में भारतीय सेना एक पेशेवर, गैर-राजनीतिक और मानवीय सेना के रूप में उभरी है

हर साल भारतीय सेना 15 जनवरी को सेना दिवस मनाती है। यह दिन 1949 के उस दिन की याद में मनाया जाता है, जिस दिन जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) केएम करिअप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल सर एफआरआर बूचर से सशस्त्र सेनाओं की कमान संभाली थी और वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रथम कमांडर-इन-चीफ बने थे। पिछले सात दशकों में भारतीय सेना एक पेशेवर, गैर-राजनीतिक और मानवीय सेना के रूप में उभरी है। दुनिया की किसी भी सेना को शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे के सियाचिन के तापमान पर और 50 डिग्री के तपते थार मरुस्थल के तापमान पर लड़ने का अनूठा अनुभव हासिल नहीं है। हमारे जवानों को पश्चिम के रेगिस्तान तथा मैदानी इलाकों में भी और उत्तर-पूर्व में घने जंगलों तथा बीहड़ों में भी युद्ध का अनुभव है।

लघु भारत के रूप में विख्यात, भारतीय सेना में सभी प्रांतों, सभी जातीय संस्कृतियों के तथा अलग-अलग भाषा बोलने वाले जवान हैं। वे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते-पीते हैं और राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक साथ युद्ध लड़ते हैं और इस प्रकार 'विविधता में एकता' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जवानों की धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यूनिटों में 'सर्व धर्म' मंदिर होते हैं, जहां सभी धर्मों के जवान, अपनी-अपनी आस्थाओं के अनुसार पूजा कर सकते हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से जवानों ने सभी लड़ाइयों में सम्मान पाया है, वहीं प्राकृतिक तथा इंसानों द्वारा उत्पन्न आपदाओं में भी देशवासियों की मदद करके उनका प्यार और आभार अर्जित किया है। भारतीय सेना, उग्रवाद-विरोधी, आतंकवाद-विरोधी अभियानों और पाकिस्तान द्वारा चलाए गए परोक्ष युद्ध में भी कृतज्ञ राष्ट्र की शाबाशी का पात्र बनी है।

भारतीय सेना का इतिहास, उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 1962 में हिमालय की पहाड़ियों पर उसे चीनियों के हाथों हार का अंधेरा देखना पड़ा था, लेकिन बाद में उसने 1965 और फिर 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के रूप में और फिर 1999 में बहुत ही दिक्कतों से भरे दुर्गम युद्धक्षेत्र-कारगिल की शानदार विजयों से उसे जग-मग कर दिया। कारगिल में भारतीय जवानों ने लगभग सीधी चढ़ाई वाली चोटियों पर मजबूती से जमी हुई पाकिस्तान सेना के पांव उखाड़ कर तिरंगा फहराया। अपनी सीमाओं से परे भारत की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कारगिल ने दिखा दिया है कि भारतीय इलाके पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश की स्थिति में सेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई होगी और समुद्र में नौसेना मोर्चा संभालेगी और दुश्मन की बंदरगाहों की नाकाबंदी करेगी। यही परस्पर कार्रवाई की नई रणनीति होगी।

कुल मिलाकर जनरल केएम करिअप्पा ने जिस भारतीय सेना को संवारा उसे आज भी जनरल बूचर द्वारा बोए गए कांटों को निकालने के अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करना है। -(अडनी)

मेलबाक्स

आर्थिक विकास का मंत्र

आम आदमी की आमदनी बढ़ाए सरकार शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. भरत झुनझुनवाला ने भारत सरकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में दिख रही मांग की कमी को दूर करने के लिए आम आदमी की आय बढ़ाने पर विचार करने की सलाह दी है। इसको संभव बनाने के लिए लेखक का मानना है कि सरकार को वित्तीय घाटे की चिंता छोड़कर आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना चाहिए। ध्यातव्य है कि वित्तीय अनुशासन पर कोई भी लापरवाही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्महत्या करने के समान होगा। इससे दो तरह की कठिनाई आएगी। पहली तो यह कि इस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख गिरेगी। ऐसा होने पर भारत सरकार के लिए न सिर्फ विश्व बैंक और आइएमएफ जैसी संस्थाओं से ऋण लेना मुश्किल होगा, बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत में पूंजी निवेश करने से कतराएंगे। यह स्थिति देश में रोजगार की संभावनाओं को कम करेगी। अल्प रोजगार की स्थिति मांग में कमी की वर्तमान समस्या को अंततः बढ़ाएगी ही। राजकोषीय अनुशासन के भंग होने की स्थिति में जिस दूसरी कठिनाई का जिक्र मैंने पहले किया है, उसे हम ऐसे समझेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, 'इन इकोनॉमिक्स देयर इज नो फ्री लंच'। सरकार का पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने का मतलब है कि सरकार पहले से ज्यादा पैसे उधार भी लेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों के उधार लेने के लिए कम पैसे बचेंगे। ऐसे माहौल में ब्याज दरें गिर नहीं पाएंगी। तब घरेलू उद्यमियों के पास निवेश के लिए पैसे कहां से आएंगे? मूल बात यह है कि राजकोषीय अनुशासन के प्रति अनदेखी विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के निवेश को कमजोर करने का काम करेगी, जिससे रोजगार और मांग की वर्तमान समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। मेरा मानना है कि भारत सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान सुस्ती को दूर करने के लिए अल्पकालीन उपाय के साथ-साथ दीर्घकालीन रणनीति पर भी काम करना चाहिए। युवाओं का कौशल विकास, आधुनिक कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा तथा नवाचार पर जोर, इन मंत्रों में ही अर्थव्यवस्था की खुशहाली के बीज छिपे हुए हैं।

चंदन कर्ण, देवघर

महंगाई के तर्क गलत

दैनिक जागरण के 14 जनवरी के अंक में प्रकाशित डॉ. भरत झुनझुनवाला का लेख, आम आदमी की आमदनी बढाए सरकार, में तर्क दिया है कि वर्तमान में जन-सामान्य की आय घटी है, इसलिए बाजार में मांग कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा है तो खुदरा महंगाई की दर ऊंची कैसे है? और मांग कम है तो माल की बिक्री अधिक क्यों? अधिक बिक्री का प्रमाण पिछले नवंबर और दिसंबर महीनों में जीएसटी एक लाख करोड़ से बढ़कर के रहना है। लेखक ने राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास को केवल बड़ी कंपनियों के हित में बताया है जो जहाजों में माल भेजकर छोटे नाविकों के पेट पर लात मार रहे हैं। छोटे नाविकों द्वारा माल-ढुलाई पर किसी प्रकार का प्रतिबंध तो सरकार ने लगाया नहीं, जिसे माल भेजना नावों से पसंद है या लाभदायक लगता है, वह अब भी उनका प्रयोग करते हैं। छोटे व्यापारी अब भी ऐसा कर ही रहे हैं। ट्रेनों से एक साथ कई ट्रक माल जाता है, इस कारण बड़ा ट्रक तो छोडिये, मिनी ट्रकों और बैलगाड़ियों तक से माल-परिवहन बंद तो नहीं हो गया। आज भी 40-40 किलोमीटर दूरी तक बहुत सा माल ऊंटगाड़ियों द्वारा भेजा जाता है। लेखक मानकर चल रहे हैं कि इस वर्ष अमरीका-ईरान तनाव के कारण तेल के दाम चढ़ेंगे।

amittalmrt2@gmail.com

ईरान की लापरवाही

आखिरकार ईरान ने अपनी ही मिसाइल से यूक्रेन के विमान के नष्ट होने की बात कबूल कर ली। इस विमान में सवार 176 लोगों की मौत हुई, जिसमें अधिकतर यात्री ईरान के ही थे। इससे यह साफ है कि बदले की आग में धधक रहे ईरान ने उन निर्दोष लोगों की जान ली है। ईरान ने बेहद गैरजिम्मेदारी से घटना को अंजाम दिया है। साथ ही उसने यह भी रेखांकित कर दिया है कि वह अब परमाणु हथियार हासिल करने का बिल्कुल हक नहीं रखता।

rumasingh12345@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएड

85 प्रतिशत कच्चे तेल के हिस्से का आयात करता है भारत को अपनी कुल खपत का। 2018-19 में भारत ने लगभग आठ लाख करोड़ रुपये मूल्य के 22.6 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था।

आजकल

विमानों की सुरक्षा पर मंडराता खतरा

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

दुनिया में जिस तरह से मिसाइलों का जोरशोर से निर्माण और तनातनी की स्थिति में उनके इस्तेमाल के वाकयों में इजाफा हो रहा है, उससे यात्री विमानों की सुरक्षा सतत खतरे में बनी हुई है। कुछ देशों में आतंकी शिविरों की मौजूदगी और पड़ोसी देशों से उनके संबंधों में तल्खी आदि कारणों से भी यात्री परिवहन विमानों की सुरक्षा दांव पर लग गई है। यूक्रेन के एक यात्री विमान का ईरान के बदले की कार्रवाई की चपेट में आ जाने की घटना ने पूरी दुनिया को घोर चिंता में डाल दिया है

यह किसने सोचा था कि अमेरिका और ईरान के संबंधों में अर्से से चली आ रही तनातनी वर्ष 2020 की शुरुआत के साथ ही एक सैन्य कमांडर की मौत और एक नागरिक विमान को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने के अंजाम तक पहुंच जाएगी। अफसोस यह सब हुआ और अब ईरान और अमेरिका तक में पछतावे का आलम है। इस घटनाक्रम की हालिया शुरुआत का एक सिरा बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक ईरान के सर्वोच्च सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से जुड़ा है, जिसे अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया। इससे भड़के ईरान ने बदले की कार्रवाई की बात कही और आठ जनवरी, 2020 को इराक स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दाग दीं, लेकिन घटनाक्रम में एक दुखद मोड़ तब आया जब तेहरान से उड़ा यूक्रेन इंटरनेशनल का यात्री विमान-752 ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया और इसमें सवार सभी 176 निर्दोष यात्री एवं क्रू मेंबर मारे गए। विमान में ईरान के 82 लोगों के साथ 63 कनाडाई, यूक्रेन के 11, स्वीडन के 10, अफगानिस्तान के 4, जर्मनी के 3 और यूके के 3 लोग सवार थे।

सड़क पर ईरानी जनता

यूक्रेन के यात्री विमान का बदले की इस कार्रवाई की चपेट में आ जाने की घटना ने पूरी दुनिया को घोर चिंता में डाल दिया है। यह एक बड़ी गलती थी-शुरुआत में इसका अहसास ईरान को नहीं हुआ। इसके उलट ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इसे तकनीकी खामी की वजह से हुआ एक हादसा कहा और दावा किया कि अमेरिका उनके देश को बदनाम करने की नीयत से यह अफवाह फैला रहा है। उनके बयान के कुछ समय बाद ईरान ने कहा कि यह यात्री विमान एक मिलिट्री बेस के पास से गुजर रहा था, इसलिए गलती से मिसाइल से उसे मार गिराया गया गया, लेकिन उपग्रहों से मिली तस्वीरों और गूगल से मिली जानकारियों से पता चल गया कि विमान की उड़ान के रास्ते में कोई मिलिट्री बेस नहीं था। मिसाइल के हमले के तुरंत बाद जिस जगह विमान से संपर्क टूटा, वहां एक पॉवर प्लांट और इंडस्ट्रियल पार्क है।

इसके बाद ईरान को अपनी गलती का अहसास हुआ और तब अयातुल्ला अली खामनेई ने इसे एक महाभूल करार दिया, लेकिन ईरान का कबूलनामा उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों ने जहां ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ईरान सरकार से आधिकारिक माफी मांगने की मांग के साथ घटना की पूरी जांच और मुआवजे की मांग कर दी है। सबसे बड़ी समस्या खुद ईरान के अंदर उठ खड़ी हुई है। ईरानी नागरिक इसके विरोध में सड़क पर आ गए हैं।

आतंकियों के निशाने पर विमान

दुनिया में जिस तरह से मिसाइलों का जोरशोर से निर्माण और तनातनी की स्थिति में उनके इस्तेमाल के वाक्यों में इजाफा हो रहा है, उससे यात्री विमानों की सुरक्षा सतत खतरे में बनी हुई है। कुछ देशों में आतंकी शिविरों की मौजूदगी और पड़ोसी देशों से उनके संबंधों में तल्खी आदि कारणों से भी यात्री परिवहन विमानों की सुरक्षा दांव पर लग गई है। हाल में इन्हीं खतरों के मद्देनजर अमेरिका में पाकिस्तान के संबंध में ऐसा ही एक अलर्ट जारी किया था। तीन जनवरी, 2020 को जारी इस चेतावनी परामर्श (एडवाइजरी) में अमेरिका के विमानन नियामक (एफएए) ने सभी अमेरिकी निजी, व्यावसायिक और सरकारी एयरलाइन कंपनियों और विमानों के पायलटों को चेताया था कि वे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से बचें। इस एडवाइजरी में आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान में सक्रिय चरमपंथी और आतंकी समूह अमेरिकी विमानों को निशाना बना सकते हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच पाकिस्तान में सिविल एविएशन को निशाना बनाने की आतंकियों की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में सक्रिय कट्टरपंथी और आतंकी तत्वों की मौजूदगी से अमेरिकी विमानों पर छोटे हथियारों, एयरपोर्ट पर हमले और एंटी-एयरक्राफ्ट गन के जरिये निशाना बनाए जाने की लगातार जोखिम है। ऐसी स्थिति में यदि किसी आकस्मिक स्थिति में या भूलवश पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल करना पड़े तो विशेष सावधानियां बरतें। पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर न रुकें और वहां के हवाई क्षेत्र में कम ऊंचाई पर उड़ान न भरें। कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान विमानों को आतंकी हमले और अपहरण का खतरा है। इस परामर्श में 2019 में इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और 2015 में बलूचिस्तान और पेशावर में पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डों पर आतंकी हमलों का जिक्र किया गया है।

सुरक्षा के क्या हैं उपाय

सवाल है कि आखिर दुनिया यात्री विमानों की सुरक्षा के लिए ऐसी चेतावनियां जारी करने के अलावा और क्या करती है? दो देशों के संबंधों में अचानक पैदा होने वाली स्थितियों के मद्देनजर पहला उपाय विमानों की उड़ानें बंद करने के रूप में होता है। मिसाल के तौर पर पिछले वर्ष कश्मीर में पुलवामा में किए गए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की आशंका के तहत हिमाचल प्रदेश के गगल, भुंतर और शिमला एयरपोर्ट से नागरिक विमानों की उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थीं। अब से करीब साढ़े पांच साल पहले एक हादसा उसी यूक्रेन में हुआ था, जिसका विमान ईरान में मार गिराया गया है।

पहले विमानन अधिकारी सोचते थे कि देशों की सेनाओं द्वारा नियंत्रित लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग 30 हजार फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे व्यावसायिक विमानों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2014 के मलेशिया एयरलाइंस के हादसे ने इस नजरिये को बदल दिया। उस वर्ष 17 जुलाई को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या-17 को रूस निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली बर्क मिसाइल से मार गिराया गया था। उस घटना में 15 क्रू मेंबर्स सहित सभी 283 यात्री मारे गए थे। इनमें 80 बच्चे थे। दावा किया गया कि वह मिसाइल यूक्रेन में सक्रिय रूस समर्थित विद्रोहियों ने छोड़ी थी। उस घटना के बाद दुनिया भर के नागर विमानन क्षेत्र में हलचल मची थी। अब ईरान की कार्रवाई इस खतरे को एक नए मुकाम पर ले आई है। सवाल यह है कि इन खतरों से कैसे बचा जाए? यहां चिंता यह है कि ऐसे खतरे सामने आने के बाद भी दुनिया में उनसे निपटने की संगठित पहल नहीं होती है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन यूनियन के यूरो कंट्रोल सहित राष्ट्रीय एजेंसियां खतरनाक क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी कर सकती हैं या उन मार्गों को प्रतिबंधित कर सकती हैं, लेकिन केवल संबंधित देश ही सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर सकते हैं। इसलिए नागर विमानन विशेषज्ञों का तर्क है कि इस बारे में एक उपाय यह हो सकता है कि एयरलाइंसें ही तय करें कि किसी खास हालात में उनके लिए कौन से रूट सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन यहां समस्या यह है कि एयरलाइंसें तो सरकारों के इशारे का इंतजार करती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सरकारों को पहल करनी चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि दुनिया में सिर्फ ईरान-इराक या यूक्रेन ही यात्री विमानों के लिए खतरनाक जोन नहीं हैं। सीरिया और यमन में भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का उपयोग होता है, लेकिन वहां यात्री विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं है।

भारत की तैयारी

इसके अलावा यात्री विमानों को कुछ खतरे आंतरिक भी हो सकते हैं। इन आशंकाओं को देखते हुए पिछले वर्ष (दिसंबर, 2019) में वायु क्षेत्र के नियमन को मजबूत करने के लिए हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करने के लिए विमान (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और वर्तमान कानून का दायरा भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आइसीएओ) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इन संशोधनों के तहत विमान में हथियार, गोला-बारूद या खतरनाक सामान ले जाने या किसी भी तरह से विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्ति पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसमें किए जाने वाले संशोधनों से भारत के तीनों विमानन नियामकों-उड्डयन महानिदेशालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में सहायता मिलेगी।

इन हादसों को न भूले दुनिया

ईरान में यूक्रेन एयरलाइंस के एक विमान को मिसाइल से मार गिराने से पहले विश्व में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस क्रम में पहली घटना वर्ष 1938 की है जिस दौर में चीन-जापान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। 24 अगस्त, 1938 को हांगकांग के उत्तर में चीनी इलाके में ही पैन अमेरिकन और चीन की एयरलाइंस सीएनएसी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक यात्री विमान को जापानी एयरक्राफ्ट ने पानी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया। नदी में उतरते ही वह विमान डूब गया, जिससे उसमें सवार 18 में से 15 यात्रियों की मौत हो गई थी। 20 अप्रैल, 2001 को एक विमान को पेरू के लड़ाकू विमान ने मार गिराया था, जिससे चार विमान सवारों में से दो की मौत हो गई थी। उसी वर्ष 4 अक्टूबर, 2001 को इजरायल से रूस जा रहा सर्बिया का यात्री विमान ब्लैक सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दावा है कि उस विमान को आतंकियों ने एस-200 मिसाइल से मार गिराया था। उस घटना के दो साल बाद 22 नवंबर, 2003 को बगदाद से बहरीन जा रहे एक कार्गो विमान पर मिसाइल से हमला किया गया था। एक हादसा 9 जनवरी, 2007 को इराक स्थित बलाड एयरबेस पर हुआ था, जहां एक यात्री विमान लैंडिंग करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में यह दावा सामने आया कि उस विमान को किसी एंटी-एयरक्राफ्ट गन से उड़ाने की कोशिश की गई थी। सोमालिया में 23 मार्च, 2007 को ट्रांसअवीवा एक्सपोर्ट एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना में भी ऐसे ही आतंकी हमले का दावा किया जाता है। यात्री विमान को मार गिराने की बड़ी घटना 2014 में मलेशिया एयरलाइंस को रूसी मिसाइल दागकर नष्ट करने वाली है, जिसे विमानन इतिहास में सबसे ज्यादा यात्रियों की मौतों वाली दुर्घटना की सूची में रखा जाता है। इनके अलावा 27 जून, 1980 को जब इटली ने अपने विमान को मार गिराया था तो उस घटना में 81 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह कोई 3 जुलाई, 1988 की उस घटना को नहीं भूल पाता है, जब अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के यात्री विमान को मार गिराया था। उसमें सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई थी।

खरी-खरी

फूल से चेहरे का फूलदान हो जाना

चेतना भाटी

दिल ढूंढता है फिर वही दिन...जब जाड़ों की दोपहर में आंगन में सन की खटिया पर पड़े हुए स्वच्छ-सुंदर नीले आकाश पर गोल घेरे में पूरे लय-ताल से उड़ती चीलों को निहारा करते थे। इन्हीं उड़ती चीलों के ऊपर से चांदी-सी चमकती चीलगाड़ी भी उड़ती चली जाती। मन की उड़ान के चलते हम सुहावने ढोल देखने को लालायित हो उठते, लेकिन अपनी किस्मत में तो पास के ही ढोल लिखे थे-ढीले, पोले, बेढंगे! बात जब किस्मत की आई तो सोचा क्यों न पंडी जी से पूछ लें भविष्यफल। पंडी जी, देखिए जरा विदेश यात्रा का योग है अपनी कुंडली में? और पंडी जी ने बताया-हां अवश्य। अर्धशतक के बाद। हालांकि इसके लिए कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, यह तो हमारी शक्ल पर ही लिखा था। विदेश यात्रा के लायक धन जुटाने में हमारी आधी से ज्यादा उम्र तो गुजर ही जानी थी। खैर, बी पॉजीटिव-नववर्ष का संकल्प है हमारा। तो आज जब हर कोई ऐसे विदेश जाने लगा है, गोया जैसे गली के नुक्कड़ से पान खाकर आना हो, तो हमारी भी इच्छाएं जाग उठीं। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर बढ़ते रहने से बड़ा लक्ष्य भी हासिल हो ही जाता है। सोचकर हमने धन के बड़े लक्ष्य को सामने से एक ओर खिसका या और छोटा लक्ष्य सामने रखा-पासपोर्ट ही बनवा लें तब तक। पता चला कि ऑनलाइन ही बन जाता है आजकल, लेकिन हम ठहरे ऑफलाइन, पर एजेंटों से भरी दुनिया में चिंता की कोई बात नहीं।

कुछ खानापूरी कर उन्होंने सूचित किया-पासपोर्ट कार्यालय पहुंच जाइए निश्चित समय पर। शेष सब तो ठीक था, हमें तो चिंता थी अपने फोटो की। आखिर हमसे पहले हमारा पासपोर्ट देखा जाएगा तो फोटो तो अच्छा होना चाहिए। कुछ प्रक्रियाओं से गुजरे। आखिर वह क्षण भी आया जब फोटो खींचा जाना था। सो हम कोण बना ही रहे थे कि आवाज आई-सीधे सामने देखिए और कानों पर से बाल पीछे कीजिए। अब हम स्क्रीन पर देख रहे थे। कुछ दिन बाद पासपोर्ट बनकर आ गया। अब हम कभी पासपोर्ट में अपने फोटो को देखते हैं, कभी लंगड़ी दौड़ में जीते अपने कप को। सोच रहे हैं कि उदासी का कौन सा स्टिकर या जीआईएफ सूट करेगा? कुलजमा हम अंग्रेजी वाले फूल लग रहे थे।

ट्वीट-ट्वीट

आतंकवाद की समस्या से लोहा लेने में भारतीय सेना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस देश में सबसे बेहतरीन संगठन है। बीते तीन दशकों में उन्होंने तमाम कुर्बानियां दी हैं। कुछ घटिया लोगों के कारण पूरे संगठन को खराब नहीं माना जा सकता।
आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

महंगाई दर छह साल के उच्चतम स्तर पर है। वहीं जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर छह वर्ष के निम्नतम स्तर पर है। इस स्थिति को सुधारना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी पहचान की राजनीति से जुड़े अंतहीन बहस वाले तमाम मसले अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
चेतन भगत@chetan_bhagat

मोदी सरकार को यह मान लेना चाहिए कि उनके पास प्रतिभाओं का अकाल है। उन्हें अविलंब एक सक्षम टेक्नोक्रेट वित्त मंत्री नियुक्त करना चाहिए। आप तीन ट्रिलिटन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बेतरतीब तरीके से नहीं चला सकते।
सदानंद धूमे@dhume

फासीवाद केवल वामपंथी शासन में ही देखा जा सकता है। केरल के इडुक्की जिले में रविवार को भाजपा के राज्य सचिव एके नाजिर की एक मस्जिद में हुई पिटाई इसका जीता-जागता सुबूत है।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या यूपी सरकार का पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला कारगर साबित होगा?

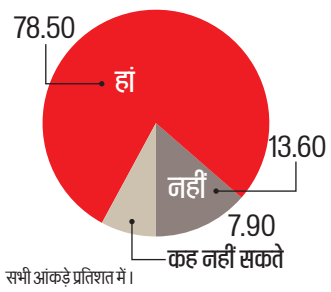

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी अस्थायी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जिन्ना वाली चाहिए आजादी तो जाव,
जाकर पाकिस्तान में हलवा-पूड़ी खाव।
हलवा-पूड़ी खाव तुम्हें किसने है रोका,
नहीं चलेगा और यहां भारत से धोखा।
होना चहिए देश आज उन सब से खाली,
आजादी जो मांग रहे हैं जिन्ना वाली।
- ओमप्रकाश तिवारी

अमित शर्मा
स्थानीय संपादक, पंजाब

पंजाब डायरी

पुलिस के 'डंडे' पर भारी अपराधियों का 'माउस'

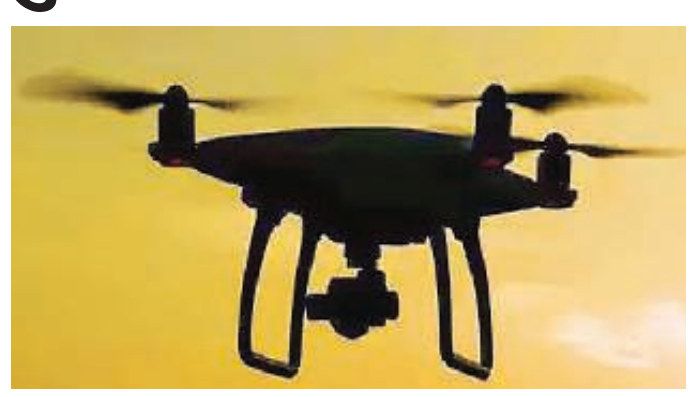

पिछले दिनों पंजाब पुलिस की आधिकारिक फेसबुक आइडी से लाइव होकर पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ड्रोन के जरिये पाकिस्तान से भारत में नशे और हथियारों की डिलीवरी मॉड्यूल का खुलासा कर रहे थे। उसी समय एक फेसबुक यूजर ने कमेंट सेक्शन में ऐसी घटनाओं के दोहराव पर कटाक्ष करते हुए लिखा ''इसे कहते हैं पंजाब पुलिस के 'डंडे' पर 'माउस' का भारी पड़ना।''

बेशक इस शख्स ने ऐसा कमेंट चुटकी लेने के लिए किया हो, लेकिन इस कटाक्ष के मायने इसी में मौजूं है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के बल पर अपराधों के बदलते स्वरूपों की वजह से पंजाब पुलिस के सामने न सिर्फ चुनौतियां बढ़ी हैं, बल्कि आज सख्त जरूरत है 'डंडे' के बल पर देश भर में अपनी धौंस दिखा चुकी धाकड़ पंजाब पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किए जाने की। आधुनिकीकरण के नाम पर वायरलेस या बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने तक सीमित रहने वाली पंजाब पुलिस की नशे से जुड़े आतंकवादी तंत्र की जांच करने की क्षमता सीमित है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां पिछले साल तक केवल पाकिस्तान साइड से भारतीय सीमा में ड्रोन आ रहे थे तो अबकी बार बीते हफ्ते नशे की खेप लाने के लिए भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान सीमा में ड्रोन भेजे जाने के सनसनीखेज मामले सामने आ गए। पुलिस महानिदेशक गुप्ता के अनुसार भारतीय सीमा पर स्थित तरनतारन जिले के एक गांव से यह ड्रोन एक या दो बार नहीं, बल्कि पांच बार अपनी उड़ान भर कर पाकिस्तान से नशा, जाली करेंसी और हथियार इस पार ला चुका था।

अच्छी बात है कि मुस्तैद पंजाब पुलिस ने इस नेटवर्क के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर मॉड्यूल का पता लगा लिया और डीजीपी ने ऐसी बढ़ती चुनौतियों से निपटने को लेकर प्रतिबद्धता और कार्ययोजना का खाका भी पेश किया, लेकिन यक्ष प्रश्न है कि क्या जब ऐसी पहली घटना पांच अगस्त 2019 को सामने आई और उसके बाद सितंबर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिये भारत में हथियार गिराए गए थे तो उसके बाद सूबे की पुलिस ने इस 'टेक्नोलॉजिकल वॉर' से निपटने और फील्ड अफसरों को सक्षम बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए? इस नई चुनौती लिए क्या बॉर्डर जिलों में तैनात पुलिस दस्तों को आधुनिक बनाने की विशेष रूपरेखा तैयार की गई। शायद नहीं! नतीजतन विध्वंसक गतिविधियों के लिए एक वर्ष पहले तक जिस नशे और हथियारों की खेप की उड़ान बॉर्डर पार पाकिस्तान में एक 'माउस' क्लिक से संचालित हो रही थी, वह आठ महीनों के अंतराल में भारतीय सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर और तरनतारन जिलों से ही संचालित होने लगी। यह विडंबना ही है कि आधुनिकीकरण के नाम पर पंजाब पुलिस में कई वर्षों से एक मॉडर्नाइजेशन विंग तो चल रहा है, जिसे डीजीपी रैंक के अधिकारी ही हेड करते हैं, लेकिन बदलते परिवेश में सूबे की पुलिस में आधुनिक प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक उपकरणों की कमी पूरी करने का आज तक कभी कोई ठोस ड्राफ्ट नहीं बन पाया है। और अगर कभी बना भी है तो या तो वह बहुचर्चित वायरलेस स्कैम जैसे घोटालों की भेंट चढ़ गया या हमेशा की तरह आला अफसरों की आपसी राजनीति का शिकार बन फाइलों में ही दब कर रह गया है।

लगातार बदलते आपराधिक परिवेश में आधुनिक टेक्नोलॉजी से दूर अपने 'डंडे' के ही बल पर आगे बढ़ने का दम भरने वाली पंजाब पुलिस के लिए यह चुनौतियां केवल भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स तस्करों या आतंकियों द्वारा ही नहीं पेश आ रही हैं। एक तरह से टेक्नोलॉजी से लैस हर अपराधी के आगे सूबे की पुलिस घुटने टेकती नजर आती है। अब बात चाहे विदेश में बैठे गर्मख्यालियों द्वारा सोशल मीडिया पर रेफरेंडम-2020 जैसे पंजाब विरोधी एजेंडा चलाने की हो या फिर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामलों की, इनकी जांच को लेकर पंजाब पुलिस अपने को ठगा सा ही महसूस करती आई है। और अब रही सही कसर पंजाब के हर शहर में बेखौफ फैलते ड्रैगन डोर के खेल ने पूरी कर दी है। जहां अपनी आपराधिक गतिविधियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से गैंगस्टर्स और अन्य अपराधी एक नए चुनौतीपूर्ण स्तर पर ले जा चुके हैं वहीं प्रदेश की साइबर पुलिस भी अधिकतर मामलों में अभी तक फिसड्डी ही साबित हुई है। यानी वास्तव में ही पंजाब पुलिस के 'डंडे' पर अपराधियों का 'माउस' भारी पड़ रहा है।

चिंता

खाड़ी में तनाव का किसानों पर असर

पुष्पेंद्र सिंह
अध्यक्ष, किसान शक्ति संघ

ईरान से तेल न खरीदने के कारण पहले ही भारतीय चावल की मांग वहां घट रही थी। अब खाड़ी देशों में अस्थिरता को देखते हुए हमारे बासमती चावल की मांग और कीमतों के और नीचे जाने की आशंका है

अमेरिका द्वारा ईरान के एक सैनिक जनरल को मारे जाने और ईरान की फिलहाल सीमित जवाबी कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हमारा देश अपनी मांग के लगभग 85 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है। 2018-19 में हमने लगभग 8 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 22.6 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था जिसमें से लगभग आधा खाड़ी देशों से आया था। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर हमारी तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। यदि कलह बढ़ी तो कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने से हमारा आयात महंगा होगा। डीजल, पेट्रोल, गैस आदि की महंगाई का असर किसान की लागत पर सीधा पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर, डीजल इंजन और अन्य मशीनों को चलाने की लागत बढ़ेगी। महंगाई दर बढ़ने के कारण अपने इस्तेमाल की अन्य वस्तुएं किसान को और महंगी खरीदनी होंगी। रुपये की कीमत गिरने से आयातित खाद के दाम भी बढ़ेंगे। कच्चे तेल से प्राप्त कई उत्पादों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों को बनाने में भी होता है। इस कारण खाद और कच्चे तेल के दाम एक दिशा में चलते हैं। अतः कच्चे तेल के महंगा होने से देश में निर्मित और आयातित दोनों तरह के खाद के दाम बढ़ेंगे और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी का बिल भी बढ़ेगा।

तेल के दाम यदि ज्यादा बढ़ गए तो देश का राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय रह रहे हैं जो 4,000 करोड़ डॉलर (लगभग 285,000 करोड़ रुपये) सालाना भारत भेजते हैं। यदि अशांति फैली तो उनके रोजगार और आमदनी पर भी असर पड़ेगा जिससे देश में आने वाली यह विदेशी मुद्रा भी खतरे में पड़ जाएगी। अतः सरकार के हाथ में संसाधन कम होंगे जिससे कृषि, ग्रामीण योजनाओं के बजट और कृषि निवेश में कटौती हो सकती है। पहले ही मंदी से जूझ रही हमारी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी, जिसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस अशांत माहौल का प्रभाव इन देशों में हो रहे हमारी कृषि जिंसों के निर्यात पर भी पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर हमारे किसानों की आय पर कैसे पड़ेगा? इसे हमारे चावल के निर्यात से समझा जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। हम 120 से 130 लाख टन चावल का निर्यात प्रति वर्ष करते हैं। 2018-19 में हमने 471 करोड़ डॉलर मूल्य के बासमती चावल और 304 करोड़ डॉलर मूल्य के गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था। इस प्रकार कुल मिलाकर 2018-19 में हमने लगभग 55,000 करोड़ रुपये मूल्य के चावल का निर्यात किया था। पिछले साल लगभग 33,000 करोड़ रुपये मूल्य के बासमती चावल के निर्यात में से लगभग 11,000 करोड़ रुपये यानी एक-तिहाई हिस्सेदारी ईरान की थी।

2018-19 में हमने ईरान से लगभग 2.4 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था, परंतु ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण मई 2019 से हमें भी ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करना पड़ा। इस कारण ईरान को होने वाले हमारे निर्यात के भुगतान की समस्या खड़ी हो गई जिससे इस निर्यात पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। इसका प्रभाव बासमती चावल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। 1121 प्रीमियम किस्म के बासमती चावल का निर्यात भाव छह-सात महीने पहले लगभग 1200 डॉलर प्रति टन था। अब यह गिरकर लगभग 900 डॉलर प्रति टन के आसपास आ गया है जो पिछले पांच साल का सबसे कम दाम है। ईरान से तेल ना खरीदने के कारण पहले ही भारतीय चावल की मांग वहां घट रही थी। अब खाड़ी देशों में अस्थिरता को देखते हुए हमारे बासमती चावल की मांग और कीमतों के और नीचे जाने की आशंका है।

देश पहले ही गेहूं-चावल के अत्यधिक मात्रा में भंडार होने से परेशान है। दिसंबर 2019 में भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में लगभग 213 लाख टन चावल और 352 लाख टन गेहूं थे। यानी कुल मिलाकर इन दोनों खाद्यान्नों का स्टॉक 565 लाख टन था, जबकि एक जनवरी को यह बफर स्टॉक 214 लाख टन होना चाहिए। इसके अलावा 260 लाख टन धान भी गोदामों में पड़ी है, परंतु अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण निर्यात घटने और खाड़ी देशों में तनाव से चावल की कीमतों पर और दबाव बढ़ेगा। इस साल पंजाब में किसानों को 1121 किस्म की बासमती धान का भाव 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो पिछले साल ईरान से अच्छी मांग के चलते 3600-3800 रुपये प्रति क्विंटल था।

भारत ने 2013-14 में 4,325 करोड़ डॉलर (आज के मूल्यों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये) मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था, जो 2016-17 में गिरकर 3,370 करोड़ डॉलर पर आ गया था। इसके बाद के वर्षों में इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, परंतु 2019-20 में अप्रैल से सितंबर की पहली छमाही में यह केवल 1,730 करोड़ डॉलर के स्तर पर है। खाड़ी देशों में अशांति और अनिश्चितता के कारण 2019-20 की दूसरी छमाही में इसमें और गिरावट आ सकती है। कृषि उत्पादों का निर्यात किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार होता है, लेकिन 2020 की शुरुआत में ही पश्चिम एशिया पर छाए अशांति के बादल हमारे देश के लिए, वहां रह रहे भारतीयों और विशेषकर हमारे किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

23 लाख लोगों की मौत हो जाती है साल में प्रदूषण की वजह से भारत में। वहीं, वैश्विक परिदृश्य में देखें तो दुनियाभर में हुई सभी मौतों के 15 प्रतिशत मामले प्रदूषण की वजह से ही होते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 15 जनवरी 2020

हिमाचल प्रदेश

अपनी हो या दूसरों की बहुत कीमती है जान

सुरक्षित यात्रा के लिए ही यातायात नियम बनाए गए हैं। इनका पालन किया जाना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन इनकी अवहेलना किया जाना जान जोखिम में डाल देता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कें हर मोड़ पर परीक्षा लेती हैं। राज्य में प्रत्येक दिन कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। सरकारी आंकड़ों की मानें तो हर दिन औसतन तीन लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है। इसके बावजूद यातायात नियमों की अनदेखी किया जाना कतई सही नहीं है। चालकों की लापरवाही से सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। एक बस चालक पर कई लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है, यदि वह नियमों की अवहेलना करता है तो गंभीर मामला है। प्रदेश में निजी बसें आवागमन का प्रमुख साधन हैं। लाखों लोग हर रोज निजी बसों में सफर करते हैं। बिलासपुर जिले में छकोह से नयनादेवी जा रही बस का चालक करीब 12 किलोमीटर तक मोबाइल का प्रयोग करता रहा। यह जानते हुए भी कि इससे कई सवारियों की जान को खतरा हो सकता है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि बस चलाते समय कई किलोमीटर तक मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई से लापरवाह वाहन चालकों को सबक मिलेगा। वे इससे बाज आएंगे।

सुखद यह रहा कि इस दौरान किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। चालक की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दैनिक जागरण ने भी लोगों से जुड़े इस संवेदनशील मामले को प्रमुखता से उठाया। इसी का नतीजा है कि परिवहन विभाग ने बस के चालक का लाइसेंस रद करने का आदेश दिया है। बस के मालिक को भी सरकार ने लापरवाही के लिए बराबर दोषी मानते हुए रूट परमिट सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इस कदम से निश्चित तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को कड़ा सबक मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में होने वाले अधिकतर सड़क हादसों का प्रमुख कारण मानवीय लापरवाही को ही माना गया है। यातायात नियमों का पालन सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि चालान से बचने के लिए किया जाता है।

समझना होगा कि जान अपनी हो या दूसरों की, बहुत कीमती है। सरकार ने अगर नियम बनाए हैं तो उनका पालन करना जनता का दायित्व है। उम्मीद है कि बिलासपुर की घटना से वाहन चालक सबक सीखेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। सभी मन से यातायात नियमों का पालन करें तो हादसों के ग्राफ को कम करना संभव हो सकेगा। इसमें सख्त नियमों के साथ ही जागरूकता का प्रसार बेहद आवश्यक होगा। कायदे-कानून भले ही कितने सख्त बना दिए जाएं, लेकिन उनका प्रवर्तन सही प्रकार नहीं होता तो उस स्थिति में वे अर्थहीन हो जाते हैं। इसके लिए नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सामुदायिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। यह उस यात्री की समझबूझ ही थी कि उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल करने वाले चालक का वीडियो बनाया जिसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकी। यदि इस प्रकार की तत्परता दिखाई जाए और एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराया जाए तो निश्चित रूप से हादसों की संख्या कम की जा सकती है।

बंगाल

परवान चढ़ेगी पुण्य कमाने की चाहत

सारे तीरथ बार-बार, गंगा सागर एक बार। शायद यह कहावत इसलिए कही गई थी, क्योंकि गंगा सागर पहुंचने में बड़ी कठिनाई झेलनी होती थी। गंगा सागर को देश का सबसे दुरुह तीर्थ कहा भी जाता था, लेकिन इसकी मंजिल अब बहुत आसान हो रही है। राज्य सरकार के सहयोग से एक निजी पर्यटन कंपनी ने क्रूज सेवा शुरू कर दी है। इससे कोलकाता से गंगा सागर पहुंचने में महज तीन घंटे लगेंगे। फिलहाल गंगासागर जाने के लिए लोगों को पहले सियालदह से ट्रेन के बाद सड़क के रास्ते काकद्वीप लाट पहुंचना पड़ता है। वहां से जहाज के माध्यम से मूड़ीगंगा पार कर सागरमेला द्वीप के घाट कचुबेड़िया पहुंचते हैं। वहां से सड़क के रास्ते कपिल मुनि आश्रम। कुल चार से पांच घंटा का समय लगता है। नदी में ज्वार या भाटा की स्थिति में 8 से 10 घंटे तक लग सकते हैं। जाहिर है जो श्रद्धालु गंगा सागर जाने के लिए काफी मशक्कत करते हैं, उनके लिए निःसंदेह यह राहत भरी योजनाकारी साबित होने वाली है। यह एक सुखद पहल है। पुण्य कमाने की चाहत को परवान चढ़ाने वाली है और सुविधाजनक भी।

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के लोग पुण्य की चाहत में यह कठिन सफर तय करते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब यहां एक अद्भुत दृश्य पैदा करता है, लेकिन यातायात की

प्रतीकात्मक

असुविधा से उन्हें वाकई इस तीर्थ तक पहुंचने में कठिन अहसास होता है।

बंगाल की खाड़ी के कांटीनेंटल शेल्फ में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में गंगा सागर एक द्वीप है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। यहीं गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। गंगा नदी के सागर से संगम पर स्नान कर लोग पुण्य की कामना करते हैं। यहां एक मंदिर है जो कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना है। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सगर के साठ हजार पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ तप कर गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा यहीं सागर से मिली थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर दस अश्वमेध यज्ञ और एक हजार गाय दान करने के बाद फल मिलता है।

अब कोलकाता के मिलेनियम पार्क घाट से गंगा सागर के कचुबेड़िया के लिए सीधी क्रूज सेवा उपलब्ध होगी। कचुबेड़िया से कपिल मुनि आश्रम पहुंचने में बस से एक घंटे का समय लगता है। मिलेनियम घाट से जहाज सुबह सात बजे जाएगा और सुबह 10.30 बजे तक कचुबेड़िया घाट पहुंच जाएगा। वापसी में जहाज कचुबेड़िया से शाम तीन से चार बजे के बीच खुलेगा। रात सात से आठ बजे तट जहाज कोलकाता पहुंच जाएगा। एसी क्रूज में 156 यात्री जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को आने-जाने में प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये खर्च होगा। सेवा के लिए मलेशिया से क्रूज मंगाया गया है। जहाज में 500 किलोवाट के दो इंजनों के साथ दो जनरेटर भी लगे हैं। शौचालय के साथ यात्रियों के मनोरंजन के लिए टीवी के साथ सिनेमा देखने के लिए दो बिग स्क्रीन भी लगाए गए हैं। जहाज की गति 30 किमी प्रतिघंटा होगी।

उम्मीद है ति यह क्रूज श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के साथ ही बंगाल के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य की आर्थिकी पर सकारात्मक असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

बिहार

मुकम्मल इंतजाम जरूरी

बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले चरण में जिस प्रकार की अराजकता हुई उससे शासन-प्रशासन को सीख लेने की जरूरत है। परीक्षा आयोजित कर रहे संगठन को विचार करना चाहिए कि परीक्षार्थी का दबाव आम जनजीवन को कैसे अस्त-व्यस्त कर देता है। इसके साथ ही इस परीक्षा में शामिल युवकों को भी सोचना होगा कि नौकरी पाने का संघर्ष कठिन है। यह तो अच्छा है कि राज्य सरकार की भर्ती परीक्षा है। आखिर दूसरे राज्यों की परीक्षा या केंद्रीय भर्ती बोर्ड की परीक्षा में हम दूर शहरों में या राज्य के बाहर जाते हैं या नहीं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं भी संयम से काम लेना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि सिपाही भर्ती परीक्षा भले ही दो-चार घंटे की हो, लेकिन जिंदगी की परीक्षा बहुत लंबी है। और उपद्रव में शामिल होने से जिंदगी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दरअसल केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई, उसमें औरंगाबाद में रेल ट्रैक जाम कर उपद्रव कर रहे छात्रों को काबू करने में

सिपाही भर्ती परीक्षा भले ही दो-चार घंटे की हो, लेकिन जिंदगी की परीक्षा बहुत लंबी है। और उपद्रव में शामिल होने से जिंदगी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रतीकात्मक

फायरिंग तक करनी पड़ी। मुंगेर, जहानाबाद आदि जिलों में भी स्थिति अनियंत्रित हुई। रेलवे ने यूं तो कुछ विशेष ट्रेन का इंतजाम किया था, लेकिन यह नाकाफी था। ऐसे मौकों पर बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में पहले से आरक्षण करा कर चलने वाले यात्रियों की भी असुविधा बढ़ जाती है। अब अगले चरण की परीक्षा 20 जनवरी को है। रेल प्रशासन को भी चाहिए कि वह इसकी तैयारी का आदर्श प्रस्तुत करे। अभी तक इस प्रकार की कोई घोषणा रेल प्रबंधन की ओर से नहीं की गई है।

जरूरत इस बात की भी है कि परीक्षार्थियों को यह आश्वासन मिल जाए कि उनके आवागमन के विशेष इंतजाम हैं। वैसे भी युवा मन अपनी रौ में रहता है। उसकी सहन शक्ति कमजोर होती है। दूसरी तरफ परीक्षा की तारीख तय करने में भी प्रशासन की ओर से मौसम की मार का ध्यान नहीं रखा गया। देश इस समय भीषण ठंड से गुजर रहा है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई स्थगित है। धुंध के कारण सड़क पर गाड़ियों का चलना खतरनाक साबित हो रहा है। चयन पर्षद को इस खतरनाक समय का संज्ञान तिथि तय करने से पूर्व जरूर लेना चाहिए था। उम्मीद है कि 20 जनवरी को छात्रों के संयम, सामान्य प्रशासन और रेल प्रबंधन के विशेष इंतजाम से व्यवस्था बेहतर बनेगी।

झारखंड

साइबर क्राइम का अगुआ होने का कलंक

झारखंड पर साइबर क्राइम का अगुआ होने का कलंक लग रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि जब भी देश में कहीं साइबर क्राइम होता है तो सबसे पहले झारखंड का ही नाम आता है। राज्य का जामताड़ा इलाका इस मामले में बेहद बदनाम है। चुटकियों में लोगों को ठग लेने में यहां के अपराधियों को महारत हासिल है। चिंता की बात यह है कि ऐसे अपराधियों में बड़ी तादाद युवाओं की है। बैंक अधिकारी बनकर खाताधारकों को फोन पर झांसा देकर उनका बैंकिंग डिटेल लेकर ठग लिया जाता है। कभी उपहार का लालच देकर उनके खाते से रुपये उड़ा लिए जाते हैं। ये अपराधी इतने शातिर हैं कि जानकारी लेते ही खाते में सेंध लगा देते हैं।

सोमवार को जामताड़ा में दो अपराधी पकड़े गए। साहिबगंज में पांच हजार रुपये के इनाम का लालच देकर एक महिला के खाते से 20 हजार रुपये टपा लिए गए। देवघर में मंगलवार को ही आठ साइबर अपराधी पकड़े गए। जामताड़ा में भी तीन पकड़े गए। गिरिडीह, देवघर, धनबाद समेत सूबे के कई जिले साइबर अपराध की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब धनबाद से साइबर अपराधियों को दबोचा गया था। जामताड़ा का साइबर अपराधी पंजाब के मुख्यमंत्री की सांसद पत्नी के खाते से भी रुपये उड़ा चुका है। इन वाकयों ने झारखंड के नाम को बदनाम कर दिया है। जो युवा राज्य की शक्ति बन सकते हैं, वे इसे गर्त में धकेल रहे हैं। ऐसे में यहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे जागरूक हों और इस कलंक को मिटाएं। सीधी सी बात है कि कोई भी बेवजह किसी को फायदा नहीं पहुंचाता। लोगों को यह बात समझनी चाहिए।

गिरिडीह, देवघर और धनबाद समेत राज्य के कई जिले साइबर अपराध की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। देश भर में यहां से सेंधमारी कर रुपये उड़ाए जा रहे हैं। इससे राज्य का नाम खराब हो रहा है।

बैंकों से भी बराबर ये संदेश आता रहता है कि उनकी ओर से अपने ग्राहकों से खाते की जानकारियां नहीं मांगी जाती। आखिर क्यों ऐसे झांसों में फंसा जाए।

जब लोग जागरूक हो जाएंगे और अपनी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा के प्रति सजग हो जाएंगे तो साइबर अपराधियों की पकड़ खुद-ब-खुद कमजोर होती जाएगी, क्योंकि सामान्य चूक ही उनका हथियार है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक लोग ऐसे ठगों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक पुलिस भी मदद नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बेहतर है कि पहले ईमेल करने वाले या फोन करने वाले की पहचान कर ली जाए। यह तय कर लेना होगा कि मोबाइल पर किसी का भी फोन आए और खाते के संबंध में कतई जानकारी नहीं देनी है। इसी माध्यम से अपराधियों का शिकार होने से बच सकेंगे। जब साइबर अपराध कम होगा तो राज्य भी बदनाम नहीं होगा।

इसमें कोई दोराय नहीं कि तकनीक के इस युग में हर सुविधा लोगों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होने से जिंदगी आसान हो गई है। पैसे का लेनदेन हो या कोई खरीदारी करनी हो तो मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यह स्थिति तभी सुखद है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह घातक साबित होता है।

हरियाणा के गांवों में बनेंगे बाजार किसान खुद बेचेंगे अपना सामान

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- किसान और खरीददार के बीच खत्म होंगे बिचौलिये, मंडियों में माल बेचने को निशुल्क फड़ देगी सरकार
- किसानों की आय बढ़ाने का फार्मूला तैयार, राज्य में फार्मर प्रोड्यूज आर्गेनाइजेशन खड़े कर रही सरकार

प्रतीकात्मक

हरियाणा के कृषि विभाग ने किसानों को फसल विविधिकरण की तरफ मोड़ने और उनकी आय में बढ़ोतरी का फार्मूला तैयार किया है। कृषि मार्केटिंग बोर्ड राज्य में किसानों व ग्राहकों के बीच से बिचौलिये खत्म करने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत राज्य में फल व सब्जी उत्पादक किसान न केवल मंडियों में खुद के उत्पाद स्वयं बेच सकेंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें मार्केटिंग बोर्ड से आढ़तियों की तरह लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार चार से छह गांवों को जोड़कर उनकी जरूरतें पूरी करने को ग्राम हाट (बाजार) भी बनाएगी।

हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने ऐसे किसानों को फार्मर प्रोड्यूज आर्गेनाइजेशन (एफपीओ) का नाम दिया है, जो खुद के उत्पाद स्वयं बेचने को आगे आएंगे। राज्य में अभी तक करीब 450 एफपीओ अपने खेतों में तैयार सब्जियां और फल बेचने के लिए सामने आ चुके हैं। बिना लाइसेंस ऐसे एफपीओ को मंडियों में अपने उत्पाद बेचने को 15 बाई 15 का फड़ उपलब्ध कराया जाएगा।

किसी भी सब्जी मंडी में आढ़तियों को किसानों के उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। वह किसानों और ग्राहकों से अलग-अलग आढ़त वसूलते हैं, लेकिन किसानों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी और बिचौलियों को साइड करने के लिए एफपीओ की परिकल्पना की गई है। यह व्यवस्था उन सभी किसानों के लिए खुली है, जो अपने उत्पाद खुद मंडी में बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित मार्केटिंग बोर्ड में अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य विपणन अधिकारी राजकुमार बैनीवाल के इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है।

पूरे राज्य में एफपीओ की संख्या बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। एफपीओ को प्रमोट करने के लिए सरकार ग्राम हाट (बाजार) योजना तैयार कर रही है। एफपीओ ही इन ग्राम हाट का संचालन करेंगे।

ग्राम हाट के लिए पंचायतों से लीज पर ली जमीन

हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य विपणन अधिकारी राजकुमार बैनीवाल के अनुसार कृषि मंत्री जेपी दलाल की यह सोच है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। उनकी आय में बढ़ोतरी हो। ग्राम हाट के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने पंचायतों से चार-चार एकड़ जमीन लीज पर ली है। इस चार एकड़ जमीन में से एक एकड़ पर ग्राम हाट बनाने की योजना है। अभी तक करीब 200 जगह ऐसे हाट बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। यहीं पर किसानों के आराम के लिए एक-एक रेस्ट हाउस भी बनेगा।

हरियाणा की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य और सपने को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। हम किसानों की आय डबल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनके लागू होने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। फसल विविधिकरण के साथ ही किसानों को खुद के उत्पाद बेचने के लिए सामने लाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

- जेपी दलाल, कृषि मंत्री, हरियाणा

चार से छह गांवों का होगा एक ग्राम हाट

योजना के तहत चार से छह गांवों को मिलाकर एक ग्राम हाट तैयार किया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड के पास रजिस्टर्ड एफपीओ (किसान) यह हाट चलाएंगे। इन्हीं हाट से संबंधित गांवों के लोग अपनी जरूरत के फल, सब्जियां, मसाले और अन्य उत्पाद खरीद सकेंगे। मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य विपणन अधिकारी राजकुमार बैनीवाल के मुताबिक प्रत्येक हाट में 10 से 15 दुकानें होंगी। अभी तक 196 प्वाइंट ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं, जहां ग्राम हाट बनेंगे।

उप्र में युवाओं की नौकरी पर 'गारंटी' का पहरा

आशीष त्रिवेदी, लखनऊ : युवाओं की नौकरी पर अब गारंटी का पहरा होगा। एक साल तक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं की नौकरी की ट्रैकिंग करेगा। वह समय-समय पर इस बात की तस्दीक करेगा कि युवाओं की नौकरी सही-सलामत है या नहीं। वहीं ऐसे में उन कौशल विकास केंद्रों गर्दन फंसेगी जो अभी मनमाने ढंग से प्लेसमेंट के आंकड़े देते हैं। हजारों युवाओं को राहत देने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसमें कौशल विकास केंद्र व प्लेसमेंट देने वाली कंपनी के साथ-साथ युवाओं का ऑनलाइन ब्योरा होगा और इसके माध्यम से निगरानी की जाएगी।

उप्र कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि जिन कंपनियों में युवाओं का प्लेसमेंट करवाया जा रहा है, वहां न्यूनतम एक वर्ष तक युवाओं की निगरानी की जाएगी। कई बार कंपनियां प्लेसमेंट तो कर लेती हैं लेकिन कुछ दिनों बाद युवाओं को निकाल देती हैं।

अब ऐसा नहीं चलेगा। सभी 3400 से अधिक कौशल विकास केंद्रों पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे युवाओं की ट्रैकिंग होगी। कौशल विकास केंद्र द्वारा करवाए गए प्लेसमेंट के समय कंपनी ने जिन शर्तों व वेतन पर युवाओं को नौकरी दी है, उसका वह सख्ती से पालन कर रही है या नहीं इसकी समय-समय पर मानीटरिंग होगी।

अभी तमाम शिकायतें सामने आती हैं कि प्लेसमेंट करने के बाद कंपनी ने कुछ दिन बाद ही नौजवानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ट्रैकिंग की व्यवस्था होने से उन पर दबाव बढ़ेगा, वह बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से बाहर नहीं कर पाएंगे। कौशल विकास केंद्रों की भी जवाबदेही तय होगी, अगर उन्होंने सांठगांठ कर प्लेसमेंट के गलत आंकड़े दिखाए हैं तो वह फंस जाएंगे। फिलहाल अब हजारों युवाओं को राहत देने की तैयारी की जा रही है।

बैसाखी पर बैंकों का सर्विलांस सिस्टम, भारी पढ़ रहे ठग

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ

किस्त तीन

साइबर अपराध को लेकर आरबीआइ की गाइडलाइंस से भले ही फाइलें भरी पड़ी हों लेकिन ठग लोगों के खाते खाली कर रहे हैं। साइबर क्राइम से निपटने के लिए आरबीआइ के निर्देशों के तहत बैंकों को एटीएम ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सभी की 24 घंटे सातों दिन निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम विकसित करना है। इसके बावजूद बैंकों का सर्विलांस सिस्टम बैसाखी पर है।

दैनिक जागरण ने अपने पाठकों को साइबर अपराधियों से बचाने के लिए खबरों के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। अगर आप साइबर जगत से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं अथवा कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में 0522 4234152 नंबर पर फोन कर सकते हैं। साइबर विशेषज्ञ और आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) में एएसपी दिनेश यादव बुधवार दोपहर 12:30 बजे जागरण कार्यालय, लखनऊ में मौजूद रहेंगे। वह लोगों को साइबर अपराधियों से बचने के उपाय बताएंगे। दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक एएसपी लोगों की जिज्ञासा शांत करेंगे।

ये हैं निर्देश

- साइबर सिक्योरिटी पर बैंक समग्रता के साथ व एकजुट होकर निर्णय लें।
- साइबर सिक्योरिटी के पैमाने को और दुरुस्त करें।
- भविष्य के खतरों से निपटने के लिए बोर्ड बैठक करें।
- बेहद जरूरी है कि साइबर सुरक्षा को लेकर सावधानियां बरती जाएं।
- ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- साइबर अपराध रोकने लिए बैंक ग्राहकों को जागरूक किया जाए।

अब रात दस बजे के बाद ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। कार्ड क्लोनिंग खत्म करने के लिए 700 मशीनें बदली जा चुकी हैं। ओटीपी ग्राहक के मोबाइल पर ही आएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मॉनीटरिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट है।

- सलोनी नारायण, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

बैंक के सभी एटीएम सर्विलांस पर हैं। कैमरा खराब होने की स्थिति में तुरंत जानकारी हो जाती है। संदिग्ध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की भी गंभीरता से निगरानी की जाती है।

- एके सिंह, उपमहाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्ड क्लोनिंग रोकने के लिए ईएमवी कार्ड रीडर साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी ट्रांजेक्शन चैनल सर्विलांस पर हैं। ऑनलाइन फ्राड रोकने के लिए कई अन्य सिक्योरिटी फीचर शुरू किए गए हैं।

- नरेंद्र सिंह, फील्ड महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

एटीएम की नियमित मॉनीटरिंग हो रही है। किसी ट्रांजेक्शन का एसएमएस आने पर यदि लगता है कि गलत/ फ्रॉड ट्रांजेक्शन है तो मोबाइल से 9264092640 पर तुरंत एक मैसेज भेज दें।

- समीर बाजपेयी, महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक

तकनीक से दूर होगी गंगासागर तीर्थ यात्रियों की परेशानी

जागरण संवाददाता, कोलकाता : गंगासागर मेले में को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में दक्षिण 24 परगना प्रशासन ने क्यूआर कोड रिस्ट बैंड मोबाइल एप व साफ्टवेयर के माध्यम तीर्थयात्रियों को और सुविधाएं देने की कोशिश की है। हर साल गंगासागर में लगनेवाले मकर संक्रांति मेले में पुण्य स्नान के लिए लिए देश के कोने-कोने से लाखों पुण्यार्थी यहां पहुंचते हैं। दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी पी उलगनाथन ने मंगलवार को बताया कि मेले में लोगों के परिजनों से बिछड़ने की घटनाओं को देखते हुए इस साल से प्रशासन क्यूआर कोड युक्त रिस्ट बैंड इस्तेमाल कर रही है। बताया कि इस साल कुंभ मेला नहीं होने की स्थिति में गंगासागर मेले में देश भर से 30 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में मूड़ीगंगा से गंगासागर द्वीप तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाना एक चुनौती है।

प्रशासन की तकनीकी सेवाएं

परिचय : क्यूआर कोड आधारित रिस्ट बैंड से बिछड़नेवालों को अपनों से मिलाएगा प्रशासन

सागर सुरक्षा : तीर्थयात्रियों की सटीक संख्या के साथ भीड़ बढ़ने व संभावित भीड़ की घोषणा करने के लिए बनी तकनीक

अतिथि पथ : सागर परिसर आनेवालों को सटीक रास्ता दिखाने के साथ भाड़े, रूट, ज्वार व भाटे का समय , जहाज व पूजा का समय बताए एप

वाहन दर्शन : सागर मेला परिसर में आनेवाले वाहनों को सटीक रास्ता दिखाने के लिए जीपीएस आधारित एप

ई-स्नान : इस साल गंगासागर नहीं पहुंच सके लोगों तक लाइव गंगा सागर दर्शन की व्यवस्था के साथ ऐसे लोगों तक प्रसाद व गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था

48 की आयु में भारतीय अपने जीवन से होते हैं सबसे असंतुष्ट

मिडलाइफ क्राइसिस का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही जिसमें माना जाता है कि इंसान औसत आयु के मध्य में आकर अपने जीवन से सबसे असंतुष्ट हो जाता है। अब इस मान्यता पर वैज्ञानिकों की मुहर लग गई है। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में किए गए अध्ययन में इस बात को प्रामाणिकता मिली है। नेशनल ब्यूरो आफ इकोनॉमिक रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि विकसित देशों में 47.2 साल की आयु इंसान के जीवन का सबसे खराब दौर होती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए आयु का यह आंकड़ा 48.2 साल है।

ऐसे हुआ अध्ययन

शोध में भाषायी, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर विभिन्नता वाले करीब 132 देशों को शामिल किया गया। इनमें विभिन्न सामाजिक स्तर की महिलाओं और पुरुषों से उनके जीवन संतुष्टि से जुड़े सवाल किए गए। ज्यादातर लोगों में आजीविका के स्रोतों को लेकर असंतोष दिखा।

प्रमुख निष्कर्ष

प्रो डेविड ब्लेंचफ्लावर द्वारा वैश्विक खुशहाली को मापने के लिए की गई इस रिसर्च में सामने आया कि तीस से चालीस साल की उम्र में इंसान के मस्तिष्क का सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है। साठ साल के बाद एक बार फिर यह प्रभावी होने लगता है। रिपोर्ट के अनुसार बीस और साठ साल की उम्र में खुशहाली का स्तर सबसे ज्यादा होता है।

जानवर भी नहीं अछूते

रिसर्च में यह भी पाया गया कि जानवर

खासतौर पर चिपांजी में भी यही लक्षण दिखाए दिए। इसलिए यह क्रिया एक प्राकृतिक बदलाव को दिखाती है।

तथ्य

- 132 देशों के 35 हजार लोगों पर यह शोध किया गया।
- ज्यादातर लोगों में असंतोष नौकरी से वजह से है।
- महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा निराशा है।
- स्व रोजगार वाले लोगों में निराशा नौकरीपेशा लोगों से कम है।

रोचक

रिसर्च के निष्कर्ष में पाया गया कि जिन देशों में सकारात्मक परिणाम मिले या लोग कम निराश मिले वे मुख्य तौर सभी देश संपन्न, साक्षर, लोकतांत्रिक और बेरोजगारी से मुक्त थे।

कौन हैं प्रो डेविड ब्लेंचफ्लावर

प्रोफेसर डेविड ब्लेंचफ्लावर डर्टमाउथ कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने लंबे समय तक जीवन संतुष्टि पर काम किया है। उन्होंने पाया कि जीवन में खुशहाली का स्तर यू के आकार में वक्र जैसा होता है। बीस साल के बाद खुशहाली बढ़ती है। लगभग मध्य आयु में आकर असंतोष चरम पर होता है। फिर उम्र बढ़ने के साथ खुशहाली लौटती जाती है और 70 साल के बाद एक बार फिर ये अधिकतम स्तर को छूती है।

आम धारणा

माना जाता है कि विकसित और विकासशील देशों में उम्र के इस पड़ाव पर लोगों के सामने तनाव की कई वजहें आ जाती हैं। बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। पारिवारिक समस्याएं शुरू हो जाती है। आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें शुरू होती हैं। बच्चों की परवरिश संबंधी चिंताएं बढ़ती है। पहली बार इन धारणाओं को वैज्ञानिक शोध द्वारा प्रामाणिकता दी गई।

99 हजार से बढ़कर एक लाख और फिर 1.01 लाख हो गई सर्वाइकल कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या भारत में। यह आंकड़ें 2016 से 2018 के तीन सालों के हैं।

1995 किलो खिचड़ी पका बना विश्व रिकॉर्ड

- गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल, मंडी जिले के तत्तापानी में हुआ आयोजन

20 हजार से अधिक लोगों में वितरित की गई 1995 किलो खिचड़ी।

08 घंटे लगे खिचड़ी पकाने में।

02 महीने बाद जारी होगा स्थायी प्रमाणपत्र। अभी विश्व रिकॉर्ड बनने का अस्थायी प्रमाणपत्र दिया गया है।

5 स्टार होटल ताज रेडिसन के शेफ भी खिचड़ी पकाने में शामिल हुए।

खिचड़ी बनाने में लगी सामग्री

405 किलो चावल	90 किलो देसी घी
100 किलो माश	30 किलो मसाले
30 किलो रोंगी	1100 लीटर पानी
65 किलो मटर	20 किलो नमक

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

मंडी जिले के तत्तापानी में मकर संक्रांति पर मंगलवार को खिचड़ी बनाने में जुटे शेफ● जागरण

- खिचड़ी बनाने के लिए हरियाणा के जगाधरी से लाया गया पतीला।
- 225 किलो पतीले का भार
- 45 किलो पतीले के ढक्कन का भार
- 7.5 फीट बर्तन का घेरा
- 5.5 फीट बर्तन की गहराई
- 11 खौंचों का इस्तेमाल किया गया खिचड़ी बनाने के लिए।
- बर्तन उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया।
- 15 शेफ व 10 हेल्पर जुटे खिचड़ी बनाने में। प्रदेश शेफ एसोसिएशन ने शेफ उपलब्ध करवाए। होलीडे होम के डीजीएम एवं प्रदेश शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा की देखरेख में खिचड़ी पकाई गई।

मंडी जिले के तत्तापानी में 1995 किलो खिचड़ी बनाने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट के साथ सीएम जयराम ● जागरण

"अभी तक तत्तापानी में खिचड़ी बिना तोले पकाई व खाई जाती थी। इस बार तोल कर खिचड़ी पकाई गई, जो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। अभी विश्व रिकॉर्ड बनने का अस्थायी प्रमाणपत्र दिया गया है। दो महीने बाद स्थायी प्रमाणपत्र मिलेगा। तत्तापानी को विश्व मानचित्र पर उभारा जाएगा।
-मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

संगम पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : माघ मेला -2020 में मकर संक्रांति के एक दिन पहले मंगलवार को ही संगम पर आस्था हिलोर लेती दिखी। भोर से ही श्रद्धालु डुबकी लगाने लगे थे। शाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई। मेला प्रशासन ने 22 लाख श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का दावा किया है।

घोषित तौर पर मकर संक्रांति का स्नान पर्व बुधवार को है पर इस बार एक दिन पहले ही संगम की रेती पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच गए। इनमें ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी, जो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते हैं। स्नानार्थी सोमवार रात से ही तंबुओं की नगरी में पहुंचने लगे थे। मंगलवार तड़के संगम तट श्रद्धालुओं से लबालब दिखाई देने लगा। स्नान, ध्यान और दान का सिलसिला शाम तक चलता रहा। सुबह छह बजे से 10 बजे के बीच सभी स्नान घाटों पर भारी भीड़ दिखी। दोपहर धूप खिली तब भी यही आलम नजर आया। अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तंबुओं की नगरी में रुके हैं। यह बुधवार को भी पुण्य की डुबकी लगाएंगे।

मकर संक्रांति स्नान के लिए मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। स्नान घाटों से लेकर मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, एंट्री प्वाइंटों और पांटून पुलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उच्चाधिकारियों ने मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा भी लिया। जहां कमियां पाईं गईं, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। मेला क्षेत्र में सोमवार से ही वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह प्रतिबंध गुरुवार सुबह तक लागू रहेगा। मेलाधिकारी रजनीश मिश्र का दावा है कि मकर संक्रांति स्नान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्नानार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंगलवार को ही शाम तक 22 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है।

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मंगलवार को पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। मुकेश कनौजिया

पैड को खाद में बदल देगा ईकोफ्रेंडली 'मेन्सयू बर्नर'

फेंकें नहीं, जलाएं...

- उपयोग किए जा चुके सेनेटरी पैड को सुरक्षित तरीके से करता है नष्ट
- जलने पर बनने वाली राख का खाद के रूप में किया जा सकेगा इस्तेमाल
- गुड़, सहजन और नीम के पत्ते मिलाने पर बन जाएगी जैविक खाद

अपनी अध्यापिका कंचन गुलेरिया के साथ छात्रा कृतिका। जागरण

राज चौधरी, पठानकोट

दसवीं में पढ़ने वाली पठानकोट, पंजाब की दो छात्राओं कृतिका और हर्षिता ने 'मेन्सयू बर्नर' नामक उपकरण बनाया है, जो उपयोग हो चुके सेनेटरी पैड का समुचित निस्तारण करता है। स्कूल की शिक्षिका के मार्गदर्शन में इन छात्राओं ने उपकरण का प्रारंभिक स्वरूप (प्रोटोटाइप) तैयार किया है, जिसे सराहा जा रहा है।

कृतिका और हर्षिता कहती हैं, उपयोग के बाद सेनेटरी नैपकिन का निस्तारण सबसे बड़ी समस्या बनता है। अमूमन इसे पॉलीथिन या कागज में रख कूड़े में फेंक दिया जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हमने जो उपकरण बनाया है, उसने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। इससे अब खाद बनेगी, जो हरियाली बढ़ाने में इस्तेमाल होगी...। पठानकोट के क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल की इन छात्राओं ने सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल यूनिट को मेन्सयू बर्नर नाम दिया है। नैपकिन जलाने के बाद, जो राख बनेगी, उसे घरों में भी गमलों में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

स्वस्थ समाज

भारत सरकार की ओर से 27 से 31 दिसंबर 2019 तक केरल में आयोजित नेशनल चिल्ड्रन कांग्रेस में देशभर के स्कूलों से 685 टीमों ने हिस्सा लिया था। इन छात्राओं का यह मॉडल भी इस में पेश किया गया, जिसे सभी ने सराहा। अब इस प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजने की तैयारी चल रही है।

छात्राओं ने बताया कि उपकरण में थर्मोस्टेट के साथ 1500 वाट क्षमता का क्वाइल हीटर लगाया गया है। टीन की चादर से तैयार डिब्बे के अंदरूनी हिस्से में मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई है। सेनेटरी पैड को इसमें डाले जाने पर एक उचित तापमान पर यह जलने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिन्हें चारकोल (कार्बन), पोटैशियम डाइक्रोमेट और फेरस सल्फेट के जार में रखे मिश्रण से गुजारा जाता है। इससे यह गैसें निष्क्रिय हो जाती हैं। नैपकिन जलने से बनी राख को खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, इसमें गुड़, सहजन और नीम के पत्ते मिलाकर इसे जैविक खाद में तब्दील कर सकते हैं।

कृतिका और हर्षिता द्वारा बनाए गए 'मेन्सयू बर्नर' का मॉडल। जागरण

मॉडल को तैयार करने में बायोलॉजी की अध्यापिका कंचन गुलेरिया छात्राओं की गाइड रहीं। उनके अनुसार इस मॉडल पर कुल 800 रुपये खर्च आया है। मेन्सयू बर्नर तीन मिनट में एक नैपकिन को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर सकता है। मॉडल में अभी और सुधार किया जाएगा। इसमें सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे यह खुद एक-एक कर नैपकिन नष्ट करता रहे। फिलहाल इसमें एक-एक कर सेनेटरी नैपकिन डालने पड़ते हैं। छात्राएं कृतिका सिंह और हर्षिता कहती हैं कि अपने मॉडल को पहला स्थान मिलने से उत्साह बढ़ा है।

कराया जाएगा पेटेंट : जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह और जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश्वर सलारिया कहते हैं कि इस उपलब्धि के लिए छात्राओं और उनकी गाइड को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इस मॉडल का पेटेंट भी करवाया जाएगा।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

'दुर्गा' के अवतार में एसडीएम शिवानी, माफिया बेहाल

जय शिवानी... ▶ मध्य प्रदेश के गुना की युवा अधिकारी के नाम से माफिया को ठंड में भी छूट रहे हैं पसीने

जागरण विशेष

ध्रुव झा, गुना

मप्र के गुना में पदस्थ युवा उप जिलाधिकारी (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट) शिवानी गर्ग के नाम से माफिया को ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ शिवानी ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 'एंटी माफिया' अभियान छेड़ा हुआ है। लिहाजा, गुना की जनता बेहद खुश है और लोकप्रिय हो चली इस महिला अधिकारी को 'मर्दानी' और 'भवानी' जैसे अलंकरण दे रही है।

इसकी वजह है, शिवानी ने अपनी दबंग कार्यशैली से माफिया जगत में खलबली मचा दी है। एक ओर वह सरकारी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करा रही हैं, तो आम अतिक्रमण के खिलाफ भी डटकर खड़ी हैं। शहर को अतिक्रमणमुक्त बनाकर सुधार-संवार रही हैं। वहीं, मिलावटखोरों पर नकेल कसने को चलाए गए उनके अभियान से भी जनता ने राहत की सांस ली है। माफिया से मुकाबले और भय के सवाल पर शिवानी कहती हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, लक्ष्य की पूर्ति का दायित्वबोध और जनसेवा का भाव प्रेरणा का काम करते हैं। नियमानुसार कार्रवाई और इसके अनुरूप आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करने से प्रशासनिक अमला सक्रिय हो जाता है। ऐसे में हर मुकाबला लड़ा जा सकता है, भय का सवाल ही नहीं उठता।

ट्रैक्टर चलाकर मावन क्षेत्र में सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करातीं एसडीएम। नईदुनिया

- मिलावटखोरों और अतिक्रमणकारियों पर लगा अंकुश
- 'शुद्ध के लिए युद्ध' और 'एंटी माफिया' मुहिम से माफिया में खलबली
- खुद मोर्चा संभाल करती हैं टीम की अगुवाई
- जेसीबी-ट्रैक्टर चला अच्छे-अच्छों के कब्जे से छुड़ा रहीं सरकारी जमीन

शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मोर्चा संभालतीं शिवानी गर्ग। नईदुनिया

मप्र के ही सागर जिले में पली-बढ़ीं शिवानी मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता राजेश रायकवार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में अकाउंटेंट हैं और मां कमला रायकवार स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर। पति अंशुल गर्ग जेल उप-अधीक्षक हैं। बताती हैं, परिवार में शैक्षिक माहौल का लाभ बचपन से मिला इसलिए पढ़ाई में अव्वल रही। स्नातक करने के बाद मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की परीक्षा की तैयारी की और 2015 में परीक्षा दी। बिना कोचिंग लिए घर पर ही तैयारी की और पहले ही प्रयास में उप जिलाधिकारी के रूप में चयन हो गया। इसके बाद पहली पोस्टिंग गुना में हुई और जनसेवा का सफर शुरू हुआ। बतौर एसडीएम गुना, शिवानी ने पद की गरिमा के अनुरूप काम शुरू कर दिया। कहती हैं, शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के जो भी निर्देश मिले, उन्हें लक्ष्य बनाकर पूरा किया। इसके अलावा स्वच्छता रैंकिंग में शहर को टॉप-10 सूची में शामिल कराना प्राथमिकता है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़कर शिवानी ने शहर के बड़े मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई की। इस दौरान एक डेयरी संचालक पर रासुका का मामला दर्ज कराया। वहीं, एंटी माफिया मुहिम को भी पूरी ताकत से अंजाम दे रही हैं। बकौल शिवाली, फिलहाल शहर में एंटी माफिया मुहिम जारी है, जिसमें आने वाले दिनों में कई और बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती हैं। नौकरी और परिवार के बीच सामंजस्य बनाने के सवाल पर शिवानी बताती हैं कि उनके पति का इसमें भरपूर सहयोग मिलता है।

निकाल रहीं दबंगों की दबंगई... : गुना के मावन क्षेत्र में एक दंबग 30 साल से 50 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए था, जिसकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपये है। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए शिवानी ने खुद टीम की अगुवाई की, गर्मागर्मी के बीच ट्रैक्टर-जेसीबी भी चलाना पड़ा, चलाकर यह जमीन मुक्त कराई। इससे पूरी टीम को हौसला मिला और दबंगों में खौफ कायम हुआ। इसी तरह 35 साल से 60 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए दबंग से उन्होंने सरकारी जमीन वापस ली। सुबह पांच बजे टीम लेकर पहुंचीं और खुद जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

मध्य प्रदेश के गुना में पदस्थ युवा एसडीएम शिवानी गर्ग। नईदुनिया

छठवीं पीढ़ी में मिलेगी पशुओं की शुद्ध नस्ल, सुधार के चल रहे प्रयास

मनोज चौधरी, मथुरा

- कृत्रिम गर्भाधान से सुधारी जा रही बिगड़ी नस्ल
- गाय की चार और भैंस की एक नस्ल में किया जाएगा बदलाव

प्रतीकात्मक

दुधारू गाय और भैंस की नस्ल क्रॉस ब्रीडिंग से बिगड़ गई है। पशुओं की नस्ल सुधारने में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान कारगर साबित हो रहा है। सूबे के कई जिलों में योजना लागू की गई है। इसमें मथुरा जिले के 300 गांव भी शामिल हैं। कृत्रिम गर्भाधान से बिगड़ी नस्ल को नई नस्ल में परिवर्तित किया जाएगा। माना जा रहा है इस योजना से पशुओं की छठवीं पीढ़ी की शुद्ध नस्ल पशु पालकों को मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना किए जाने की घोषणा की है। उसमें कृषि के साथ पशुपालन भी शामिल है लेकिन दुधारू पशुओं की कई नस्ल ऐसी हैं, जो काफी कम दूध देती हैं। वर्तमान समय में मथुरा में पशुओं की दुग्ध क्षमता 300 दिन में औसतन 1000 से 1500 लीटर तक है। यहां गाय की देसी नस्ल लगभग पूरी बिगड़ चुकी है। इसके विपरीत कई राज्यों में गाय की साहीवाल, हरियाणा, जर्सी और हाल्सटीन फ्रिजियन के अलावा मुर्रा नस्ल की भैंस इतने ही दिन में औसतन 3000 लीटर से अधिक दूध देतीं हैं। देसी नस्ल खराब होने के पीछे कारण क्रॉस ब्रीड माना गया है। नस्ल सुधार के लिए बिगड़ी नस्ल के पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के जरिये साहीवाल, हरियाणा, जर्सी, हाल्सटीन फ्रिजियन के अलावा मुर्रा नस्ल में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी ऐसे ही नस्ल बिगड़ चुकी है।

जिलों के सौ-सौ गांव चयनित : कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में 100-100 गांव चुने गए हैं, लेकिन मथुरा में चुने गए गांवों की संख्या 300 है। यहां अधिक संख्या के पीछे गायों की संख्या अधिक होना माना जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में निश्शुल्क कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. एसके मलिक कहते हैं कि गर्भाधान में पहले साल 30 फीसद तक पशुओं की नस्ल में बदलाव होता है और दूसरी दफा में यह 50 फीसद तक हो जाता है। छठवीं पीढ़ी में जाकर शुद्ध नस्ल पशुपालक को मिल जाएगी। ऐसा कई शोध में प्रमाणित भी हो चुका है। उनका कहना है कि इसके लिए पशुपालक को इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि वह जिस नस्ल के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करा रहा है, वह लगातार छह बार उसी सीमन से कराए। सीमन बदल गया, तो फिर नस्ल में सुधार नहीं हो पाएगा।

नियाग्रा को टक्कर देगा उप्र का राजदरी-देवदरी जलप्रपात

उत्तर प्रदेश के चंदौली में राजदरी का विहंगम दृश्य। जागरण

अशोक सिंह, वाराणसी

- चंदौली की शांत व सुरम्य वादियों में इस नक्सल इलाके को इको टूरिज्म सेंटर के रूप में किया जाएगा विकसित
- पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने किया निरीक्षण
- पर्यावरण और वन्य जीवों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ने का रखेंगे ध्यान

यूं तो विश्व का सबसे ऊंचा नियाग्रा फाल कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है लेकिन प्रदेश के चंदौली में भी उसे टक्कर देने वाला राजदरी-दवेदरी जल प्रपात है। यहां कभी नक्सलियों का बोलबाला रहने से पहुंचना खतरों भरा भी रह। रिमझिम फुहारों के बीच चंद्रप्रभा की हसीन वादियों में पूर्वांचल के सैलानियों का सबसे सुहाने पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने की शासन की मंशा है। इसके विकास का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है।

इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यटन राज्यमंत्री डा. नीलकंठ तिवारी स्वयं राजदरी व देवदरी स्थल का दौरा किया और उसे इको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित करने का खाका खींचा। मंत्री ने कहा कि यहां होने वाले कामों से पर्यावरण और वन्य जीवों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ना चाहिए। उन्होंने देवदरी के लिए आगणन तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजदरी से देवदरी के आंतरिक मार्ग का पैदल भ्रमण कर निर्देशित किया कि उक्त मार्ग को सुदृढ़ किया जाए। पर्यटक इस मार्ग का उपयोग नेचर ट्रेल के रूप में कर सकें।

अद्भुत सुंदरता का स्थल : जलप्रपात अपनी नैसर्गिक सुंदरता के साथ पक्षियों की चहचहाहट व वन्य जीवों के पदचाप से गुलजार रहता है। बरसात शुरू होते ही अद्भुत नजारा हो जाता है। बड़ी चट्टानों से टकराती चंद्रप्रभा का जल जब पूरे वेग से सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरता है तो उसका आकर्षक दृश्य देख रोम-रोम पुलकित हो उठता है। राजदरी से एक किमी दूर देवदरी का जलप्रपात है। यहां राजदरी से आने वाला पानी ही गिरता है।

होने वाले प्रमुख कार्य

- राजदरी में सेल्फी प्वाइंट का निर्माण
- बनेगा नेचर ट्रेल और पाथवे
- पांच सौ लोगों के लिए ऑडिटोरियम
- सैलानियों के लिए डॉरमेट्री हाल और कैफेटेरिया
- पर्यटकों को बैठने के लिए बेंच
- बोल्डर पीचिंग
- जानकारी के लिए जगह-जगह लगेंगे साइनेज

पहल

जैन समाज की अनोखी मुहिम, पक्षियों के लिए बनाया 21 मंजिला आशियाना, 36 फीट ऊंचे भवन में 252 आशियाने, हर मंजिल पर पक्षियों के लिए 12 फ्लैट्स

दाना-चुग्गा न मौसम की चिंता, अब परिंदों का 'मेरा आशियाना'

आनंद भार्गव, सिरसा

अहिंसा परमो धर्मः का संदेश देने वाले जैन धर्म के अनुयायियों ने सिरसा में एक अद्भुत प्रयोग किया है। लगातार बढ़ते कंकरीट के जंगल के बीच आशियाना बनाने से वंचित परिंदों को आश्रय देने के लिए मेरा आशियाना बनाया है।

रानियां रोड स्थित ऐतिहासिक दादाबाड़ी मंदिर में तैयार किए गए 36 फीट ऊंचे 21 मंजिला आशियाने में परिंदों को न तो दाना पानी की चिंता होगी और न ही खराब मौसम व कुत्ते-बिल्ली जैसे शत्रुओं का भय। जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर बने इस आशियाने में पक्षियों के लिए 252 आशियाने बनाए गए है। प्रत्येक मंजिल पर 12 फ्लैट्स बनाए गए है, जो एक फुट चौड़े, चार फुट गहरे व पंद्रह इंच ऊंचे होंगे। इनमें रोशनी, हवा का प्रबंध है। साथ ही समय-समय पर सफाई भी हो सकेगी।

आशियाने के नीचे पक्षियों के लिए करीब एक हजार वर्ग फुट लंबाई चौड़ाई का तथा जमीन से चार फुट ऊंचा चबूतरा तैयार किया गया है, जिस पर पक्षियों के लिए दाने डाले जा सकेंगे। यहीं पर पक्षियों के लिए पीने के पानी का प्रबंध तथा फव्वारा भी लगाया गया है। आशियाने पर सबसे ऊपर 15 फीट ऊंची मोर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो इस आशियाने की सुंदरता को और बढ़ाएगी।

घायल पक्षियों के इलाज को 45 लाख से बनेगा अस्पताल : महासचिव संदीप नाहटा ने बताया कि पक्षियों के लिए बनाए गए इस आशियाने का शुभारंभ जैन साध्वी श्रुति महाराज करेंगी। इसके साथ ही जैन समुदाय द्वारा पक्षियों के इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें घायल पक्षियों के इलाज का प्रबंध किया जाएगा। पक्षियों के इलाज के लिए एक दुपहिया एंबुलेंस की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जो सिरसा और आसपास के क्षेत्रों से घायल पक्षियों का इलाज करेगी। इस अस्पताल पर करीब 45 लाख रुपये खर्च होंगे।

पानीपत के सेक्टर 11-12 में पक्षियों के लिए बनाया गया आशियाना। जागरण

पानीपत में भी है पक्षियों का चौदह मंजिला आशियाना

जागरण संवाददाता, पानीपत : औद्योगिक नगर में पहली बार पक्षियों का आशियाना बनाया गया। यह आशियाना पॉस इलाके सेक्टर 11-12 में एंजल मॉल के सामने है। भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इसे बनाया गया है। पक्षियों के लिए बनाए गया यह आशियाना 51 फीट ऊंचा और 14 मंजिला है। इस घर में एक साथ 1000 जोड़े पक्षी आराम से रह सकेंगे। ट्रस्ट के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि सनौली रोड पर एक पक्षी अस्पताल भी चलाया जा रहा है। जैन समाज के सिद्धांत है जीयो और जीने दो। पक्षियों के आशियाने में रहने के साथ-साथ खाने पीने की सुविधा भी दी जा रही। सुरेश कुमार ने बताया कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जिससे शहरों में पक्षियों को रहने की समस्या बनती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही यह आशियाना बनाया गया है। अन्य शहरों में आशियाना बनाने की योजना है। पक्षी यहां प्रजनन भी कर सकेंगे। कुत्ता और बिल्ली आशियाने के पक्षियों तक नहीं पहुंच सकें इसका पूरा ख्याल रखा गया है।

यूएस, जापान और ईयू ने की सब्सिडी रोधी नियम बनाने की मांग

वाशिंगटन : अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन (ईयू) सब्सिडी संबंधित नए नियम बनाने को लेकर लामबंदी कर रहे हैं। ये देश सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाने के लिए डब्ल्यूटीओ से नए नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारें अपनी कंपनियों को कारोबारी सहायता देकर ग्लोबल ट्रेड में प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से प्रभावित करती हैं। पश्चिमी देश लंबे समय से सब्सिडी देने को लेकर चीन पर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। (एएफपी)

खुदरा बाजार में कीमतों को थामने के लिए प्याज आयात किया गया। अब राज्य खरीदने से पीछे हट रहे हैं। कल कोई यह न कहने लगे कि गोदामों में प्याज सड़ रहा है।
— रामविलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री

संसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,952.63 ▲ 92.94	12,362.30 ▲ 32.75	₹ 40,422 ▼ ₹61	₹ 47,083 ▼ ₹602	₹ 70.87 ▲ ₹0.1	$ 64.53

न्यूज गैलरी

कैबिनेट सचिव ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली : कैबिनेट सचिव ने ग्रोथ और निवेश के पांच वर्षीय लक्ष्य पर विचार के लिए इसी महीने की 20 तारीख को बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के पांच सचिवों के अलावा अलग-अलग मंत्रालयों के सचिव भाग लेंगे। बैठक में कैबिनेट सचिव विभिन्न सेक्टर के सचिवों की समितियों (सीओएस) से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विमर्श करेंगे और पांच वर्षों के लक्ष्य पर आधारित प्रजेंटेशन देखेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह इकोनॉमिस्ट, सेक्टरों के विशेषज्ञों और कारोबारियों के साथ मुलाकात की थी और पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य पर केंद्रित योजना बनाने को कहा था। (आइएएनएस)

हरियाणा में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस देंगे पांच हजार नौकरियां

नई दिल्ली : अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हरियाणा में दो नए गोदाम (वेयर हाउस) स्थापित किए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर पांच हजार से अधिक नौकरियां पैदा होने की बात कही गई है। वालमार्ट के मालिकाना हक वाली ई-कॉमर्स कंपनी ने बताया कि वह अपनी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास की योजना पर कार्य कर रही है। कंपनी के मुताबिक ये वेयर हाउस नौ लाख वर्ग फुट में फैले हैं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इससे उत्तर भारत में कंपनी अपनी आपूर्ति बढ़ा सकेगी। इसके साथ ही अब हरियाणा में कंपनी के कुल 12 वेयर हाउस हो गए हैं। (प्रेट्र)

भारत-चीन द्विपक्षीय कारोबार में गिरावट

बीजिंग : पिछले वर्ष भारत और चीन के द्विपक्षीय कारोबार में करीब 300 करोड़ डॉलर (21,000 करोड़ रुपये) की गिरावट आई है। इस दौरान भारत के व्यापार घाटे में भी बड़ा इजाफा हुआ है। समीक्षाधीन अवधि में चीन के साथ देश का व्यापार घाटा 5,677 करोड़ डॉलर रहा। इस संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि में दोनों देशों के बीच 63,952 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। चीन द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात में 2.1 परसेंट का इजाफा हुआ। चीन की ओर से होने वाला निर्यात 51,563 करोड़ डॉलर रहा। वहीं भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 0.2 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच भारत सरकार चीन से आयात होने वाली एक दवा पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। यह दवाई बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। (प्रेट्र)

थोक बाजार में भी सिर उठाने लगीं कीमतें, बढ़ी महंगाई

मुश्किल ▶ बदलते हालात में सस्ते कर्ज की उम्मीदें हुईं धूमिल

दिसंबर में थोक महंगाई की दर 2.59 फीसद पर, आठ महीने में सर्वाधिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

खाने पीने के सामान की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते महंगाई फिर से सिर उठाने लगी है। दिसंबर, 2019 में थोक महंगाई की दर 2.59 फीसद हो गई। यह पिछले आठ महीने में सर्वाधिक है। नवंबर में थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर 0.58 फीसद रही थी। हालांकि दिसंबर, 2018 में महंगाई की यह दर 3.46 फीसद रही थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर, 2019 में खाने पीने के सामान की महंगाई दर 13.12 फीसद रही है। नवंबर में यह 11 फीसद थी। गैर खाद्य उत्पादों की महंगाई दर में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यह नवंबर के 1.93 फीसद से करीब चार गुणा 7.27 फीसद हो गई है। गौरतलब है कि दिसंबर में खुदरा महंगाई की दर भी बीते पांच साल के अधिकतम पर रही है।

जहां तक खाद्य उत्पादों का सवाल है, उनमें महंगाई की मार सबसे अधिक सब्जियों पर दिखी है। दिसंबर में सब्जियों की कीमतों में 69.69 फीसद की वृद्धि देखी गई है। इसमें भी सर्वाधिक हिस्सेदारी प्याज की है जिसकी थोक महंगाई दर दिसंबर में 455.83 फीसद रही है। इसके अलावा आलू की कीमतों में भी 44.97 फीसद का उछाल आया है। विभिन्न बाजारों में प्याज की कीमतें अब भी 100 रुपये किलो के आसपास बनी हुई हैं। हालांकि नई फसल की बाजार में आवक शुरू होने से इसकी कीमतों में नरमी आने लगी है।

थोक और खुदरा दोनों प्रकार की महंगाई की दर में तेज उछाल ने रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में कमी की संभावनाओं को धूमिल कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में खुदरा महंगाई की दर अभी और बढ़ने की आशंका है। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद नहीं की जा सकती। एसबीआइ के इकोनॉमिक रिसर्च विभाग ने अनुमान लगाया है कि जनवरी, 2020 में खुदरा महंगाई की दर आठ फीसद के आंकड़े को छू सकती है। हालांकि इसके बाद महंगाई में नरमी के रुख के आसार हैं।

आंकड़ों के मुताबिक मैन्यूफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के वर्ग में महंगाई की दर में 0.25 फीसद की कमी दर्ज की गई है। लेकिन मैन्यूफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर में वृद्धि हुई है। यह दिसंबर में 6.89 फीसद रही है। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेल, एनीमल ऑयल एंड फैट्स के वर्ग की महंगाई दर भी 9.66 फीसद रही है।

थोक महंगाई में खाने-पीने की वस्तुओं की बढ़ी कीमतों का अहम योगदान रहा। प्रतीकात्मक फोटो

बड़ी चुनौती से पार पाने को बड़े सुधारों की दरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने से उद्योग जगत चिंतित

▶ आनंद महिंद्रा ने ब्लॉकबस्टर बजट की उम्मीद जताई

देश की आर्थिक विकास दर के घटने से चिंतित उद्योग जगत को महंगाई के तेवर ने और परेशान कर दिया है। देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों ने तो वित्त मंत्री से अब 'ब्लॉकबस्टर बजट' पेश करने की गुहार लगानी शुरू कर दी है ताकि अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाया जा सके। दूसरी तरफ कई एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अब राजकोषीय संतुलन से अधिक चिंता विकास दर करनी चाहिए। राजकोषीय घाटा अगर अगले वित्त वर्ष के दौरान 3.5 फीसद के करीब भी रहता है तो यह चिंता की बात नहीं होगी। अर्थव्यवस्था से जुड़े ताजा आंकड़ों को देखते हुए कुछ एजेंसियां यह कह रही हैं कि सरकार के पास इस बार करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा।

चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर के पांच फीसद पर सीमित रहने पर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, 'इस विकास दर के साथ हम फिर चीन से पिछड़ जाएंगे। हमारी प्रतिस्पर्धी क्षमता को फिर से बाहर लाने की जरूरत है। वित्त मंत्री जी अपने ब्लॉकबस्टर बजट से फिर से दुनिया को चौंकाने का काम कीजिए। इसमें कुछ नाटकीय कदमों को जोड़िए।' देश के प्रमुख उद्योग चैंबर सीआइआइ की तरफ से बजट पर सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें महंगाई दर के मध्यावधि लक्ष्य की तरह ही राजकोषीय घाटे का भी मध्यावधि लक्ष्य तय करने और इसे लचीला (ताकि जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सके) बनाने को कहा है। राजकोषीय घाटे को लचीला बनाकर विकास के लिए ज्यादा पैसे का इंतजाम किया जा सकता है। आगे चलकर दो-तीन वर्ष में राजकोषीय घाटे को एक निर्धारित समयसीमा में काबू करने की रणनीति बनाई जा सकती है। कहने की जरूरत नहीं कि सीआइआइ के इस सुझाव को मानना सरकार का बड़ा कदम होगा। आर्थिक क्षेत्र के कई अन्य जानकार भी कमोबेश बजट को लेकर ऐसी ही राय रखते हैं। बाजार में मांग बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी।

बड़े कदम उठाना मुश्किल

दूसरी तरफ मंगलवार को एचडीएफसी बैंक की तरफ से आगामी बजट पर अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। बैंक मानता है कि हालात ऐसे नहीं हैं कि सरकार कोई बड़े कदम उठा सके। मौजूदा व पुराने बजटीय प्रस्तावों में कुछ इधर-उधर करके बजट पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्री न तो सरकारी खर्चे में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि करने की स्थिति में हैं और न ही राजस्व की स्थिति को देखते हुए करों की दरों में कोई बड़ा बदलाव कर सकती हैं।

ब्याज दरें बढ़ने का खतरा

मोतीलाल ओसवाल समूह की आर्थिक शोध विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा महंगाई की दर के पिछले साढ़े पांच वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब ब्याज दरों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अगर अगले दो महीनों के दौरान सब्जियों की कीमतों में नरमी आ भी जाती है, तब भी कुल महंगाई की दर सात फीसद के आसपास बनी रह सकती है। इससे पूरे वर्ष 2020 के दौरान महंगाई दर के पांच फीसद से ऊपर बने रहने की आशंका है, जो चिंताजनक है।

सड़क मंत्रालय ने बजट में मांगे डेढ़ लाख करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ आर्थिक सुस्ती के कारण सड़क निर्माण की रफ्तार हुई रोजाना 25 किमी से कम

चालू वर्ष में सड़क निर्माण की सुस्त हो गई चाल को रफ्तार देने के लिए सड़क मंत्रालय ने सरकार से बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की है। मंत्रालय का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण निजी निवेश के बीओटी और हाइब्रिड-एन्यूटी मॉडल विफल हो गए हैं और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकारी निवेश पर आधारित ईपीसी मॉडल अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) पर कर्ज के बोझ को कम करने के लिए भी सरकारी निवेश में बढ़ोतरी जरूरी हो गई है।

आर्थिक सुस्ती के चलते चालू वित्त वर्ष (2019-20) के दौरान सड़क निर्माण की रफ्तार पिछले वर्ष के 30 किलोमीटर रोजाना से घटकर 25 किलोमीटर प्रति दिन से कम रह गई है। इसमें एनएचएआइ ने जहां 2017-18 में 3320 किमी सड़कों का निर्माण किया था, वहीं चालू वित्त वर्ष में 4500 किमी के लक्ष्य के विपरीत दिसंबर तक लगभग 2900 किमी सड़कें बन पाई थीं। सुस्ती के कारण बीओटी और हाइब्रिड-एन्यूटी परियोजनाओं से जुड़ी सड़क निर्माता कंपनियों को कर्ज देने में बैंक आनाकानी करने लगे हैं। इससे परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। इसे देखते हुए सड़क मंत्रालय ने अब बीओटी और हाइब्रिड-एन्यूटी के बजाय ईपीसी मॉडल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। पिछले चार-पांच महीनों के दौरान एनएचएआइ द्वारा अवार्ड की गई लगभग सभी परियोजनाएं ईपीसी आधारित हैं।

लगातार बढ़ा है बजट आवंटन : सड़क निर्माण के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखते हुए सरकार पिछले तीन साल से सड़क मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी करती आ रही है। 2017-18 में मंत्रालय को लगभग 61 हजार करोड़ तो 2018-19 में लगभग 79 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन हुआ था। भारतमाला प्रोजेक्ट के मद्देनजर जुलाई में पेश 2019-20 के बजट में 83 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में एक रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।

बढ़ता कर्ज भी चुनौती : सड़क निर्माण में वृद्धि की चुनौती के अलावा एनएचएआइ पर बढ़ रहे कर्ज को काबू में करने के लिए भी सड़क मंत्रालय की ओर से ज्यादा बजट की मांग की गई है। पिछली सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनएचएआइ अब तक 1.85 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुका है। इससे उस पर इनके मूलधन के अलावा ब्याज अदायगी का बोझ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। सड़क मंत्रालय नहीं चाहता है कि कर्ज और बढ़े। इसके लिए मंत्रालय ने पिछले दिनों एनएचएआइ को पूरी हो गई सड़क परियोजनाओं से धन जुटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने का अधिकार कैबिनेट से दिलवाया है।

क्या हैं सड़क निर्माण के मॉडल? : सड़क निर्माण के बीओटी मॉडल में पूरा पैसा निजी कंपनी लगाती है और बाद में टोल के जरिये मुनाफा समेत उसकी भरपाई करती है। हाइब्रिड-एन्यूटी मॉडल में 40 फीसद राशि सरकार अग्रिम तौर पर निर्माता कंपनी को देती है, जबकि शेष 60 फीसद राशि कंपनी को खुद जुटानी होती है। सरकार का पैसा बाद में कंपनी टोल वसूलकर वापस कर देती है। ईपीसी में कांट्रैक्ट लेने वाली कंपनी को सरकार से पूरा पैसा मिलता है। सड़क बनने के बाद सरकार अपने पैसे की भरपाई टोल के ठेके उठाकर करती है।

प्रतीकात्मक फोटो

मैन्यूफैक्चरिंग से टूटता जा रहा है पानीपत का मोह

महावीर गोयल, पानीपत

▶ पानीपत के 18000 लघु उद्योगों में तीन लाख से अधिक को मिला है रोजगार

▶ मुश्किलों के चलते उत्पादन छोड़ ट्रेडिंग की ओर रुख करने लगे हैं उद्यमी

▶ अलग-अलग राज्यों से कपड़े मंगाकर यहां बेचने का चलन बढ़ने लगा

हैंडलूम सिटी पानीपत को देश-दुनिया में टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है। अपनी काबिलियत से यहां के टेक्सटाइल उद्योग ने कोने-कोने में अपनी पहचान बनाने में सफलता पाई है। यही वजह है कि आप चाहे कहीं रह रहे हों, आपके घर में इस्तेमाल हो रहे चादर, तकिया, कंबल, परदे, तौलिया, बाथमैट आदि का पानीपत से नाता मिल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल उद्योगों को जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि शायद कुछ साल बाद पानीपत का यह रुतबा फीका पड़ जाएगा।

पानीपत के करीब 18,000 लघु उद्योगों में तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें ज्यादातर उद्योग टेक्सटाइल से संबंधित हैं। इन उद्योगों ने मैन्यूफैक्चरिंग के दम पर खुद को स्थापित किया है। लेकिन अब यहां के उद्यमियों का मोह मैन्यूफैक्चरिंग से टूटने लगा है। बढ़ती लागत और अन्य परेशानियों के कारण उद्यमी किनारा करने लगे हैं। अग्रणी टेक्सटाइल उत्पादक सीधे ट्रेडिंग के क्षेत्र में कूद रहे हैं। मुंबई, गुजरात और अन्य प्रदेशों से कपड़े मंगाकर यहां बेचा जा रहा है। कारपेट बनाने में पानीपत का विशेष स्थान था, लेकिन अब यहां चीन के बने कारपेट बिक रहे हैं। ट्रेडिंग की ओर रुख होने से लोगों के रोजगार पर भी संकट के बादल दिखने लगे हैं। धागा बनाने के नए प्लांट भी नहीं खुल रहे हैं। पुराने भी उत्पादन कम करने पर मजबूर हैं। पिछले चार साल से निर्यात भी स्थिर है। निर्यात का आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ ही नहीं पा रहा।

अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी की मांग : इस समय परिस्थितियों की जरूरत को देखते हुए उत्पादन सस्ता करने के लिए टेक्सटाइल उद्योगों में लगी मशीनों के अपग्रेडेशन की जरूरत है। उद्यमियों का कहना है कि केंद्र सरकार बजट में उद्योगों को अपग्रेड करने के लिए मशीनरी आयात में सब्सिडी का प्रावधान करे तो सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। बजट में मदद दी जाए तो पानीपत के उद्यमी चीन से सस्ता उत्पादन करने में सक्षम हैं। वैसे भी चीन से कम लागत में मिंक ब्लैंकेट, पोलर ब्लैंकेट और बेडशीट बनाकर यहां के उद्यमी अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं। चीन की तरह भारत सरकार को भी उद्यमियों की मदद करनी चाहिए।

उद्योगों को लाल फीताशाही से भी हो रही मुश्किल

एकता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आरबी गुप्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश में नई टेक्सटाइल यूनिट लगाने पर 40 फीसद सब्सिडी मिल रही है। बिजली भी सस्ती है। वहीं पानीपत में लाल फीताशाही के चलते उद्यमियों की उत्पादन में रुचि कम हो रही है। मनरेगा लागू होने के बाद लेबर की समस्या भी बढ़ गई है। यही वजह है कि उद्यमी ट्रेडिंग को अपना रहे हैं।

सरकार से साथ की गुहार

- उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो
- कुशल कामगार भी उद्योगों की जरूरत
- नया इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बनाने की भी जरूरत

अमेरिका ने चीन को करेंसी मैनीपुलेटर की सूची से हटाया

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका और चीन के बीच होने जा रहे पहले दौर के कारोबारी समझौते से पहले अमेरिका ने चीन को करेंसी से छेड़छाड़ करने वाले (करेंसी मैनीपुलेटर) देशों की सूची से हटा दिया है। उसने चीन को पिछले वर्ष इस सूची में डाला था। समझौते पर हस्ताक्षर से ठीक पहले वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि चीन का यूआन मजबूत हुआ है, इसलिए उसे अब करेंसी मैनीपुलेटर माना जाना ठीक नहीं है। इस कदम को समझौते से पहले गुडविल संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जानबूझकर करेंसी को कमजोर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने अपनी करेंसी को कमजोर करके अमेरिकी कारोबार और फैक्टरियों को हड़पने की कोशिश की है। पिछले वर्ष चीन ने अपनी करेंसी यूआन को प्रति डॉलर सात के स्तर तक गिरा दिया था। यह बाद में सुधरकर एक डॉलर के मुकाबले 6.93 यूआन के स्तर तक आ गई।

कम हुआ चीन का ट्रेड सरप्लस : चीन और अमेरिका में लगभग दो वर्ष तक चले ट्रेड-वार के चलते चीन के ट्रेड सरप्लस में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल चीन के ट्रेड सरप्लस में 8.5 परसेंट की गिरावट आई। इस दौरान चीन का ट्रेड सरप्लस करीब 29,580 करोड़ डॉलर रहा। 2018 में चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस 32,330 करोड़ डॉलर रहा था। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनातनी के चलते शुल्क में कई बार इजाफा किया गया था।

समझौते की तारीख करीब : अमेरिका और चीन में पहले दौर के समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि करीब है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपिओ ने सिलिकॉन वैली को चीन के साथ कारोबार को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे की संपन्नता के लिए अमेरिकी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहे हैं। पोंपिओ के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कारोबारियों के हितों को सर्वोपरि रखकर चीन के साथ समझौता कर रहा है।

अगले साल से गहनों पर हॉलमार्क अनिवार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अगले साल से सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क वाले सोने के गहने बेचे जा सकेंगे। वर्तमान में सोने के आभूषण 10 अलग-अलग ग्रेड में उपलब्ध हैं। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि यह नई व्यवस्था 15 जनवरी, 2021 से प्रभाव में आएगी। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना और एक साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया जाएगा।

पासवान ने बताया कि सोने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लाई गई इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए आभूषण विक्रेताओं को एक साल का वक्त दिया गया है। इस दौरान वे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) से पंजीकरण करा सकते हैं और अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रणाली लागू करने की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को सोने की पहचान के लिए चार चिह्नों को ध्यान में रखना होगा। इसमें बीआइएस मार्क, कैरेट में शुद्धता, जांच करने वाले केंद्र का नाम और ज्वैलर्स की पहचान वाला निशान शामिल है।

इस समय देश में 234 स्थानों पर सोने के 892 जांच केंद्र हैं। 28,849 ज्वैलर्स बीआइएस के साथ पंजीकृत हैं। पासवान ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक जिले में हॉलमार्क सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए उपलब्ध समय के दौरान हम ज्यादा से ज्यादा ज्वैलर्स को बीआइएस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जल्द ही जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं के हित को सुनिश्चित किया जा सकेगा और उन्हें संभावित धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। बीआइएस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि हॉलमार्किंग के नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक हॉलमार्किंग नहीं करने वालों से एक लाख रुपये या गहनों की कीमत का पांच गुना जुर्माना लिया जाएगा। उन्हें एक साल की जेल भी हो सकती है।

केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बना आयातित प्याज

प्याज की बढ़ी कीमतों को थामने के लिए आयात किया गया प्याज अब सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा यातायात का खर्च वहन करने के बावजूद राज्य सरकारें इसे खरीदने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि केंद्र इसे 55 रुपये प्रति किलो के आयातित भाव पर राज्यों को देने और गंतव्य तक पहुंचाने का खर्च भी उठाने को तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्याज सड़ने की बात कहकर अदालत चला जाए। करीब 36 हजार टन प्याज आयात करने संबंधी करार हुए हैं, जिसमें से अधिकतर प्याज पहुंच चुका है। पासवान ने बताया कि तमाम अनुरोध के बाद भी राज्यों ने इसमें से सिर्फ दो हजार टन प्याज खरीदा है। सितंबर में प्याज की खुदरा कीमतें 170 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थीं। इसे नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार ने तुर्की और मिस्र जैसे देशों से भारी मात्रा में प्याज आयात का सौदा किया था। अब स्थानीय स्तर पर आपूर्ति सुधरने से राज्यों को आयातित प्याज महंगा पड़ने लगा है।

उम्मीदें

राजस्थान व अन्य राज्यों के अस्पतालों की खस्ता हालत बच्चों की मौत की बड़ी वजह, 2025 तक स्वास्थ्य बजट को जीडीपी के 2.5 फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य

सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने को हो सकता है बड़ा एलान

नीलू रंजन, नई दिल्ली

आगामी बजट में केंद्र सरकार सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए बड़ा एलान कर सकती है। राजस्थान के कोटा व अन्य राज्यों के अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। ऐसे में देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी कर डॉक्टरों की कमी दूर करने के फैसलों के बाद सरकारी अस्पतालों के हालात सुधारना सरकार की प्राथमिकता में है।

दरअसल केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जा रही है। लेकिन कोटा के अस्पताल में जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने और चिकित्सा उपकरणों के सुचारू रूप से काम नहीं करने व स्टाफ की कमी का मामला सामने आने के बाद सरकार इस सहायता को और बढ़ाने तथा अस्पतालों में उनके इस्तेमाल की निगरानी की जरूरत महसूस कर रही है। इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके लिए किसी बड़ी योजना का एलान कर सकती हैं।

दरअसल आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। इसके लिए दो साल पहले बजट में देश के 50 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त और कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई थी। अभी तक इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक गरीबों का इलाज हो चुका है। इसके साथ ही 2022 तक आम लोगों की पहुंच में अत्याधुनिक जांच सुविधाओं को लाने के लिए पूरे देश में डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलने का काम भी चल रहा है। लेकिन आयुष्मान भारत के तहत केवल गंभीर बीमारियों के लिए द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी के अस्पतालों में इलाज की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में गरीबों का एकमात्र सहारा सरकारी अस्पताल होता है।

मोदी सरकार ने 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में चिकित्सा बजट में बढ़ोतरी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके तहत 2025 तक चिकित्सा बजट को कुल जीडीपी के 2.5 फीसद तक पहुंचाना है। इसे देखते हुए पिछले साल बजट में चिकित्सा क्षेत्र के आवंटन को 55,959 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 64,559 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि अब भी बजटीय आवंटन जीडीपी के एक फीसदी से ज्यादा नहीं है। जाहिर है अगले पांच साल के भीतर बजटीय आवंटन में ढाई गुना तक बढ़ोतरी की शुरुआत इस साल से देखी जा सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा के लिए पांच लाख 38 हजार करोड़ की जरूरत : अगले पांच साल में देश में प्राथमिक चिकित्सा के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पांच लाख 38 हजार 305 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। 15वें वित्त आयोग के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मांग रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर दिए गए प्रजेंटेशन के अनुसार देश में प्राथमिक चिकित्सा में आधारभूत ढांचे का बेहद अभाव है। वेलनेस सेंटर के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने, स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर करने, राष्ट्रीय एंबुलेंस सर्विस को सुचारू रूप से चलाने के साथ जांच उपकरणों और दवाओं के लिए बड़े पैमाने पर धन की जरूरत पड़ेगी। वित्त आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल के साथ मिलकर इसके लिए नए सिरे प्रस्ताव तैयार कर देने को कहा है।

सरकार की प्राथमिकता में है बेहतर चिकित्सा व्यवस्था। प्रतीकात्मक फोटो

शेयर बाजारों में बढ़त का सिलसिला कायम

मुंबई, प्रेट्र : पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मंगलवार को भी भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी बरकरार रही। इस दौरान प्रमुख सूचकांक सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। शेयर बाजारों की तेजी में एचडीएफसी, आइटीसी, एक्सिस बैंक और टीसीएस जैसे बड़े स्टॉक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 92.94 अंकों की बढ़त के साथ 41,952.63 के सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। इंट्रा-डे के दौरान यह 41,994.26 तक पहुंच गया था। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 32.75 अंकों का सुधार हुआ। यह 12,362.30 के सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.15 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। कारोबार के दौरान आइटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एचडीएफसी और टीसीएस के शेयरों में भी बढ़त देखी गई।

14 लोग जख्मी और 10 लोग लापता हैं उत्तर-पश्चिमी चीन के किंगघई प्रांत में एक व्यस्त सड़क पर गड्ढा बन जाने से। दरअसल, अचानक गड्ढा होने से उनमें वहां से गुजर रही एक बस समा गई और इसके बाद उसमें एक विस्फोट भी हो गया।

टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद ने खुद को बताया निर्दोष

- पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत आज सुनेगी अंतिम दलीलें
- कवरेज के लिए पत्रकारों को अदालत कक्ष में प्रवेश की नहीं है अनुमति

लाहौर, प्रेट्र: मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने टेरर फंडिंग के दो मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। आतंकी समूहों पर नकेल कसने के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच जमात उद दावा के सरगना ने मंगलवार को यहां आतंकवाद रोधी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। पाक के आतंकवाद रोधी विभाग ने पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंकवाद के लिए वित्तीय मदद देने के मामलों में सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ 23 प्राथमिकी दर्ज की थीं और उसे 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसे लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है।

अदालत के एक अधिकारी ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद कहा कि आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) लाहौर द्वारा आतंकवाद संबंधी वित्तीय मदद के आरोपों को लेकर सौंपी गई प्रश्नवाली का सईद ने मंगलवार को जवाब दिया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि एटीसी बुधवार को अंतिम दलीलें सुनेगी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग के आवेदन पर लाहौर और गुजरांवाला शहरों में सईद के खिलाफ आतंकवाद के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के आरोपों में मामले दर्ज किए गए हैं। सईद को कड़ी सुरक्षा में एटीसी में पेश किया गया। कार्यवाही की कवरेज के लिए पत्रकारों को अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

हाफिज सईद। फाइल

पाकिस्तान में बर्फबारी और बारिश से 84 लोगों की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसियां : पाकिस्तान में भारी बर्फबारी और तेज बारिश के कारण 84 लोगों की मौत हुई है। रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार, गुलाम कश्मीर स्थित नीलम घाटी में पिछले 24 घंटे में आए हिमस्खलन से 15 गांव प्रभावित हुए। इस आपदा में 45 घर पूरी तरह तबाह हो गए। कम-से-कम 57 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। बचाव दलों ने 42 घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हिमस्खलन व भूस्खलन के चलते बलूचिस्तान में 14 और पंजाब में कम से कम सात लोगों की जान जा चुकी है। खराब मौसम में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं।

पाकिस्तान के राहत, आपदा एवं लोक रक्षा सचिव सैयद मोहिउद्दीन कादरी ने बताया कि भीषण हिमपात के कारण ऊंचाई वाले इलाकों का पूरे देश से संपर्क टूट गया है। लगातार वर्षा के कारण सियालकोट, गुजरात और पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्कों से जोड़ने वाली सड़कें भी बंद पड़ी हैं। जिसके कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।

लंदन में नवाज शरीफ की रेस्तरां में बैठे फोटो वायरल

- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके गंभीर स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए
- भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे शरीफ को मिली थी इलाज के लिए जमानत

इस्लामाबाद, एएनआइ : लंदन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के बीमार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह तस्वीर लंदन के एक रेस्तरां की बताई जा रही है, जिसमें वह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेताओं ने उनके गंभीर स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए हैं। शरीफ को इलाज के लिए गत 19 नवंबर को लंदन लाया गया था। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद शरीफ की हालत ज्यादा खराब होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलाज के लिए उन्हें जमानत मिली थी।

वायरल फोटो में नवाज शरीफ, पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और अपने बेटे हमजा के साथ रेस्तरां में बैठे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, इस फोटो के सामने आने के बाद पीटीआइ की अगुआई वाली पंजाब सरकार से नवाज को लंदन में लंबी छुट्टी हासिल करने में परेशानी होगी। नवाज शरीफ को इलाज के लिए अदालत से चार हफ्ते की छुट्टी मिली थी। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस अवधि को बढ़ाने की मांग की है। 23 दिसंबर को दिए अपने आवेदन के साथ, शरीफ ने अपनी चिकित्सा रिपोर्ट भी लगाई है। हालांकि, पंजाब सरकार द्वारा अभी शरीफ के आवेदन पर फैसला नहीं लिया जा सका है, सरकार द्वारा फिर से ताजा रिपोर्ट मांगी गई है।

सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस फोटो में नवाज शरीफ (मध्य में) अपने भाई और पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ (दाएं) व अन्य लोगों के साथ रेस्तरां में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर

इमरान के मंत्री ने साधा निशाना : संघीय मंत्री फवाद चौधरी ने कथित फोटो ट्वीट करते हुए पीएमएल-एन सुप्रीमो पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, लंदन के एक अस्पताल के आइसीयू में शरीफ का इलाज चल रहा है, वहां मौजूद सभी रोगी बेहतर महसूस कर रहे हैं।' बताया गया कि इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस तस्वीर पर भी चर्चा हुई।

पीएमएल-एन ने कहा, डॉक्टर की सलाह पर गए थे बाहर : पीएमएल-एन ने शरीफ के स्वास्थ्य पर राजनीति करने के लिए पीटीआइ नेताओं को लताड़ा और जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि डॉक्टरों ने उन्हें माहौल के बदलाव के लिए बाहर जाने की सलाह दी थी। लंदन में एक पीएमएल-एन नेता ने डॉन को बताया, डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को पर्यावरण के बदलाव के लिए बाहर जाने की सलाह दी है। वे जोर देकर कहते हैं कि ज्यादा देर तक घर के अंदर रहना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए, शरीफ बाहर जाने लगे हैं। ताजी हवा खाने के लिए रविवार को शरीफ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सैर की। एक रेस्तरां में एक चाय पी थी। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को सात साल कैद की सजा दी गई है। तबीयत के कारण वे जमानत पर हैं।

न्यूज गैलरी

लेबर पार्टी के नेता की दौड़ में भारतवंशी नंदी दूसरे चरण में

लंदन : ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता के लिए होने वाले चुनाव में भारतवंशी सांसद लीसा नंदी पहले पड़ाव को पार कर गईं हैं। सोमवार को पहले दौर के समापन के बाद नंदी 31 सांसदों के समर्थन के साथ दूसरे दौर में प्रवेश कर गईं हैं। इस चरण में नंदी का मुकाबला बर्मिंघम से लेबर पार्टी के सांसद जेस फिलिप के अलावा एमिली थॉर्नबेरी, कीर स्टारमर और रेबेका लौंगबेली से होगा। फिलहाल रेस में स्टारमर और लौंगबेली सबसे आगे चल रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले माह हुए संसदीय चुनाव में मिली पराजय के बाद लेबर पार्टी के प्रमुख जेरेमी कॉर्बिन ने अपना पद छोड़ने का एलान किया था। संसद में मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के नए नेता का एलान चार अप्रैल को होना है। इसके मद्देनजर नेता का चुनाव कई चरणों में संपन्न किए जा रहे हैं। दूसरे चरण के नामांकन का काम बुधवार को शुरू हो रहा है। लेबर पार्टी की सांसद लीसा नंदी ने पिछला संसदीय चुनाव ग्रेटर मैनचेस्टर के विगान सीट से जीता था। (आइएएनएस)

स्टंटबाजी करते अमेरिका में गई भारतवंशी छात्र की जान

वाशिंगटन : अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्टंटबाजी (छतों के बीच कूद रहे) में एक भारतवंशी मेडिकल छात्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सोमवार को एनआरआइ पल्स समाचार पत्र द्वारा दी गई खबर के मुताबिक, मृतक की पहचान ड्रेक्सल कॉलेज ऑफ मेडिसिन के 23 वर्षीय छात्र विवेक सुब्रमणि के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुब्रमणि और उसके दो दोस्त 11 जनवरी की रात को छतों के बीच कूदने का स्टंट रहे थे कि इसी दौरान विवेक नीचे गिर गया, जिसके बाद थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि विवेक ने दोस्तों के साथ शराब भी पी थी। (आइएएनएस)

बाजवा का विरोध करने वाला जनरल पाकिस्तान में कैद

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार का विरोध करने वाले एक वरिष्ठ जनरल को परिवार सहित घर में कैद कर लिया गया है। इस जनरल ने बाजवा के तीन साल के सेवा विस्तार के विरोध में सार्वजनिक बयान दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार सेना प्रमुख बाजवा के बाद सेना प्रमुख बनने के बड़े दावेदार थे। वह पाकिस्तानी सेना में बाजवा के बाद सबसे ज्यादा वरिष्ठ जनरल थे। प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत करने से जनरल सत्तार की सेना प्रमुख बनने की संभावना खत्म हो गई। इसलिए उन्होंने विरोध जताया था। (एएनआइ)

ईरान ने कुछ संदिग्धों को किया गिरफ्तार

यूक्रेन विमान हादसा ▶ पकड़े गए लोगों और उनकी संख्या के बारे में नहीं दी कोई जानकारी

राष्ट्रपति रूहानी ने कहा, हादसे के जिम्मेदारों को दंडित किया जाना चाहिए

तेहरान, एजेंसियां : अंतरराष्ट्रीय दबावों में घिरे ईरान ने मंगलवार को बताया कि उसने यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराए जाने के मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी सामने आने के कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा था कि विमान हादसे से जुड़े सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

ईरान के कानून मंत्रालय के प्रवक्ता गुलाम हुसैन इस्माइल ने कहा कि इस मामले में व्यापक जांच की गई और हादसे के जिम्मेदार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने ना तो उनकी पहचान बताई है और ना ही पकड़े गए लोगों की संख्या की जानकारी दी है। हालांकि इस घटना के विरोध में तेहरान में प्रदर्शन कर रहे 30 लोगों को भी गिरफ्तार करने की उन्होंने जानकारी दी। ब्रिटिश राजदूत की गिरफ्तारी पर इस्माइल ने कहा कि प्रदर्शन में रोब मकायर को नहीं जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के तहत उनके दायित्व स्पष्ट हैं। उन्होंने देश में होने वाले प्रदर्शनों से ब्रिटिश राजदूत को दूर रहने को कहा है।

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। एपी

उधर, मंगलवार को टीवी पर संबोधन में राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि वैसे तो सभी दुःखों की जड़ अमेरिका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हादसे के मूल कारण पर ध्यान नहीं दें। इस मामले में बटन दबाने वाला व्यक्ति ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके पीछे और लोग भी हैं।' उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में न्यायपालिका को विशेष अदालत का गठन करना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश और दर्जनों विशेषज्ञ शामिल हों। क्योंकि दुनिया इसे देख रही होगी। सरकार ईरानियों और उन देशों के प्रति जवाबदेह है, जिनके नागरिक इस हादसे में मारे गए हैं। बता दें कि पिछले बुधवार को तेहरान से उड़ान भरने के बाद यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के एक विमान को मिसाइल से मार गिराया गया था, जिसमें विमान में सवार 176 यात्री और क्रू के सदस्य मारे गए थे। अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर पश्चिमी देशों के विमान को मार गिराने के आरोपों से ईरान कई दिनों तक इन्कार करता रहा, लेकिन गत शनिवार को उसने स्वीकार कर लिया कि विमान को उसी ने मार गिराया था।

कल लंदन में मिलेंगे प्रभावित देश : यूक्रेन के विदेशमंत्री वादिम प्राइसटाइको ने कहा कि जिन पांच देशों के नागरिक इस विमान हादसे में मारे गए हैं उनकी गुरुवार को एक बैठक होगी। लंदन में होने वाली इस बैठक में तय किया जाएगा कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए कानूनी सहित कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।

कनाडा ने कहा-सुलेमानी पर हमला से पहले अमेरिका ने हमें नहीं बताया: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगर क्षेत्र में तनाव नहीं होता तो हादसे में मारे गए सभी लोग जीवित होते। उन्होंने कहा कि सुलेमानी पर हमला करने से पहले अमेरिका ने हमें विश्वास में नहीं लिया। यह ठीक है कि अमेरिका कार्रवाई को लेकर दृढ़प्रतिज्ञ था, लेकिन बड़े मुद्दों पर हम एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के तौर पर काम करते हैं। हालांकि कभी-कभी देश अपने सहयोगियों को सूचित किए बिना कार्रवाई करते हैं।

कनाडा के दो जांचकर्ता तेहरान पहुंचे : ईरान ने हादसे की जांच में हिस्सा लेने के लिए कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन और अमेरिका के विशेषज्ञों को बुलाया है। कनाडा के दो जांचकर्ता तो सोमवार को तेहरान पहुंच भी गए। आने वाले दिनों में दो और जांचकर्ताओं के आने के उम्मीद है।

सुल्तान के निधन से भारत को अपूरणीय क्षति : जयशंकर

- नकवी ने नए सुल्तान से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद के निधन से भारत को एक सच्चे दोस्त और शुभचिंतक के रूप में एक अपूरणीय क्षति हुई है। खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय तक शासन करने वालों में से एक और नई दिल्ली के करीबी मित्र का 79 वर्ष की आयु में 10 जनवरी को निधन हो गया। मस्कट गए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को ओमान के नए सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सैद से मुलाकात कर पूर्व सुल्तान काबूस के निधन पर संवेदना प्रकट की। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा, 'ओमान दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। भारत को एक सच्चे मित्र एवं शुभचिंतक के रूप में अपूरणनीय क्षति हुई है।'

काबूस 1970 में ओमान की सत्ता पर आसीन हुए थे और उन्होंने देश को तीव्र वृद्धि एवं विकास के पथ पर ले जाने का नेतृत्व किया था। खाड़ी क्षेत्र की अपनी दूरदृष्टि के लिए वैश्विक स्तर पर उन्हें काफी सम्मान मिला।

नकवी ने नए सुल्तान को मोदी का निजी पत्र सौंपा : भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ओमान के नए सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सैद से मुलाकात कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता की ओर से पूर्व सुल्तान काबूस के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने ओमान के सुल्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निजी पत्र सौंपा।

मस्कट में मंगलवार को ओमान के नए सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सैद (दाएं) से मुलाकात कर सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद के निधन पर संवेदना प्रकट करते केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रेट्र

संघर्ष विराम स्वीकार किए बिना तालिबान से वार्ता नहीं

- अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता की आतंकी संगठन को दो टूक
- बातचीत के दौरान भी आतंकवादियों ने मारे थे कई अमेरिकी सैनिक

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी प्रकार की शांति वार्ता से पहले तालिबान को संघर्ष विराम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी संगठन ऐसा नहीं करता है तो अफगान सरकार से वार्ता नहीं होगी।

राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता सादिक सीद्दिकी ने कहा कि तालिबान के संघर्ष विराम किए बिना ना तो लंबे समय तक क्षेत्र में शांति रह सकती है और ना ही हिंसा में किसी भी प्रकार की कमी आएगी। इस बीच एक सूत्र ने कहा है कि तालिबान ने हिंसा में कमी के लिए एक योजना तैयार की है, लेकिन वह अफगान सरकार के साथ वार्ता से पहले संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं है।

अफगानिस्तान के लिए नाटो के प्रतिनिधि निकोलस काई का कहना है कि वह आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ेगी और उससे अफगान सरकार से आतंकी संगठन की वार्ता का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान शांति प्रक्रिया के पक्ष में एक मजबूत क्षेत्रीय सहमति बनी है और वर्तमान समय में इस क्षेत्र में सुरक्षा बल पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। शांति वार्ता से जुड़े एक अन्य सूत्र ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका के विशेष दूत जाल्मे खलीलजाद पिछले एक सप्ताह से कतर में हैं। इस दौरान उनकी तालिबान के उपनेता अब्दुल गनी बरादर के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, अफगान सरकार के नेताओं के साथ हिंसा को कम करने के वास्ते तालिबान द्वारा तैयार की गई योजना को साझा करने के लिए खलीलजाद जल्द ही काबुल का दौरा करेंगे। बता दें कि अफगानिस्तान के संकट को हल करने के लिए अक्टूबर 2018 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन पिछले साल सितंबर में एक कार बम विस्फोट के बाद यह पटरी से उतर गई थी। सात दिसंबर 2019 को वार्ता फिर शुरू हुई, लेकिन बगराम हमले के बाद यह फिर से रुक गई। अब अफगानिस्तान सरकार ने आतंकी संगठनों को आड़े हाथ लिया है।

सीनेट 21 को शुरू कर सकती है महाभियोग की सुनवाई

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 21 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई शुरू हो सकती है। यह जानकारी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने दी है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने गत 18 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और संसद की कार्यवाही में रोड़ा अटकाने के आरोप तय किए गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले ऊपरी सदन में अब यह तय होना है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे या नहीं।

रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कोर्निन ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि सीनेट 21 जनवरी को महाभियोग पर सुनवाई शुरू कर सकती है। प्रतिनिधि सभा से महाभियोग का प्रस्ताव मिलने के बाद सीनेट को सुनवाई प्रारंभ करने में कुछ दिन का समय लग सकता है। सीनेट में सुनवाई के नियम तय करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।

इस बीच खबर है कि प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी इसी हफ्ते प्रस्ताव सीनेट के पास भेज सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अनुसार, स्पीकर और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता पेलोसी आने वाले दिनों में सीनेट में अपनी पार्टी के ऐसे करीब छह सदस्यों का चयन करेंगी, जो ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए मजबूती से दलील रख सकें।

इस मामले में है महाभियोग : ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने गत वर्ष 25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इसमें उन्होंने जेलेंस्की पर इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन को बदनाम करने के लिए दबाव बनाया था।

वाशिंगटन में महाभियोग संबंधी एक बैठक में हिस्सा लेने जाती प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी (दाएं)। एपी

बगैर सुनवाई आरोप खारिज करने के प्रयास पर रिपब्लिकन में विरोध

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई शुरू होने से पहले ही रिपब्लिकन पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं।

पार्टी के कुछ सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ लगाए आरोपों को बगैर सुनवाई खारिज करने के प्रयास का विरोध किया है। रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी ने कहा, 'मैं आरोपों को खारिज करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करूंगा।'

पहल

वाशिंगटन में गुरुवार से शुरू होने जा रही हैं नि:शुल्क हिंदी कक्षाएं, हिंदी के साथ ही भारत की संस्कृति पर भी समझ बढ़ाने का रहेगा प्रयास

अमेरिका में हिंदी सिखाएगा भारतीय दूतावास

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय दूतावास हिंदी सीखने और भारत की उदार संस्कृति के बारे में समझ बढ़ाने के इच्छुक अमेरिकियों और विदेशी नागरिकों के लिए गुरुवार से निःशुल्क हिंदी कक्षाएं शुरू करने जा रहा है।

भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक बयान में बताया कि दूतावास के भारतीय संस्कृति शिक्षक मोक्षराज 16 जनवरी से निःशुल्क हिंदी की कक्षाएं लेंगे। मोक्षराज ने बताया, 'भारत की वैश्विक साख तेजी से बढ़ रही है। लोग हिंदी भाषा सीखकर भारत के बारे में सही जानकारी हासिल करना चाहते हैं। करोड़ों लोगों में भारत की कला-संस्कृति, परिवार व्यवस्था, वैवाहिक जीवन, हिंदी फिल्म, योग-ध्यान, खानपान, राजनीति और कारोबार के बारे में समझ बढ़ाने के लिए हिंदी सीखने की इच्छा बढ़ रही है। अमेरिका में हिंदी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है।' भारतीय दूतावास पिछले दो वर्ष से विभिन्न देशों के नागरिकों के लिए हिंदी की निःशुल्क कक्षाएं चला रहा है। इसके लिए दूतावास ने जॉर्ज वाशिंगटन और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। मोक्षराज ने बताया कि अमेरिका में कई स्थानों पर हिंदी और संस्कृत के साथ ही गीता के श्लोक भी पढ़ाए जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में बतौर सांस्कृतिक राजनयिक के तौर पर नियुक्त किए गए मोक्षराज अमेरिका के विभिन्न राज्यों में हिंदी, संस्कृत, भारतीय संस्कृति और योग की शिक्षा देते हैं।

भारतीय संगठन भी दे रहे हैं हिंदी को बढ़ावा

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के कई संगठन भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं। ये संगठन कवि सम्मेलन और विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिये हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास। फाइल

हैरी की इच्छा के सामने झुकीं ब्रिटेन की महारानी

सैंड्रिंघम (इंग्लैंड), रायटर : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (93) अपने पौत्र हैरी (35) और उनकी पत्नी मेगन (38) की इच्छा के सामने झुक गई हैं जो ज्यादा स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। इस मसले पर विवाद सुलझाने के लिए सोमवार को ब्रिटिश शाही परिवार की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। ब्रिटिश मीडिया ने इस प्रकरण को 'ब्रेक्जिट' की तर्ज पर 'मेग्जिट' नाम दिया है।

हैरी और उनकी अमेरिकी अभिनेत्री पत्नी मेगन ने पिछले हफ्ते यह घोषणा करके शाही परिवार में संकट पैदा कर दिया था कि वे राजसी कर्तव्यों से हटना चाहते हैं और उत्तरी अमेरिका में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। सोमवार को पूर्वी इंग्लैंड में महारानी के ग्रामीण सैंड्रिंघम इस्टेट में बुलाई गई आपात बैठक में हैरी के पिता और सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और हैरी के बड़े भाई प्रिंस विलियम भी उपस्थित थे। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, शाही परिवार हैरी-मेगन की योजना का समर्थन करता है।

निसान के पूर्व सीईओ कार्लोस गोन ने रेनो पर किया केस

बेरूत, आइएएनएस: कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व सीईओ कार्लोस गोन ने सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों को लेकर फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। फरवरी के अंत में इस मामले पर सुनवाई होगी। गोन 7,70,000 यूरो (छह करोड़ रुपये से अधिक) प्रति वर्ष पेंशन के हकदार हैं। बता दें कि दोनों कंपनी मिलकर काम करती हैं और वह इसके भी सीईओ थे, लेकिन नवंबर 2018 में जापान में गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें पद छोड़ने को विवश किया गया।

जापान से भागकर लेबनान आए गोन ने बेरूत में सोमवार को फ्रेंच मीडिया से जुड़े दो समाचार पत्रों को दिए साक्षात्कार में अपने कदम को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि रेनो के सीईओ के तौर पर औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया था। साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि शुरुआत में मैं विवाद को दोस्ताना तरीके से निपटाना चाहता था। गोन के अनुसार उन्हें अपने स्थान पर एक सीईओ को नियुक्त करना था और इसीलिए उन्होंने 23 जनवरी 2019 को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जिसमें लिखा था कि मैं कर्तव्यों से निवृत्त होना चाहता हूं ताकि कंपनी का कामकाज सुचारु रूप से चल सकें। हालांकि रेनो के प्रबंधन ने इसे मेरे इस्तीफे के तौर पर पेश किया। इसी के बाद कंपनी ने 2018 में मिलने वाले मेरे लाभों को भी कम कर दिया। मेरे पत्र को इस्तीफे के तौर पर पेश किया गया जबकि ऐसा नहीं था।

कार्लोस गोन। फाइल

बराबरी का मुकाबला

ये भी जानिए

वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने के मामले में फिंच- वार्नर की जोड़ी (नौ बार) दूसरे नंबर पर आ अई है। इनसे आगे एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन (16 बार) हैं।

शीर्ष क्रम में छेड़छाड़ पड़ी टीम इंडिया को भारी

ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारतीय टीम को 10 विकेट से रौंदा, दोनों सलामी बल्लेबाज फिंच और वार्नर ने लगाए नाबाद शतक

मुंबई, प्रेट्र : कहते हैं ना अच्छी खासी चल रही चीज के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना पूरी लय बिगड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मंगलवार को भारतीय टीम के साथ, जिसका अपने शीर्ष क्रम से छेड़छाड़ करना उसी पर भारी पड़ गया। वानखड़े स्टेडियम की जिस विकेट पर भारतीय बल्लेबाज रनों के लिए तरसते रहे उसी विकेट पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की सलामी जोड़ी डेविड वार्नर (नाबाद 128) और आरोन फिंच (नाबाद 110) ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी मेजबान टीम को 15 वर्ष बाद वनडे में 10 विकेट से हार के लिए मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। शिखर धवन (74) और लोकेश राहुल (47) को छोड़कर भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने ज्यादा कुछ रन नहीं कर सके और 49.1 ओवरों में 255 रनों पर ढेर हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने आसान सा लक्ष्य 37.4 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया।

यह वनडे इतिहास में तीसरा मौका है जब कोई टीम 250 या उससे ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 विकेट से जीती है। रोचक बात यह है कि हारने वाली तीनों टीमें एशियाई हैं। भारतीय टीम अपने घर में दूसरी बार, जबकि कुल मिलाकर पांचवीं बार वनडे में 10 विकेट से हारी है। मैन ऑफ द मैच चुने गए वार्नर और फिंच की सलामी जोड़ी ने भारत में दूसरी बार पहले विकेट के लिए 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी की है। इससे पहले इन दोनों ने 2017 में बेंगलुरु में 231 रन बनाए थे।

यह भारत के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए अभी तक सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इससे पहले भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी 242 रनों की थी, जो स्टीव स्मिथ और जॉर्ज बैली ने 2016 में पर्थ में बनाई थी। इस स्टेडियम पर भारत पहली बार 10 विकेट से हारा है। इस स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच यह चौथा मैच था जिसमें से तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। वार्नर और फिंच ने भारतीय गेंदबाजी की कलई खोलते हुए बल्लेबाजी को बेहद आसान बना दिया। दो ऐसे मौके आए थे जब भारत को सफलता मिल गई थी, लेकिन रिव्यू में भारत को मायूसी मिली। अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बीच वार्नर ने अपने वनडे करियर का 18वां और फिंच ने 16वां शतक पूरा किया। वार्नर ने 112 गेंदों का सामना कर सात चौके और तीन छक्के मारे। फिंच ने 114 गेंदों का सामना कर 13 चौके और दो छक्के लगाए। इन दोनों के सामने न जसप्रीत बुमराह चले और न ही मुहम्मद शमी। कुलदीप यादव की चाइनामैन और रवींद्र जडेजा की फिरकी भी इन दोनों के सामने बेअसर रही। वहीं डीआरएस लेने के फैसले भी भारतीय टीम के खिलाफ गए। एक मौके पर तो शार्दुल ठाकुर की गेंद पर अंपायर ने वार्नर को आउट भी दे दिया था, लेकिन वार्नर डीआरएस लेकर बच निकले। डीआरएस खत्म हो गए तो कई मौके ऐसे आए जब एलबीडब्ल्यू के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया और उनके पास डीआरएस भी नहीं बचा था।

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन भारतीय टीम को रोहित शर्मा (10) के रूप में पहला झटका जल्द ही लग गया, जब मिशेल स्टार्क (3/56) की गेंद पर डेविड वार्नर ने मिड ऑफ पर उनका कैच लपक लिया। इसके बाद धवन (74) का साथ देने राहुल (47) आए और दोनों ने बिना किसी दिक्कत के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। शुरुआत में संभलकर खेलने वाले धवन ने आगे चलकर अपने शॉट खेलने शुरू किए और उसी वक्त अच्छी गेंदों को सम्मान भी दिया।

धवन ने अपनी क्षमता दिखाते हुए मैदान के चारों ओर शॉट खेले और लेग स्पिनर एडम जांपा (1/53) की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, अर्धशतक के बाद धवन का एश्टन एगर (1/56) की गेंद पर वार्नर ने आसान सा कैच टपका दिया। धवन और राहुल भारतीय पारी को आसानी के साथ आगे चला रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद अपने अर्धशतक से तीन रन दूर राहुल ने एगर की गेंद पर स्टीव स्मिथ को कैच थमा दिया और धवन भी कुछ देर बाद पैट कमिंस (2/44) की गेंद पर एगर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। राहुल ने जहां अपनी पारी में चार चौके लगाए, तो वहीं धवन ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया।

राहुल व धवन के अंतिम-11 में रहने की वजह से कप्तान विराट कोहली (16) ने खुद को नंबर चार स्थान पर उतारा, लेकिन वह अपने खेल को लंबा नहीं ले जा सके और जांपा की गेंद पर उन्हीं को कैच थमाकर चले गए। श्रेयस अय्यर (04) भी अपने घरेलू मैदान पर कुछ खास नहीं कर सके और स्टार्क की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट के पीछे खड़े एलेक्स कैरी के दस्तानों में समा गई। रिषभ पंत (28) और रवींद्र जडेजा (25) ने छठे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी करके भारतीय पारी को थोड़ा संभाला, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम वापसी नहीं कर सकी। अंत में कुलदीप यादव (17) और मुहम्मद शमी (10) ने टीम को 250 रनों के पार पहुंचाया।

भारत के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मैच के दौरान रन के लिए दौड़ते ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आरोन फिंच (बायें) और डेविड वार्नर ● एएफपी

धवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन पूरे

मुंबई : भारतीय ओपनर शिखर धवन ने मंगलवार को एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली और वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए। बायें हाथ के बल्लेबाज धवन इस टीम के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरे करने वाले कुल मिलाकर 32वें खिलाड़ी बने। भारतीयों में दिग्गज सचिन तेंदुलकर (3077 रन), महेंद्र सिंह धौनी (1660), विराट कोहली (1727) और रोहित शर्मा (2047) यह उपबल्धि अपने नाम कर चुके हैं। 34 वर्षीय धवन ने यह मुकाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25वीं पारी के दौरान हासिल किया। धवन ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार शतक जड़े हैं।

स्कोर बोर्ड

टॉस : ऑस्ट्रेलिया (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : डेविड वार्नर

भारत — 255 (49.1 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. वार्नर बो. स्टार्क	10	15	02	00
शिखर धवन का. एगर बो. कमिंस	74	91	09	01
लोकेश राहुल का. स्मिथ बो. एगर	47	61	04	00
विराट कोहली का. एवं बो. जांपा	16	14	00	01
श्रेयस अय्यर का. कैरी बो. स्टार्क	04	09	00	00
रिषभ पंत का. टर्नर बो. कमिंस	28	33	02	01
रवींद्र जडेजा का. कैरी बो. रिचर्डसन	25	32	02	01
शार्दुल ठाकुर बो. स्टार्क	13	10	02	00
मुहम्मद शमी का. कैरी बो. रिचर्डसन	10	15	01	00
कुलदीप यादव रन आउट	17	15	02	00
जसप्रीत बुमराह नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-3, वा-8) 11

कुल : 49.1 ओवर में 255 रनों पर सभी आउट

विकेट पतन : 1-13 (रोहित, 4.3), 2-134 (राहुल, 27.1), 3-140 (धवन, 28.5), 4-156 (कोहली, 31.2), 5-164 (अय्यर, 32.5), 6-213 (जडेजा, 42.1), 7-217 (पंत, 43.2), 8-229 (शार्दुल, 44.5), 9-255 (कुलदीप, 48.6)

गेंदबाजी

मिशेल स्टार्क 10-0-56-3

पैट कमिंस 10-1-44-2

केन रिचर्डसन 9.1-0-43-2

एडम जांपा 10-0-53-1

एश्टन एगर 10-1-56-1

ऑस्ट्रेलिया — 258/0 (37.4 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
डेविड वार्नर नाबाद	128	112	17	03
आरोन फिंच नाबाद	110	114	13	02

अतिरिक्त : 20 (बा-4, लेबा-7, वा-9)

कुल : 37.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 258 रन

गेंदबाजी : शमी 7.4-0-58-0

जसप्रीत बुमराह 7-0-50-0

शार्दुल ठाकुर 5-0-43-0

कुलदीप यादव 10-0-55-0

रवींद्र जडेजा 8-0-41-0

परिणाम : ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

रन	जोड़ी	बनाम	जगह	वर्ष
284	मैथ्यू हेड-वार्नर	पाकिस्तान	एडिलेड	2017
260	स्मिथ-डेविड वार्नर	अफगानिस्तान	पर्थ	2015
258*	वार्नर-आरोन फिंच	भारत	मुंबई	2020

बिना कोई विकेट गंवाए सबसे बड़ा लक्ष्य पाने वाली टीम

लक्ष्य	टीम	बनाम	जगह	वर्ष
279	द. अफ्रीका	बांग्लादेश	किंबरले	2017
256	ऑस्ट्रेलिया	भारत	मुंबई	2020
255	इंग्लैंड	श्रीलंका	एजबेस्टन	2016

किसी एक टीम के खिलाफ जोड़ी के सबसे ज्यादा रन

रन	पारी	जोड़ी	देश	बनाम
1407	22	गॉर्डन ग्रीनिज-डेसमंड हेंस	वेस्टइंडीज	भारत
1286	23	शिखर धवन-रोहित शर्मा	भारत	ऑस्ट्रेलिया
1244	21	डेविड बून-रॉड मार्श	ऑस्ट्रेलिया	भारत
1182	20	सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली	भारत	द. अफ्रीका
1152	29	गॉर्डन ग्रीनिज-डेसमंड हेंस	वेस्टइंडीज	ऑस्ट्रेलिया

भारत की वनडे में 10 विकेट से हार

बनाम	जगह	वर्ष
न्यूजीलैंड	मेलबर्न	1981
वेस्टइंडीज	ब्रिजटाउन	1997
दक्षिण अफ्रीका	शारजाह	2000
दक्षिण अफ्रीका	कोलकाता	2005
ऑस्ट्रेलिया	मुंबई	2020

02 ओपनरों (फिंच और वार्नर) ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली बार भारत के खिलाफ शतक लगाए हैं

04 नंबर पर पिछली सात पारियों में विराट कोहली 09, 04, नावाद 03, 11, 12, 07 और 16 रन बना पाए हैं

18 वां शतक ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में डेविड वार्नर ने लगाया। उन्होंने इस मामले में मार्क वॉ की बराबरी की। उनसे आगे अब सिर्फ 29 शतक लगाने वाले रिकी पोंटिंग हैं

2010 में विशाखापत्तनम में भारत के खिलाफ मिशेल स्टार्क ने वनडे में पदार्पण किया था। खास बात यह है मुंबई में स्टार्क ने भारत में अपने करियर का मात्र दूसरा वनडे खेला

5000 रन सबसे तेज वनडे में पूरा करने के मामले में डेविड वार्नर (115) ने जो रूट (116) को पछाड़ दिया। सबसे तेज 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड हाशिम अमला (101) के नाम है

स्टेडियम में सीएए के समर्थन और विरोध में लगे नारे

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच के दौरान मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कुछ लोगों ने नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच वहां मौजूद भीड़ ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। हजारों की संख्या में लोग मोदी-मोदी चिलाने लगे। सुरक्षाकर्मी तुरंत स्थिति को संभालने उनके पास पहुंचे और उन्हें नारे नहीं लगाने या मैदान के बाहर जाने के लिए कहा। सीएए के खिलाफ नारे लगा रहे इन लोगों के कपड़ों पर नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर लिखा हुआ था। जब इन्होंने नारेबाजी करनी शुरू की तो उसके कुछ ही देर में वहां मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले कुछ लोगों ने दावा किया था कि आयोजन स्थल पर सीएए के खिलाफ विरोध को रोकने के लिए काले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि इन खबरों पर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने कहा कि इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस विरोध की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गईं। हालांकि स्टेडियम में बैनर लाने के लिए जरूर प्रतिबंध लगा था। एमसीए के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम में बैनर लाने पर प्रतिबंध लगाया था।

पंत के सिर में चोट, नहीं की विकेटकीपिंग

मुंबई : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां पहले वनडे मैच में बल्लेबाजी करते वक्त भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत के सिर में चोट लग गई। इसके चलते वह ऑस्ट्रेलियाई पारी में विकेटकीपिंग के लिए नहीं उतरे। पंत की चोट को लेकर बीसीसीआइ ने ट्विटर पर लिखा कि रिषभ पंत के हेलमेट पर बल्लेबाजी करते समय गेंद लगी, जिससे परेशानी हो रही थी। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल ने विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाला। पंत अभी निगरानी में हैं।

एक नजर में

रानी न्यूजीलैंड दौरे पर होंगी महिला हॉकी टीम की कप्तान

नई दिल्ली : स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल 25 जनवरी से ऑकलैंड से शुरू हो रहे भारतीय महिला हॉकी टीम के न्यूजीलैंड दौरे पर 20 सदस्यीय टीम की अगुआई करेंगी। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को टीम की घोषणा की। गोलकीपर सविता भारतीय टीम की उप कप्तान होंगी। भारत को दौरे पर पहला मैच 25 जनवरी को न्यूजीलैंड की युवा टीम से खेलना है। इसके बाद 27 और 29 जनवरी को न्यूजीलैंड की टीम से मुकाबले होंगे। भारतीय टीम चार फरवरी को ब्रिटेन से भी खेलेगी। वहीं, दौरे का आखिरी मैच पांच फरवरी को न्यूजीलैंड से खेलना है। **टीम :** रानी रामपाल (कप्तान), सविता, रजनी ई, दीप ग्रेस इक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर, सलीमा टेटे, सुशीला चानू, निशा, नमिता टोप्पो, उदिता, मोनिका, लिलिमा मिंज, नेहा, सोनिका, शर्मिला देवी, नवनीत कौर, लालरेम्सियामी, वंदना कटारिया, नवजोत कौर। (प्रेट्र)

आनंद ने गिरी से खेला ड्रॉ

विज्क आन जी (नीदरलैंड्स) : भारतीय दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने मंगलवार को यहां नीदरलैंड्स के अनीश गिरी के साथ अंक बांटकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में तीन बाजियों में अपना दूसरा ड्रॉ खेला। सफेद मोहरों से खेल रहे आनंद ने नौवीं चाल से ही हावी होना शुरू कर दिया और 12वीं चाल तक वह बेहतर स्थिति में पहुंच गए। गिरी को 21वीं चाल में लगा कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने ड्रॉ की पेशकश कर दी जिसे आनंद ने स्वीकार कर दिया। (प्रेट्र)

डोपिंग मुक्त खेल पर जोर

गुवाहाटी : खेल मंत्री किरन रिजिजू और नाडा के एंबेसडर अभिनेता सुनील शेट्टी ने साफ सुथरी व डोपिंग मुक्त खेल संस्कृति पर जोर देते हुए भारतीय खिलाड़ियों से प्रतिबंधित पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। युवाओं को डोपिंग के खतरों को लेकर जागरूक करने संबंधी कार्यशाला में शेट्टी ने बच्चों की जिंदगी में खेलों के महत्व का जिक्र किया। रिजिजू और शेट्टी ने एक फुटबॉल मैच के बाद शूटआउट में भी भाग लिया। रिजिजू ने कहा, 'मैं सभी कोचों और अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थों से दूर रहें। हम उनका हर कदम पर साथ देंगे।' (प्रेट्र)

'गोपीचंद अकादमी छोड़ने का फैसला साइना का था'

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी (पीपीबीए) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि रियो ओलंपिक से पहले हैदराबाद में गोपीचंद अकादमी छोड़कर बेंगलुरु में विमल कुमार के मार्गदर्शन में अभ्यास करने का फैसला साइना नेहवाल का अपना था और अकादमी की इसमें कोई भूमिका नहीं रही।

गोपीचंद ने आगामी किताब 'ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन : इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स' के 'बिटर राइवलरी' शीर्षक के एक अध्याय में लिखा है कि 2014 विश्व चैंपियनशिप के बाद विमल कुमार के मार्गदर्शन में बेंगलुरु स्थित पादुकोण अकादमी में अभ्यास के साइना के फैसले से वह काफी दुखी हुए। गोपीचंद ने यह भी कहा कि उन्हें बुरा लगा कि पादुकोण, विमल और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के अधिकारी वीरेन रसकिन्हा ने साइना को हैदराबाद छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पादुकोण अकादमी ने एक बयान में कहा, 'बेंगलुरु में पीपीबीए पर अभ्यास करने के साइना के फैसले में पीपीबीए का कोई हाथ नहीं है। विमल कुमार ने साइना को खराब फॉर्म से निकलकर दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीते।'

किताब में गोपीचंद ने यह भी लिखा है कि उन्हें हैरानी है कि पादुकोण ने कभी उनके बारे में कुछ सकारात्मक नहीं कहा। इस पर पीपीबीए ने लिखा, 'पीपीबीए एक खिलाड़ी और कोच के रूप में भारतीय बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद के योगदान का सम्मान करती है। हमने विश्व स्तर पर उनके खिलाड़ियों की सफलता की सराहना की है और हमेशा उनके साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं।' गोपीचंद ने खुद पादुकोण के मार्गदर्शन में अभ्यास किया और 2001 में ऑल इंग्लैंड जीतने के बाद कोच गांगुली प्रसाद के साथ जुड़े। पादुकोण अकादमी ने कहा, 'पीपीबीए पिछले 25 साल से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही है। हमारे कई खिलाड़ी अपने करियर के अलग-अलग चरण पर अकादमी छोड़कर गए हैं। हम कभी उनकी प्रगति में बाधा नहीं बने और यही अकादमी की नीति रहेगी।'

एक विकेट से हारी हरियाणा की टीम

रणजी ट्रॉफी

जागरण संवाददाता, रोहतक : ओडिशा ने लाहली में खेल गए रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-सी के रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को एक विकेट से हराकर छह अंक हासिल किए। ओडिशा को चौथी पारी में जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य मिला था। टीम ने मैच के चौथे दिन 58.1 ओवर में नौ विकेट पर 182 रन बनाकर एक विकेट से जीत हासिल की। दिन का खेल शुरू हुआ था तब हरियाणा को जीत के लिए तीन विकेट की जरूरत थी, जबकि मेहमान टीम को 32 रन चाहिए थे।

ओडिशा ने सात विकेट पर 147 रन से आगे खेलना शुरू किया और सोमवार के नाबाद बल्लेबाज राजेश धूपर (32) और राजेश मोहंती (21) ने स्कोर ने आठवें विकेट के लिए 29 रन जोड़कर स्कोर को 165 रन तक पहुंचाया। राजेश मोहंती नौवें बल्लेबाज के रूप में जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 176 रन था। हरियाणा के मध्यम गति के गेंदबाज अजीत चहल ने दूसरी पारी में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 80 रन देकर सात विकेट लिए।

पहली पारी में छह और दूसरी पारी में पांच विकेट लेने वाले हरियाणा के मध्यम गति के गेंदबाज सूर्यकांत प्रधान मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने पहली बार मैच में 10 से अधिक विकेट लेने का कारनामा किया। इससे पहले हरियाणा की पहली पारी 90 रन पर सिमट गई थी, जबकि टीम ने दूसरी पारी में 248 रन बनाए। हरियाणा ने पहली पारी में 160 रन बनाए थे।

उप्र के खिलाफ बड़ौदा ने ड्रॉ कराया मैच

जागरण संवाददाता, कानपुर : फॉलोऑन के खतरे से जूझ रही बड़ौदा की टीम के लिए मंगलवार का दिन थोड़ी राहत भरा रहा। ग्रीनपार्क में खेले गए रणजी मुकाबले में बड़ौदा ने उत्तर प्रदेश (उप्र) की टीम से जूझते हुए मैच ड्रॉ करा लिया। हालांकि, उप्र की टीम के लिए फायदेमंद यह रहा कि टीम ने इस मुकाबले में तीन अहम अंक हासिल किए, जबकि बड़ौदा को एक अंक पर संतोष करना पड़ा। मैच में उप्र की ओर से शतक लगाने वाले मुहम्मद सैफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के अंतिम दिन खेलने उतरी बड़ौदा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। 179 रन पर आठ विकेट गंवाने के बाद अंतिम दिन पहले सत्र वीएस भोसले व भार्गव भट्ट ने संभलकर खेलना शुरू किया। बड़ौदा का नौवां विकेट वीएस भोसले के रूप में 226 के योग पर गिरा। भोसले 136 गेंदों पर 39 रन बनाकर सौरभ की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद दूसरी छोर पर खेल रहे भार्गव (20) पर रिंकू की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। बड़ौदा को फॉलोऑन से बचने के लिए 282 रन तक पहुंचना था परंतु पूरी टीम 230 रनों पर ही सिमट गई।

उत्तराखंड-त्रिपुरा मैच ड्रॉ : उत्तराखंड की टीम त्रिपुरा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच ड्रॉ करने में सफल रही। पहली पारी में उत्तराखंड को 90 रन पर आउट करने के बाद त्रिपुरा ने पांच विकेट पर 279 रन बनाकर पारी घोषित की। उत्तराखंड ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में 21 रन पर एक विकेट से की और मैच ड्रॉ घोषित होने तक टीम ने आठ विकेट पर 148 रन बना लिए थे। विजय जेठी 81 रन पर नाबाद रहे।

विश्व कप में आइपीएल की फॉर्म तय करेगी वापसी : एबी

नजरिया

- दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज ने दिए वापसी के संकेत
- बीबीएल के पदार्पण मैच में ब्रिसबेन हीट को दिलाई जीत

सिडनी, एएफपी : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप से पहले टीम में वापसी आइपीएल की फॉर्म पर निर्भर करेगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक वेबसाइट 'क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू' से 35 साल के इस आक्रामक बल्लेबाज ने कहा कि वह संन्यास लेने के दो साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे। डिविलियर्स इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेल रहे है। उन्होंने कहा कि मैं वापसी करना चाहूंगा। मैं मार्क बाउचर (दक्षिण अफ्रीका के कोच), ग्रीम स्मिथ (क्रिकेट निदेशक) और फाफ डुप्लेसिस (कप्तान) से बात कर रहा हूं। हम सब चाहते हैं कि वापसी हो।

उन्होंने कहा कि अभी काफी समय बचा है और काफी कुछ हो सकता है। आइपीएल भी होना है। मुझे उस समय फॉर्म में रहना होगा। इसलिए मैं अपना नाम संभावित खिलाड़ियों में शामिल करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो।

आइपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) की ओर से खेलने वाले डिविलियर्स ने बीबीएल में शानदार पदार्पण किया। ब्रिसबेन हीट की ओर से खेलते हुए डिविलियर्स ने 32 गेंदों पर 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। 11 रनों पर दो विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डिविलियर्स आउट होने तक टीम की जीत सुनिश्चित कर चुके थे। ब्रिसबेन हीट ने एडिलेड स्ट्राइकर्स द्वारा मिले 111 रन के लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। डिविलियर्स 360 डिग्री के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वह हर दिशा में शॉट लगा सकते हैं। आइपीएल के पिछले सत्र में डिविलियर्स का प्रदर्शन खास नहीं रहा।

चार स्वर्ण जीतकर शीर्ष पर पहुंचा महाराष्ट्र

गुवाहाटी, प्रेट्र : महाराष्ट्र खेलो यूथ गेम्स के पांचवें दिन मंगलवार को यहां चार स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में फिर से शीर्ष पर पहुंच गया। सोमवार को 12 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन करने वाला हरियाणा अब 18 स्वर्ण और कुल 54 पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र ने अब तक 21 स्वर्ण सहित 89 पदक जीते हैं। इस सूची में दिल्ली तीसरे स्थान पर है जिसके नाम 15 स्वर्ण के साथ कुल 41 पदक है।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया चार स्वर्ण पदक जीते। इससे उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में तमिलनाडु और गुजरात को पछाड़ दिया और चौथे स्थान पर आ गया। उत्तर प्रदेश के विजय कश्यप (200 मीटर), उत्तम यादव (1500 मीटर) और मुहम्मद शाहबान (हैमर थ्रो) ने लड़कों के अंडर-17 में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीते, जबकि इसी आयु वर्ग के जिम्नास्टिक्स के पैरेलल बार्स में गौरव कुमार ने स्वर्ण जीता। टेबल टेनिस के चार वर्गों में चार अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ियों ने बाजी मारी।

टेनिस डायरी — भारतीय खिलाड़ी होबार्ट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं, मिर्जा मां बनने की वजह से दो साल तक टेनिस से दूर रही थीं

दो साल बाद जीत के साथ सानिया की कोर्ट पर वापसी

होबार्ट, प्रेट्र : भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने डब्ल्यूटीए सर्किट पर जीत के साथ वापसी करते हुए होबार्ट अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में यूक्रेन की नादिया किचेनोक के साथ महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दो साल बाद कोर्ट पर लौटीं सानिया और यूक्रेन की नादिया किचेनोक ने जॉर्जिया की ओकसाना कलाशनिकोवा और जापान की मियू कातो को एक घंटे 41 मिनट तक चले मुकाबले में 2-6, 7-6, 10-3 से हराया। अब उनका सामना अमेरिका की वानिया किंग और क्रिस्टीना मैकहेल से होगा।

अमेरिकी जोड़ी ने चौथी वरीयता प्राप्त स्पेन की जॉर्जिना गार्सिया पेरेज और सारा सौरिबेज तोरमो को 6-2, 7-5 से मात दी। सानिया और किचेनोक की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने दो बार डबल फॉल्ट किए। इसके साथ ही सात ब्रेक प्वाइंट में से एक भी नहीं भुना सकीं। इसकी वजह से पहला सेट गंवा दिया। दूसरे सेट में हालांकि दोनों ने अच्छी वापसी की। दोनों टीमों ने तीन-तीन ब्रेक प्वाइंट भुनाए। कड़े मुकाबले के बीच यह सेट जीतकर सानिया और किचेनोक ने मैच टाई ब्रेकर तक खिंचा। टाई ब्रेकर में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सानिया ने जीत दर्ज की।

भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मां बनने की वजह से दो साल तक टेनिस से दूर रही थीं। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह करने वाली सानिया ने 2018 में इजहान को जन्म दिया था। सानिया ने अक्टूबर 2017 में पिछला टूर्नामेंट खेला था। भारतीय टेनिस को नई बुलंदियों तक ले जाने वाली सानिया डबल्स में नंबर एक रह चुकी हैं और छह बार की ग्रैंडस्लैम विजेता भी हैं। उन्होंने 2013 में सिंगल्स टेनिस खेलना छोड़ दिया था। वह 2007 में डब्ल्यूटीए सिंगल्स रैंकिंग में 27वें स्थान तक पहुंची थीं। अपने करियर में वह लगातार कलाई और घुटने की चोट का सामना करती रही हैं।

मैच खत्म होने के बाद बेटे इजहान से मिलतीं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ● ट्विटर

धुएं का असर ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों पर

मेलबर्न, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से निकले खतरनाक धुएं का असर ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों पर पड़ा जब मंगलवार को एक क्वालीफायर सांस लेने में तकलीफ के कारण रिटायर हो गई, जबकि यूजिनी बुचार्ड को चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। मेलबर्न में हवा की गुणवत्ता का स्तर इस समय बेहद खराब है और नगर प्रशासन ने इसे खतरनाक करार दिया है। इन हालात में साल के पहले ग्रैंडस्लैम के क्वालीफाइंग मुकाबले देर से शुरू हुए। स्लोवेनिया की डालिला जाकुपोविक को स्विट्जरलैंड की स्टेफानी वोएजेले के खिलाफ मैच में बार-बार खांसी आने के बाद पीछे हटना पड़ा। वहीं, बुचार्ड को छाती में तकलीफ के कारण मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा। बाद में उन्होंने तीसरा सेट और मैच जीता। मारिया शारापोवा को भी एक नुमाइशी मैच में बार-बार खांसी के कारण ब्रेक लेना पड़ा।

> यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। लंबे समय बाद मेरे परिवार और बेटे ने मेरा मैच देखा और हम मैच जीत गए। यह मैच जीतकर मुझे अच्छा लग रहा है।
>
> – **सानिया मिर्जा**, टेनिस खिलाड़ी, भारत

प्रजनेश आगे बढ़े, रामकुमार, अंकिता बाहर

मेलबर्न, एएफपी : भारतीय खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालीफायर्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि रामकुमार रामनाथन पहला सेट जीतने के बावजूद मैच हारकर बाहर हो गए। प्रजनेश ने स्थानीय ख

जो खिलाड़ी स्टंप माइक के आसपास स्लेजिंग करते हैं, मेरी नजर में वह खिलाड़ी बेवकूफ हैं।
– माइकल वॉन, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर

बेहतर कल के लिए साहा ने एनसीए को चुना

बेंगलुरू, आइएएनएस : चोट से वापसी के लिए भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अभ्यास कर रहे हैं। साहा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और एनसीए को बेहतर कल के लिए मजबूत बताया। साहा ने अपनी एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेहतर कल के लिए, मैं एनसीए बेंगलुरू में हूं।

वाल्वर्डे को हटा सेतियान बने बार्सिलोना के मैनेजर

फुटबॉल डायरी ▸ रीयल बेटिस के पूर्व मैनेजर क्विकी के नाम पर बनी सहमति, अब नए जोश में दिखेगा क्लब

यूरोपीयन चैंपियनशिप में बार्सा के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था क्लब

मैड्रिड, एएफपी : स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने ईर्नेस्टो वाल्वर्डे को हटाकर उनकी जगह क्विकी सेतियान को अपना नया मैनेजर नियुक्त किया है। इस बात की जानकारी स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना ने दी।

कैंप नाउ में सोमवार को बार्सिलोना की दो घंटे से ज्यादा देर तक चली बोर्ड की बैठक के बाद वाल्वर्डे को हटाए जाने पर फैसला लिया गया। बार्सिलोना ला लीगा की अंक तालिका में शीर्ष पर है, लेकिन वह पिछले पांच मुकाबलों में से केवल एक जीत पाया है, जिससे क्लब संतुष्ट नहीं था। 2003 में लुइस वान गाल के बाद वाल्वर्डे पहले मैनेजर हैं जिन्हें बीच सत्र से ही हटाया गया है। सोमवार देर रात बार्सिलोना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि एफसी बार्सिलोना और ईर्नेस्टो वाल्वर्डे की सहमति के साथ दोनों करार को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। बार्सिलोना और और क्विकी सेतियान के बीच क्लब के पहली टीम के लिए 30 जून 2022 तक के करार पर सहमति बन गई है। क्लब ने आगे लिखा कि सेतियान स्पेनिश फुटबॉल के सबसे अनुभवी मैनेजर में से एक हैं। वह अपने करियर के दौरान गेंद पर कब्जा जमाने और आक्रमक फुटबॉल खेलने के लिए मशहूर रहे हैं, जो दर्शकों को आकर्षित करता है।

सेतियान की चुनौती : सेतियान का बार्सिलोना के मैनेजर के तौर पर पहला मैच आगामी रविवार को होगा जब स्पेनिश चैंपियन ग्रेनाडा से भिड़ेगा। वहीं, बार्सिलोना को अगले महीने यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में नापोली से भिड़ना है, जबकि रीयल मैड्रिड से उसे घरेलू लीग में मार्च में भिड़ना है। इस दौरान सेतियान को अपनी छाप छोड़ने की चुनौती होगी। 61 वर्षीय सेतियान एटलेटिको मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। मैनेजर के तौर पर रीयल बेटिस के साथ सफल कार्यकाल के बाद बार्सिलोना की नजर उन पर थी। 2018 में उनके मार्गदर्शन में बेटिस ने घरेलू लीग में छठा स्थान हासिल किया था और उसी सत्र में कैंप नाउ में उसने बार्सिलोना को 4-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया था।

वाल्वर्डे को यूरोपीय प्रदर्शन ले डूबा : 2017 में जुड़ने के बाद से वाल्वर्डे ने बार्सिलोना को 2018 और 2019 में ला लीगा खिताब दिलाए, लेकिन चैंपियंस लीग में उनकी टीम अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। हाल ही में स्पेनिश सुपर लीग के सेमीफाइनल में बार्सिलोना को एटलेटिको मैड्रिड से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वाल्वर्डे की जगह के लिए बार्सिलोना के पूर्व स्ट्राइकर जाबी और रोनाल्ड कोइमन दौड़ में शामिल थे, लेकिन अंत में सेतियान के नाम पर सहमति बनी।

नए मैनेजर सेतियान (बीच में) के साथ बार्सिलोना क्लब के प्रमुख बार्टोमेउ ((बायें) और फुटबॉल निदेशक एरिक अबिदाल (दायें)। एपी

किंग काजू ने 53 साल की उम्र में बढ़ाया करार

टोक्यो, एएफपी : अगले महीने 53 साल के होने जा रहे जापान के पूर्व स्ट्राइकर काजूयोशी मियूरा ने योकोहामा एफसी के साथ अपने करार को बढ़ाया है, जो उनके सबसे बुजुर्ग पेशेवर फुटबॉलर के रिकॉर्ड को बेहतर करेगा। किंग काजू के नाम से मशहूर काजूयोशी अपने पेशेवर करियर का 35वां सत्र खेलने उतरेंगे। काजूयोशी 2005 में जापानी क्लब योकोहामा से जुड़े थे और उनका मानना है कि वह 60 साल की उम्र से पहले खेलना नहीं छोड़ेंगे। पिछले सत्र में वह अपने क्लब की ओर से तीन मुकाबलों में उतरे, लेकिन कोई गोल नहीं कर पाए। 2017 में काजूयोशी पेशेवर फुटबॉल में गोल करने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बने थे। उसी साल उन्होंने पेशेवर फुटबॉल में खेलने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड बनाया था।

आर्चर पर नस्ली टिप्पणी करने वाले दर्शक पर लगा प्रतिबंध

वेलिंगटन, आइएएनएस : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान नस्ली टिप्पणी करने वाले दर्शक पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद दर्शक को अब दो साल तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैच देखने के लिए स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। आर्चर ने पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन दावा किया था कि मैदान में एक दर्शक ने उन पर नस्ली टिप्पणी की।

आर्चर ने मैच समाप्त होने के बाद ट्विटर पर लिखा था कि अपनी टीम को बचाते समय नस्ली टिप्पणी सुनने से आज मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने आगे लिखा था कि इस सप्ताह उस एक आदमी को छोड़कर दर्शकों की संख्या अद्भुत थी। बार्मी आर्मी (इंग्लैंड के दर्शक) हमेशा की तरह यहां भी शानदार थी।

न्यूजीलैंड ने बे ओवल मैदान पर खेले गए इस पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को पारी और 65 रनों से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने कहा कि जांच के बाद पुलिस ने ऑकलैंड के 28 वर्षीय दर्शक से इस बारें में बात की थी और उन्हें इस अपशब्द भाषा के लिए मौखिक चेतावनी भी दी गई थी। एनजेडसी के प्रवक्ता एंथनी क्रूमी ने कहा कि जिस दर्शक पर प्रतिबंध लगाया गया है अगर वह दोबारा से इन नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर पुलिस उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी।

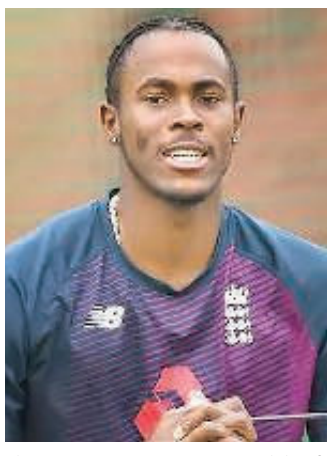

जोफ्रा आर्चर। फाइल फोटो, एपी

फिर से बच्चा जैसा महसूस कर रहा हूं : ड्वेन ब्रावो

पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेट्र : लगभग तीन साल बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी करने वाले 36 वर्षीय ड्वेन ब्रावो ने कहा कि वह बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं। ब्रावो की 2014 में बोर्ड के तत्कालीन पदाधिकारियों के साथ विवाद हो गया था जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इस आलराउंडर ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच सितंबर 2016 में खेला था।

ब्रावो ने त्रिनिदाद के रेडियो '1955 एफएम' से कहा कि यह शानदार अहसास है। मैं फिर से बच्चे जैसा महसूस करने लगा जब मुझे वेस्टइंडीज चयनसमिति के अध्यक्ष रोजर हार्पर ने फोन किया और कहा कि टीम में और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर स्वागत है। आयरलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की टी-20 टीम में वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व बदलने के बाद यह बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं इस क्षेत्र का फिर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने पर खुश हूं और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हूं। ब्रावो ने अक्टूबर 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी लेकिन वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते रहे। दिसंबर 2019 में उन्होंने संन्यास से वापसी की और इस साल होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले खुद को चयन के लिए उपलब्ध रखा।

ड्वेन ब्रावो। फाइल फोटो, एएफपी

नहीं रहे दिग्गज शतरंज प्रबंधक कोया

कोझिकोड (केरल), प्रेट्र: अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) के पूर्व उपाध्यक्ष पीटी उम्मेर कोया का मंगलवार को यहां केरल के कोझिकोड में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पीटी उम्मेर कोया 69 साल के थे। उनके मृत्यु की जानकारी मंगलवार को परिवार के सूत्रों ने दी। कोया 1996 से 2006 तक फिडे के उपाध्यक्ष थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं।

केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कोया के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके निधन से भारतीय शतरंज महासंघ को बड़ा नुकसान हुआ है। फिडे और एआइएफसी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोया की उपलब्धियां बहुत हैं, जिनको गिनाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हैं। उनके निधन से प्रदेश को भारी हानि हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मुश्किल परिस्थितियों में हम उनके परिवार की पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। कोया ने शतरंज और केरल प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है।

एमसीसी ने भी की पांच दिवसीय टेस्ट की वकालत

क्रिकेट डायरी

लंदन, प्रेट्र : क्रिकेट के नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने मंगलवार को कहा कि टेस्ट पांच दिन के ही होने चाहिए, हालांकि उसे आइसीसी के लंबे प्रारूप को चार दिवसीय करने के प्रस्ताव में कुछ फायदे भी नजर आते हैं। एमसीसी ने कहा कि क्रिकेट समिति और एमसीसी की विश्व क्रिकेट समिति ने हाल में इस मसले पर चर्चा की और उन्हें हालांकि चार दिवसीय क्रिकेट से कुछ फायदे नजर आते हैं, लेकिन दोनों समितियों का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट पांच दिन तक ही खेला जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) मार्च में अपनी क्रिकेट समिति की बैठक में चार दिवसीय टेस्ट मैच के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

श्रीलंका ने जिंबाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की

कोलंबो, एएफपी : श्रीलंका ने जिंबाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम घोषित की। जिंबाब्वे की आइसीसी का निलंबन हटाए जाने के बाद यह पहली सीरीज होगी। दोनों टेस्ट मैच में हरारे में खेले जाएंगे। पहला मैच रविवार से, जबकि दूसरा मैच 27 जरवरी से शुरू होगा। जिंबाब्वे ने अपना पिछला टेस्ट मैच नवंबर 2018 में खेला था।

जिंबाब्वे के खिलाफ श्रीलंकाई टेस्ट टीम : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), ओशादा फर्नांडो, कुशल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, लाहिरु थिरिमाने, धनंजय डिसिल्वा, निरोशन डिकवेला, दिलरुवान परेरा, लसित एंबुलडनिया, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, कासुन रजिता, लक्षण संदाकन और सुरंगा लकमल।

मुर्तजा ने खुद को बीसीबी के केंद्रीय अनुबंध से बाहर रखा

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश के वनडे कप्तान मशरफे मुर्तजा ने राष्ट्रीय टीम के साथ अपने अनुबंध को खत्म कर दिया है। इससे अब उनके संन्यास लेने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुर्तजा ने सोमवार को कहा कि कल तक मैं केंद्रीय अनुबंध का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष नजमुल हसन ने पत्रकारों से कहा कि मशरफे अब अनुबंधित खिलाड़ियों के रूप में अपना अनुबंध आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश के लिए 217 वनडे मैच खेलने वाले मुर्तजा ने हालांकि कहा है कि वह लंबे समय तक खेलना जारी रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बीसीबी क्रिकेटरों का माता-पिता है। मुझे बड़ी पार्टी देने के लिए मै बीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। 36 साल के मुर्तजा ने बांग्लादेश के लिए 36 टेस्ट और 54 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं।

पीसीबी के मुख्य वित्त अधिकारी का इस्तीफा

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुख्य वित्त अधिकारी बदर एम खान ने आठ साल इस पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। बदर इस महीने के अंत में अपना पद छोड़ देंगे। पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज के माध्यम से इस बात की जानकारी दी।

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पीसीबी से सीनियर अधिकारियों का इस्तीफा देने का क्रम लगातार जारी है और बदर का इस्तीफा इसी का एक हिस्सा है। इससे पहले, पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुभान अहमद, मार्केटिंग हेड नैला भट्टी और सीनियर जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) शोएब शेख इस्तीफा दे चुके हैं। पीसीबी ने कहा है कि वह जल्द ही बदर के उत्तराधिकारी की खोज शुरू करेगा।

विविध

नगालैंड में एनएससीएन (आइएम) के ठिकानों पर एनआइए के छापे

नई दिल्ली, प्रेट्र : एनआइए ने नगालैंड में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की है। यह कदम नगा उग्रवादी संगठन एनएससीएन (आइएम) से संबंधित आतंकी चंदा मामले में उठाया गया है। मंगलवार को राजधानी इंफाल और दीमापुर में मामले की मुख्य आरोपित अलेम्ला जमीर के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे मारे गए। अलेम्ला जमीर एनएससीएन (आइएम) की संचालन समिति के सदस्य पुंगतिन शिरमरांग उर्फ जेम्स जमीर की पत्नी और इसी संगठन के महासचिव मुइवाह की रिश्तेदार भी है। एनआइए के मुताबिक पुंगतिन फरार है।

एनआइए के प्रवक्ता ने कहा, '82.6 लाख रुपये नकद, तीन करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज, अपराध का सुराग देने वाली डायरी, फोटोग्राफ, डिजीटल डिवाइस, 15 स्मार्ट फोन, एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और चार लैपटाप बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान उग्रवाद और फिरौती से संबंधित सामग्री के साथ ही अपराध का संकेत देने वाले अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।'

डेथ-वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा दोषी मुकेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी मुकेश ने पटियाला हाउस की एक अदालत द्वारा जारी डेथ-वारंट को रद करने की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मुकेश ने उपराज्यपाल एवं राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लंबित होने का हवाला देकर डेथ-वारंट रद करने की मांग की है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद मुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को दया याचिका भेजी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ-वारंट के खिलाफ याचिका दायर की। दिल्ली सरकार अब दया याचिका पर फैसला कर इसे उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेगी।

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश ने डेथ-वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संविधान के तहत उसकी दया याचिका का संवैधानिक अधिकार निष्फल रह जाएगा। उसने यह भी कहा कि फांसी की सजा दिए जाने से 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाना चाहिए अगर दया याचिका खारिज हो जाती है। याचिका में शत्रुघन चौहान बनाम भारत सरकार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। याचिका में कहा गया कि सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया था कि दया याचिका खारिज होने और सजा की तारीख तय होने की सूचना के बीच 14 दिन का नोटिस होना चाहिए, ताकि दोषी कानूनी राहत ले सके। दोषी मुकेश ने कहा कि वह किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा है और न ही उसे सुनाई गई फांसी की सजा पर सवाल उठा रहा है।

जेल में गलत आचरण पर भी कई बार दंडित किए जा चुके हैं निर्भया के गुनहगार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जैसे-जैसे निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की तिथि नजदीक आ रही है, जेल प्रशासन इनके रिकॉर्ड को खंगाल रहा है ताकि इनकी एक अंतिम फाइल तैयार की जा सके। सूत्रों की मानें तो चारों दोषियों द्वारा किए गए गलत आचरण पर समय-समय पर नियमों के अनुसार दोषियों को दंडित किया जाता रहा है। इनमें सबसे कम अक्षय को एक बार, मुकेश को तीन बार, पवन को आठ बार और सबसे अधिक विनय को 11 बार जेल प्रशासन गलत आचरण पर दंड दे चुका है। जेल सूत्रों का कहना है कि दोषियों में मुकेश ऐसा है जिसने जेल में कोई काम नहीं किया है। अक्षय, पवन और विनय ने जेल में समय-समय पर कार्य किए। इस एवज में इन्हें जेल प्रशासन की ओर से मेहनताना भी दिया गया।

सूत्रों का कहना है कि अक्षय ने करीब 69 हजार रुपये बतौर मेहनताना कमाए। वहीं पवन ने 29 हजार तो विनय ने करीब 39 हजार रुपये कमाए। कैदियों की कमाई को जिस खाते में रखा जाता है, उसे कैदी कल्याण खाता कहा जाता है। इस खाते में जमा रुपयों का दोषी क्या करेंगे, इस बाबत इन्होंने जेल प्रशासन से अभी तक कुछ नहीं कहा है। जेल सूत्रों का कहना है कि ये जिस व्यक्ति के खाते में रुपये जमा करने को कहेंगे, उसके खाते में उतने पैसे डाल दिए जाएंगे। ये चाहें तो ये पैसे खुद भी खर्च कर सकते हैं। यदि इन्होंने कुछ नहीं कहा तो फांसी के बाद इनके पैसे पर परिजनों का हक होगा। जेल सूत्रों का कहना है कि जल्द ही जेल प्रशासन इस बाबत दोषियों से बात करेगा।

पढ़ाई-लिखाई में फिसड्डी

जेल सूत्रों के अनुसार, 2016 में मुकेश, पवन व अक्षय ने ओपन स्कूल में दसवीं कक्षा में दाखिला लिया था। परीक्षा भी दी थी, लेकिन ये उत्तीर्ण नहीं हो सके। इसी तरह विनय ने बीए में दाखिला कराया, लेकिन इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई।

महिला को छह बच्चों सहित जिंदा जलाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, मेरठ

मेरठ के जाहिदपुर में सोमवार रात ढाई बजे दुस्साहसिक वारदात हुई। हमलावरों ने बुटीक संचालिका को छह बच्चों संग जिंदा फूंकने का प्रयास किया। परिवार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग में बुटीक संचालिका और उसके दो बच्चे झुलस गए, जबकि धुएं में दम घुटने से चार बच्चे बेहोश हो गए। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर किया गया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर अज्ञात में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया।

जाहिदपुर निवासी राहमीन ने पुलिस को बताया कि वह घर के बाहरी हिस्से में 12 वर्षीय बेटी यशा व आठ वर्षीय बेटे अनस के साथ सो रही थी। अंदर कमरे में बेटी राहिल, साफिया, शगुफ्ता और बुशरा सो रहे थे। रात ढाई बजे उनके मकान की छत से कुछ लोगों के चलने की आवाज आई। इससे उसकी आंख खुल गई। इसी बीच खिड़की से पाइप के जरिए पेट्रोल अंदर डाला गया। तेल की गंध समझ में ही आई थी कि तभी खिड़की से कोई जलती हुई चीज फेंकी गई। इससे आग लग गई। आग ने चारपाई पर लेटे अनस, यशा और राहमीन को चपेट में ले लिया। बच्चों को बचाते हुए राहमीन चिल्लाई। सभी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी बीच राहिल और साफिया भागकर अपने मामा मुश्ताक के घर पर पहुंचीं। तब तक अनस का चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। राहमीन और यशा भी काफी झुलस गए। दूसरे मामा मुस्तफा के साथ आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे हुए तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां से अनस को दिल्ली रेफर कर दिया। धुएं में दम घुटने से चार बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें मुश्किल से होश में लाया जा सका। इंस्पेक्टर मनीष बिष्ट ने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ महिला के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौके से पेट्रोल डालने वाला पाइप और बोतल कब्जे में ले ली है।

पत्नी को छोड़ प्रेमिका संग रहने लगा था कमरुद्दीन : लिसाड़ीगेट क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी निवासी राहमीन का निकाह 22 वर्ष पहले हापुड़ के मजीरपुर निवासी कमरुद्दीन से हुआ था। राहमीन ने छह बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। आठ वर्ष पहले कमरूद्दीन को एक महिला से प्रेम हो गया। वह उसके साथ चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। राहमीन तब से सात बच्चों को लेकर जाहिद्पुर में शौकीन के मकान में किराए पर रहती हैं।

बुटीक संचालिका और उसके बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। सभी को उपचार दिलाया गया। मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा गया। हमलावर आसपास के ही हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
– अजय साहनी, एसएसपी

राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट से नाखुश

- कहा-वर्तमान रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं
- कोर्ट ने अगली सुनवाई अगले हफ्ते होना तय किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ी साजिश की जांच करने वाली सीबीआइ के नेतृत्व वाली बहुआयामी जांच एजेंसी (एमडीएमए) की ताजा स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा है कि वह जानना चाहती है कि रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जांच में पिछले दो सालों में क्या प्रगति हुई है। लेकिन रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं बताई गई है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते सुनिश्चित की है।

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुनवाई के दौरान दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए जस्टिस एलएन राव और हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि इस रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नई रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा, 'हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले दो साल में जांच कहां तक पहुंची।' कोर्ट ने केंद्र से एक नई रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। यह सुनवाई राजीव गांधी हत्या मामले में 'बेल्ट बम' से संबंधित जांच हो रही थी। दरअसल, पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में बड़ी साजिश पर मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) से ताजा स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी।

पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अपने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के जरिए तुरंत पेश हो और इस पर बहस करे। बता दें कि अदालत ने बिना अगली तारीख दिए मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी है।

ठाकुर जी के विवाह के साक्षी बने देश-विदेश से आए श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, मथुरा : दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेदमंत्रों की ऋचाओं के बीच भगवान रंगनाथ और श्रीगोदाम्माजी का मंगलवार शाम वैदिक रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। ठाकुरजी के विवाह के विलक्षण पलों का साक्षी बनने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आए।

दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर में मंगलवार को अनोखी छटा दिखाई दी। भगवान रंगनाथ और श्रीगोदाम्माजी के विवाह की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थीं। परंपरा के अनुसार भोर में ही डोले में विराजमान कराकर श्रीगोदाम्माजी को यमुना दर्शन के लिए ले जाया गया। इसके बाद मंदिर की बारहद्वारी में विराजमान कराकर विवाह पूर्व की रस्में शुरू हुईं। दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे भगवान रंगनाथ गरुणजी पर विराजमान होकर निज मंदिर से बरात लेकर निकले और बारहद्वारी पहुंचे।

कराटे खिलाड़ियों ने टीसी को पीटा, ट्रेन से फेंकने का प्रयास

- दो खिलाड़ियों के बेटिकट होने पर हुआ विवाद, पीड़ित की सूचना पर नौ खिलाड़ियों को पकड़ा

नईदुनिया, बैतूल

यशवंतपुर से पाटलिपुत्र जा रही ट्रेन में मंगलवार को बिहार के कराटे खिलाड़ियों ने टीसी (टिकट कलेक्टर) से मारपीट की। उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का प्रयास किया। टीसी की सूचना पर मध्य प्रदेश के बैतूल में चार और इटारसी में पांच खिलाड़ियों को पकड़ लिया गया।

बिहार के 11 कराटे खिलाड़ी चेन्नई में संपन्न राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेकर दानापुर (बिहार) लौट रहे थे। वे यशवंतपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के एस-6 कोच में सवार थे। मंगलवार सुबह ट्रेन नागपुर पहुंची तो फ्लाइंग स्क्वॉड ने चेकिंग शुरू की। इसी में शामिल टीसी लोकेंद्र कौशिक एस-6 में पहुंचे तो 11 में से दो खिलाड़ी बेटिकट मिले। जुर्माने की रसीद बनाने पर विवाद हो गया। लोकेंद्र का आरोप है कि खिलाड़ियों ने उनसे मारपीट कर ट्रेन से बाहर फेंकने का प्रयास किया। उन्होंने खिड़की पकड़ ली और यात्रियों ने बचाया। उस समय ट्रेन आमला और बैतूल के बीच थी। टीसी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। मंगलवार दोपहर 1.29 पर ट्रेन बैतूल आते ही आरपीएफ-जीआरपी ने आरोपित शिवम पुत्र हजारीलाल ग्वाला, राहुल पुत्र सत्यानंद ग्वाला, रजनीश पुत्र मनोज यादव और बबलू पुत्र शिवनारायण यादव को पकड़ लिया। शेष खिलाड़ी ट्रेन में छिप गए। करीब 15 मिनट ट्रेन वहां खड़ी रही। टीसी का इलाज कराया गया। शाम करीब साढ़े चार बजे ट्रेन के इटारसी पहुंचते ही यहां पांच आरोपितों शिक्षा रौनक, मुन्ना कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार और अमरजीत कुमार को पकड़ा गया।

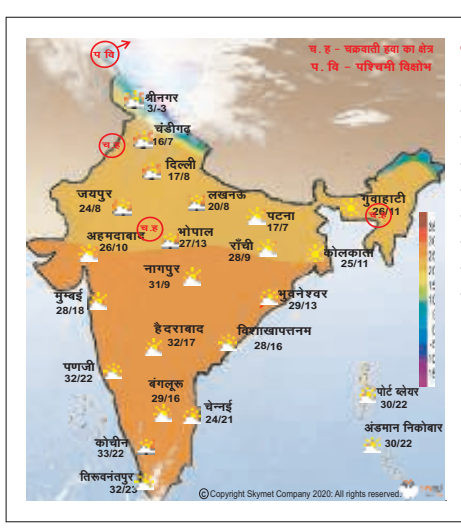

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा व बर्फबारी जारी रहेगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में ठंडी सुबह में मध्यम कोहरा व कुहासा रहेगा। दिन शीतल रहेगा। दोपहर से बादलों में वृद्धि होगी। रात के समय कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	27/17/व	अहमदाबाद	24/09/आंबा
कोलकाता	25/12/आंबा	बड़ौदा	26/12/सा
चेन्नई	29/18/आंबा	नागपुर	31/09/आंबा
हैदराबाद	32/17/आंबा	इन्दौर	27/16/व
बंगलूरू	30/16/आंबा	रांची	29/16/सा
त्रिवेन्द्रम	32/23/सा	पटना	28/15/व
गुवाहाटी	27/16/आंबा	जमशेदपुर	32/16/सा
गंगटोक	09/-5/आंबा	पुणे	30/18/आंबा

केएम करिअप्पा बने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ

आज ही के दिन 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद केएम करिअप्पा ने संभाला था। उन्हें फील्ड मार्शल की फाइव स्टार रैंक से सम्मानित किया गया। वे 1919 में सेना में शामिल हुए थे और उन्होंने 1947 में हुए भारत-पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था।

नरेंद्र हिरवानी ने अपने पहले ही मैच में झटके 16 विकेट

आज 1988 में स्पिनर नरेंद्र हिरवानी ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट झटके। चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच की दोनों पारियों में 8-8 विकेट लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बॉब मैसी का रिकॉर्ड तोड़ा था। रवि शास्त्री की कप्तानी में खेला गया यह एकमात्र टेस्ट था।

खशाबा जाधव ने जीता था ओलंपिक में पदक

आज ही के दिन 1926 में देश के लिए पहला एकल ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान खशाबा दादासाहेब जाधव का जन्म महाराष्ट्र के गांव गोलेश्वर में हुआ। उनके पिता भी पहलवान थे। 1948 में किसी तरह लंदन ओलंपिक में कुश्ती लड़ने पहुंचे और छठे स्थान पर रहे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 30 सालों तक महाराष्ट्र पुलिस में सेवाएं दीं। 14 अगस्त 1984 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ओलंपिक पदक जीतने वाले अकेले खिलाड़ी हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कार नहीं मिला है।

मेढक के स्टेम सेल से बने सजीव रोबोट

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल के जरिए पहली सजीव मशीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। इन सजीव रोबोट्स को 'जीनोबोट्स' का नाम दिया गया है। एक इंच के 25वें हिस्से के बराबर इन रोबोट्स को कैंसर कोशिकाओं के खात्मे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें समुद्र से माइक्रोप्लास्टिक एकत्रित करने के काम में लाया जा सकता है। यह शोध 'प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस' में प्रकाशित हुआ है। भविष्य में इन रोबोट्स के अन्य प्रभावी उपयोग सामने आ सकते हैं।

इस तरह आए अस्तित्व में

वैज्ञानिकों ने इन छोटे रोबोट्स को वेरमाउंट विश्वविद्यालय और टफ्ट्स विश्वविद्यालय में विकसित किया है। इसके लिए अफ्रीका के मेढक जीनोपस लेविस के भ्रूण से स्टेम सेल लिए गए।

अमेरिका ने मुहैया कराया धन

इस शोध को अमेरिका के डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के लाइफ लांग लर्निंग मशीन प्रोग्राम ने धन मुहैया कराया है। इसका उद्देश्य मशीनों में जैविक शिक्षा प्रक्रियाओं को फिर से बनाना है।

क्रम विकास एल्गोरिदम

रोबोट्स में क्रम विकास को एल्गोरिदम के जरिए सुपर कंप्यूटर में रन कराया जाता है। यह कार्यक्रम पांच सौ से एक हजार त्वचा और हृदय कोशिकाओं के क्रम रहित थ्रीडी कॉन्फिगरेशन के जरिए शुरू होता है। प्रत्येक डिजाइन को एक आभासी वातावरण के जरिए परीक्षण किया जाता है।

रोबोट लेकिन पारंपरिक नहीं

शोध से जुड़े वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यह न तो कोई पारंपरिक रोबोट है और न ही जंतुओं की कोई ज्ञात प्रजाति है। उनका दावा है कि यह नए 'कृत्रिम सेल' लक्ष्य के अनुसार किसी भी तरह की शक्ल ले सकते हैं। साथ ही यह खत्म नहीं होते और स्वयं की मरम्मत करने में भी सक्षम है। शोधकर्ता जोशुआ बोंगार्ड के मुताबिक, यह न पारंपरिक रोबोट है और न ही जंतुओं की कोई ज्ञात प्रजाति। यह मानव द्वारा निर्मित एक नई प्रजाति है, एक जीवित और प्रोग्राम योग्य जीव है।

ये है उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य इन रोबोट के निर्माण से कहीं अधिक चीजें हासिल करना है। इसका उद्देश्य जीवन के सॉफ्टवेयर को समझना है। यदि आप जन्म के दोष, कैंसर, उम्र से संबंधित बीमारियों के बारे में सोचते हैं, तो इन सभी चीजों को हल किया जा सकता है। यदि हमें यह पता है कि जैविक संरचना कैसे बनाई जाए, तो विकास और आकार पर अंतिम नियंत्रण हो जाता है।

खुद खत्म हो जाते हैं

यह जीनोबोट्स जब अपना काम पूरा कर लेते हैं तो सात दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और एक मृत कोशिका के रूप में रह जाते हैं।

मानवता को होंगे लाभ

इस बारे में शोध करने वालों का अनुमान है कि इससे मानवता को काफी लाभ होंगे। हालांकि वे यह भी स्वीकारते हैं कि इससे जुड़े कुछ नैतिक मसले भी सामने आ सकते हैं।

रोगों में कारगर

इन रोबोट की चौड़ाई एक इंच का 25वां भाग है। इस कारण से यह शरीर के किसी भी हिस्से में दवा पहुंचाने का काम भी बहुत ही सहजता से कर सकते हैं। जिस हिस्से में दवा की जरूरत है वहां पर सीधे दवा पहुंचा सकते हैं। इस तरह से यह कैंसर जैसी बीमारियों में कारगर हो सकते हैं।

पहले सजीव रोबोट का सफर

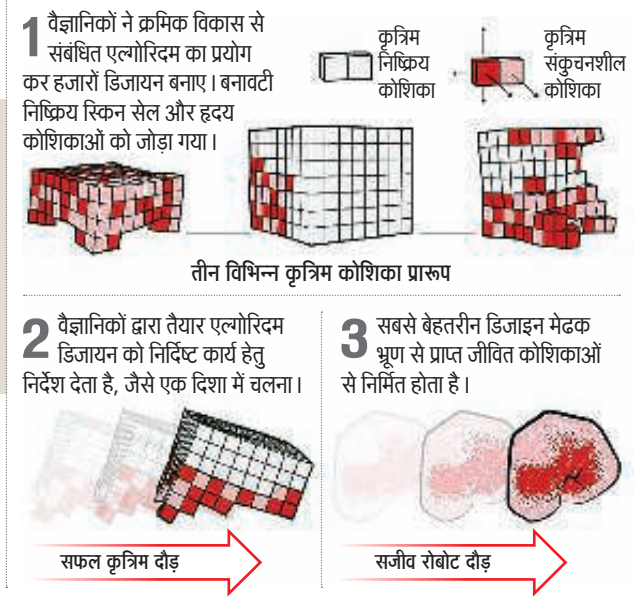

इधर-उधर की

हीरो को देख ऑनलाइन मंगाया स्वेटर, आई ऊन

लंदन, एजेंसी: हम अक्सर फिल्मों या सीरियलों में कलाकारों के कपड़ों को देखकर के खरीदारी करते हैं। हालांकि कभी-कभी ऑनलाइन खरीदारी परेशानी का सबब बन जाती है। डेन शिहान के साथ ऐसा ही हुआ। क्रिस ईवन की एक फिल्म देखकर नॉर्वे की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से स्वेटर ऑर्डर कर दिया। शिहान ने सस्ते के चक्कर में विदेशी वेबसाइट से ऑर्डर तो कर दिया लेकिन जब यह ऑर्डर घर आया तो वे दंग रह गए। उनके ऑर्डर में स्वेटर की जगह ऊन के कई गोले निकले। ऐसा शिहान ने कभी नहीं सोचा था। हालांकि बाद में अपनी गलती का अहसास हुआ, जिसमें उन्होंने स्वेटर की जगह ऊन का ऑर्डर दे दिया था। अब ऊन से स्वेटर बनाने के विशेष कौशल की आवश्यकता है और वह इसमें जीरो है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो डालकर के यह कहानी बताई है। जिसके बाद लोगों ने काफी मनोरंजक कमेंट किए हैं और इस पर अब तक करीब डेढ लाख लाइक्स आ गए हैं।

शोध अनुसंधान

अनियमित धड़कन का कारण बन सकती है थकान

भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकान या बर्नआउट महसूस कर रहे लोग सचेत हो जाएं। इस तरह की लंबी थकान दिल की सेहत के लिए भारी पड़ सकती है। एक अध्ययन में इस तरह की थकान का संबंध दिल की अनियमित धड़कन के खतरे से पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इस तरह की थकान को बर्नआउट कहा जाता है। यह एक सिंड्रोम है, जो तनाव के कारण हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह बर्नआउट डिप्रेशन से अलग होता है। यह निष्कर्ष करीब 11 हजार अधेड़ उम्र के लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इस दौरान थकान, गुस्सा, अवसाद रोधी दवाओं के उपयोग करने वाले लोगों पर नजर रखी गई। जिन प्रतिभागियों में ज्यादा बर्नआउट पाया गया, उनमें दिल की अनियमित धड़कन का खतरा 20 फीसद ज्यादा पाया गया। -प्रेट्र

पिछले साल सबसे गर्म रहे महासागर

चिंताजनक ▶ पृथ्वी की जलवायु के लिए विनाशकारी हो सकते हैं परिणाम

महासागरों के बढ़ते तापमान से ही कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के पैदा हो रहे हालात

यह अध्ययन 'एडवांसेज इन एटमॉस्फीयरिक साइंसेज' में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

बीजिंग, प्रेट्र : अब तक के मानव इतिहास में 2019 में दुनिया के महासागर, खासतौर पर सतह और दो हजार मीटर की गहराई के बीच सबसे ज्यादा गर्म रहे। वैज्ञानिकों ने मंगलवार को बताया कि मानवनिर्मित उत्सर्जन से बहुत ही तेजी के साथ गरम हो रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पैदा होने वाली उष्मा का 90 फीसद हिस्सा महासागर सोख लेते हैं। महासागरों का बढ़ता तापमान पृथ्वी के जलवायु के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है।

दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा चीन के वायुमंडलीय भौतिकी संस्थान (आइएपी) की तरफ से संकलित किए गए डाटा के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। 'एडवांसेज इन एटमॉस्फीयरिक साइंसेज' नाम के जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह भी पाया गया कि वैश्विक महासागरीय तापमान के लिहाज से बीते दस साल सबसे गर्म रहे और आखिरी पांच साल में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया।

228 अरब खरब जूल उष्मा की पड़ी जरूरत

: अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, 2019 में महासागर का तापमान 1981-2010 के औसत तापमान से 0.075 डिग्री सेल्सियस अधिक था। उन्होंने कहा कि इस तापमान तक पहुंचने के लिए महासागर को 228 अरब खरब जूल उष्मा की आवश्यता पड़ी होगी। जूल उष्मा की माप इकाई है। चीनी विज्ञान अकादमी (सीएएस) के एसोसिएट प्रोफेसर लीजिंग चेंग ने कहा, 'बीते 25 वर्षों में हमने दुनिया के महासागरों में उतनी उष्मा दी है जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम विस्फोट से निकली उष्मा से 3.6 अरब गुना है।' दुनिया भर के 11 संस्थानों के 14 वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय दल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पलटने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। नए आंकड़ों से अनुसंधानकर्ताओं को 1950 के दशक से महासागरों के तापमानों की प्रवृत्ति के अध्ययन में मदद मिलती है।

प्रभावित हो रहा है समुद्री जीवन : वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि महासागरों के गर्म होने के नतीजे हमारे सामने आने लगे हैं। इससे मौसम गरम हो रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। पेन के सरकारी अर्थ सिस्टम साइंस सेंटर के निदेशक माइकल मान ने कहा कि महासागरों ने 2018 की तुलना में 2019 में पृथ्वी से निकलने वाली अतिरिक्त 25 अरब खरब जूल उष्मा को सोख लिया। इस उष्मा को इस तरह से समझा जा सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति साल भर तक लगातार सौ हेयरड्रायर या सौ माइक्रोवेव चलाता है और उससे जो उष्मा निकली है, वह 25 अरब खरब जूल उष्मा के बराबर है।

तापमान में वृद्धि से बढ़ रही हैं आपदाओं की आवृत्ति : पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर काबू पाने के लिए ही साल 2015 में पेरिस समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत तापमान में बढ़ोत्तरी को दो डिग्री सेल्सियस से कम और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिकीकरण से पहले के समय की तुलना में अभी पृथ्वी के तापमान में सिर्फ एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और उसी के परिणामस्वरूप कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ और कहीं आंधी-तूफान तो कहीं जगलों में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हमें बढ़ते तापमान के खतरों से निपटना है तो समय रहते पेरिस समझौते के लक्ष्य को पाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। दुनिया भर के देशों को इसके लिए अपने-अपने लक्ष्य तक करने होंगे।

कैफी आजमी की 101वीं जयंती पर गूगल ने बनाया डूडल

स्पेक्ट्रम

कैफी आजमी। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : मशहूर शायर व गीतकार कैफी आजमी की 101वीं जयंती पर मंगलवार को गूगल ने उनकी याद में शानदार डूडल बनाया। खूबसूरत व रंगीन चित्र के जरिये गूगल ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आने वाले इस लेखक को श्रद्धांजलि दी।

1919 में पैदा हुए कैफी का असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था। पढ़ने लिखने के शौकीन कैफी ने पहली गजल महज 11 वर्ष की उम्र में लिखी थी। उर्दू भाषा के बेहतरीन नज्मकार कैफी का नाम फिल्म जगत के एक शानदार गीतकार के रूप में भी लिया जाता है। 1973 की फिल्म गर्म हवा की पटकथा, डायलॉग व गीतों के लेखन के लिए उन्हें तीन फिल्मफेयर अवार्ड एक साथ मिले थे। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में कैफी के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था।

लेखनी के अलावा कैफी को सामाजिक मुद्दों में भी गहरी अभिरूचि थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित कैफी की 1943 में झंकार नाम से पहली कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी। इसके बाद उन्हें सामाजिक सुधार के पैरोकार प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की सदस्यता भी मिली थी।

कैफी सिर्फ अपनी नज्मों तक ही सीमित नहीं थे बल्कि अपनी जिंदगी में भी काफी प्रगतिशील थे। वे अमीरी-गरीबी को मिटाने की बात तो करते ही थे साथ ही उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को एक समान दर्जा देने की भी वकालत की। उनके कुछ प्रमुख गीत- वक्त ने किया क्या हसीं सितम, मिलो न कि तुम हम घबराएं, मैं ये सोच के उसके दर से उठा था, जीत ही लेंगे बाजी हम-तुम, बहारों मेरा जीवन भी संवारो, धीरे-धीरे मचल ए दिले बेकरार आदि हैं। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजामी के पिता कैफी की मृत्यु 10 मई, 2002 को हो हुई थी।

फिलीपींस में ज्वालामुखी की राख में लिपट गई घर और गलियां

दक्षिणी फिलीपींस के बातांगस प्रांत में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से सब कुछ राख में लिपट गया है। इस विस्फोट में इतनी राख निकली है कि कई घर दबकर टूट गए हैं। ताल ज्वालामुखी से निकल रहे लावे की ऊंचाई आधा मील तो राख हवा में नौ मील तक उड़ रही है। इलाके में रह रहे हजारों ग्रामीण घर छोड़कर पलायन करने लगे हैं। ज्वालामुखी की 17 किलोमीटर की परिधि में करीब 920000 हजार लोग रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन लोगों के जीवन को गंभीर खतरा है। प्रशासन की ओर से अब तक लगभग 25000 हजार से अधिक लोगों को अस्थाई शिविरों में भेजा जा जा चुका है। लोगों के राहत और बचाव के लिए फिलीपींस की सेना ने अपने 120 जवान और 20 गाड़ियां भेजी हैं। एपी

ब्राजील ने अंटार्कटिका में खोला होटल की तरह भव्य शोध स्टेशन

ब्राजील ने मंगलवार को अंटार्कटिका में अपने नए वैज्ञानिक शोध आउटपोस्ट 'कमांडेंटे फेराज अंटार्कटिका' का उद्घाटन किया। यह आठ साल पहले आग लगने से तबाह हो गए आउटपोस्ट से आकार में दोगुना है। इसके निर्माण पर करीब 100 मिलियन डॉलर (करीब आठ अरब रुपये) का खर्च आया है। 64 शोधकर्ताओं की क्षमता वाले इस स्टेशन में किसी होटल की तरह लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि साल 2012 में ईंधन ट्रांसफर करने के दौरान आग लगने से दो नौसैनिकों की मौत हो गई थी और स्टेशन भी तबाह हो गया था। इस घटना के एक साल बाद नए स्टेशन को मंजूरी मिली थी। किंग जॉर्ज द्वीप पर स्थित कमांडेंटे फेराज अंटार्कटिका स्टेशन। फाइल/एएफपी

स्क्रीन शॉट

रोहित शेट्टी करेंगे वेब शो का निर्देशन

बीते साल 'सुपर 30', 'सांड की आंख', 'कमांडो 3' जैसी फिल्मों का निर्माण करने वाला रिलायंस एंटरटेनमेंट इस साल रोहित शेट्टी निर्देशित 'सूर्यवंशी', कबीर खान निर्देशित '83', परिणीति चोपड़ा अभिनीत 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' समेत कई फिल्में लेकर आ रहा है। साथ ही वह करीब दर्जन भर वेब शो के निर्माण में लगा है। इनमें एक शो रोहित शेट्टी भी निर्देशित कर रहे हैं। उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। यह शो सत्य घटनाओं से प्रेरित होगा और एक्शन स्पेस में होगा। इस शो को अमेजन के लिए बनाया जा रहा है। वहीं, फिल्ममेकर विक्रमादित्य मोटवाणी 'स्टारडस्ट' नामक शो बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग अप्रैल से आरंभ होगी। वह पिछले दो साल से इस पर काम कर रहे हैं। यह शो गुरुदत्त के समय से लेकर वर्तमान की फिल्म इंड्रस्टी को दर्शाएगा। यह फिक्शनल शो होगा, लेकिन दर्शक उसे देखकर समझ जाएंगे कि किस किरदार की बात हो रही है। उसका विषय रोचक है। 'स्त्री' फेम निर्देशक अमर कौशिक 'विषपुरी' बना रहे हैं। यह शो एक किताब पर आधारित है। मिलन लूथरिया, मृगदीप लांबा जैसे दिग्गज निर्देशक भी वेब शो का निर्माण कर रहे हैं।

विक्रांत मेस्सी ने बताई बचपन की बेवकूफी

फिल्म 'छपाक' में दीपिका पादुकोण के साथ विक्रांत मेस्सी के अभिनय की काफी सराहना हो रही है। मकर संक्रांति पर अपनी पतंगबाजी की यादें साझा करते हुए विक्रांत बताते हैं, 'मैंने बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर खूब पतंगें उड़ाई हैं। मैंने कई बार दूसरों की पतंग काटी हैं। हम लोग तार वाला मांझा इस्तेमाल करते थे, जिससे पतंग उड़ाने के चक्कर में हमारी उंगलियां भी कट जाती थीं। इससे बचने के लिए हम उंगलियों में सेलो टेप या बैंडेज बांधकर पतंग उड़ाते थे। मुंबई में हम एक छह मंजिला बिल्डिंग में रहते थे। हम बिल्डिंग की छत पर पतंग उड़ाते थे। एक बार मेरी पतंग छत से नीचे वाले घर की बालकनी के ग्रिल में फंस गई थी। उसे छुड़ाने के लिए मैं छत से बिना किसी सहारे के छज्जों से होते हुए छठे मंजिल की बालकनी पर उतर गया। दो फीट के छज्जे पर पैरों के जरा-सा भी इधर-उधर हिलने पर, मैं छठवीं मंजिल से सीधा नीचे गिर सकता था। जब भी मैं उस वक्त को याद करता हूं, तो मुझे यह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है।' इन दिनों विक्रांत अपनी आगामी फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी' की तैयारी में व्यस्त हैं। विक्रांत के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्होंने डांस प्रशिक्षण लिया है और एक बार फिर से डांस करना शुरू कर दिया है। विक्रांत अच्छे डांसर हैं। इससे पहले वह कुछ रियलिटी शो में अपनी डांस की कला को प्रदर्शित कर चुके हैं। 'गिन्नी वेड्स सनी' के अलावा इस साल विक्रांत की एक और फिल्म 'हसीन दिलरुबा' भी रिलीज होगी।

सलमान के हाथों में बेटी को सुरक्षित मानती हैं बहन अर्पिता खान

सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने मंगलवार को भाई सलमान और उनकी मां सलमा के साथ अपनी नवजात बेटी आयत की एक प्यारी तस्वीर साझा की है। साथ ही अर्पिता ने लिखा, 'इस दुनिया में मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि आप मेरे साथ हैं और आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब आयत को भी इन्हीं हाथों का आशीर्वाद मिला हैं। मुझे प्यार देने के लिए सलमान भाई और मां सलमा को शुक्रिया।' पिछले साल 27 दिसंबर को अर्पिता ने आयत को जन्म दिया था।

एम.एस. बिट्टा अपने किरदार में देखना चाहते हैं अजय देवगन को!

बायोपिक्स की फेहरिस्त में अब ऑल इंडिया एंटी-टेररिस्ट फ्रंट के मुखिया मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का नाम भी शुमार हो गया है। कई बार बम धमाकों से बचे एम.एस. बिट्टा का जीवन प्रेरणात्मक रहा है। सिल्वर स्क्रीन पर अपने अवतार में किसे देखना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मेरा किरदार कौन निभाएगा, यह फैसला तो फिल्ममेकर्स लेंगे, लेकिन अजय देवगन मुझे बेहतरीन लगते हैं। जब मैं उन्हें 'द लेजेंड ऑफ भगत सिंह' में देखता हूं तो उनमें मुझे वही शहीद-ए-आजम नजर आता है। उनकी गंभीरता नजर आती है। मेरी फिल्म में आंखों में आंसू होंगे, जज्बात होंगे, वंदे मातरम होगा। जब लोग मुझसे मेरा धर्म पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरा धर्म भारत मां, मेरी जाति वंदे मातरम है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आखिरी वक्त पर यही शब्द कह पाऊं।' एम.एस बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 'जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसके लिए मेरा जीवन हाजिर है।' फिल्म की कहानी गिरीश कोहली लिख रहे हैं।

तकनीक

प्लास्टिक के जरिये बनाया 18 कैरेट का सोना

स्विस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मैट्रिक्स से तैयार की कीमती धातु, प्रोटीन फाइबर और टेलेक्स पॉलीमर के साथ सोने के नैनोक्रिस्टल का किया इस्तेमाल

- **पारंपरिक सोने के मुकाबले इसका वजन छह गुना है कम**
- **एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन**
- **अल्कोहल जेल और कार्बन डाइऑक्साइड से इसे दिया जा सकता है मनचाहा आकार**

प्लास्टिक के भौतिक गुणों से लैस है यह सोना। फाइल

लंदन, आइएएनएस: आभूषण प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उनकी पसंद की सोने की वस्तुएं बहुत हल्की हो सकती हैं वह भी बिना अपनी चमक खोए। दुनिया में पहली बार स्विस वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की मदद से 18 कैरेट का सोना तैयार किया है। इसके साथ ही यह वजन में काफी हल्का भी है। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के मैट्रिक्स का इस्तेमाल मिश्रित धातु की जगह करके सोने को बनाया है। स्विस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सोने का एक नया रूप विकसित किया है। जिसका वजन पारंपरिक 18 कैरेट सोने से लगभग पांच से छह गुना कम है।

एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल जर्नल में प्रकाशित हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि पारंपरिक मिश्रण में आमतौर पर तीन चौथाई सोना और एक चौथाई तांबा होता है। इसका घनत्व 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। शोधकर्ताओं लियोनी वैंट हैग, राफेल मेजेंगा और इनकी टीम ने मैट्रिक्स बनाने के लिए प्रोटीन फाइबर और टेलेक्स पॉलीमर का प्रयोग किया। उन्होंने इसी मैट्रिक्स में सोने के नैनोक्रिस्टल की पतली डिस्क को लगाया।

ऐसे तैयार किया सोना : शोधकर्ताओं के अनुसार, सोने के प्लेटलेट्स और प्लास्टिक एक ऐसे पदार्थ में पिघल जाते हैं, जिसे आसानी से यांत्रिक रूप से परिष्कृत किया जा सकता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने पहले सामग्रियों को पानी में मिलाया और फिर इसका घोल तैयार किया। इस घोल को जेल में बदलने के लिए इसमें नमक मिलाया गया। इसके बाद उन्होंने पानी की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया। फिर उन्होंने अल्कोहल जेल को उच्च दबाव वाले चेंबर में रखा। उच्च दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक-दूसरे में मिला देता है। जब दबाव छोड़ा जाता है, तो सब कुछ एरोजेल जैसे गैसोमर में बदल जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के पॉलीमर को हटाने के लिए ताप यानी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह सामग्री का स्वरूप बदला जाता है और उसे मनोवांछित आकार दिया जाता है।

गिरने पर प्लास्टिक की तरह करता है आवाज : अध्ययन के अनुसार, इस सोने में प्लास्टिक के भौतिक गुण होते हैं। अगर इसका कोई टुकड़ा किसी सख्त सतह पर गिरता है, तो यह प्लास्टिक की तरह आवाज करता है। हालांकि, यह सोने की तरह चमकता है और इसे पॉलिश भी किया जा सकता है।